चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 21 मई–27 मई 2012 | मूल्य 5 रुपये

यह एक छलावा है

पेज-3

कांग्रेस गांधी की गुनहगार है

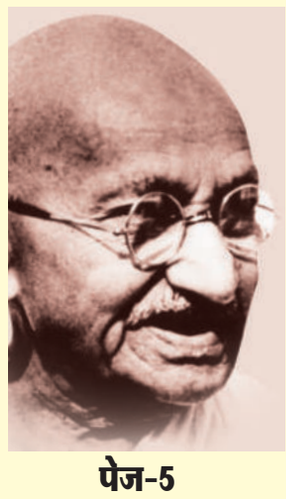

पेज-5

राष्ट्र धर्म पर चिंतन करें

पेज-7

इस सच को कहने की हिम्मत कौन करेगा?

पेज-9

मुंबई

पुनर्विकास के बहाने

महाराष्ट्र सरकार आराम नगर को बेचना चाहती है

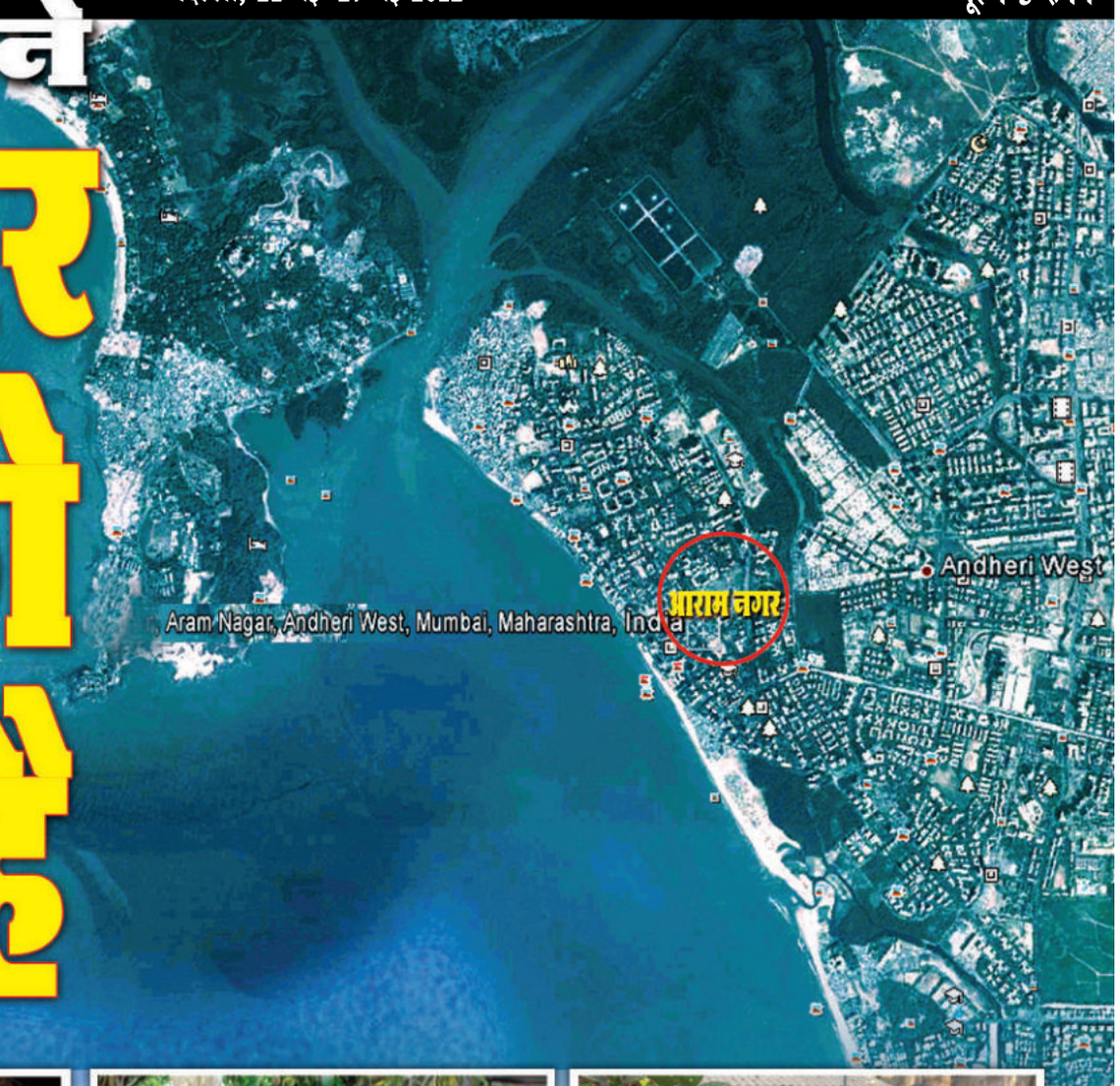

शशि शेखर

कहते हैं मुंबई में खाने को मिल जाता है, रहने की जगह आसानी से नहीं मिलती. ऐसे में अगर किसी मुंबईवासी को अपना 65 साल पुराना घर छोड़ने के लिए सरकार मजबूर करे तो इसे क्या कहेंगे? सरकार घर तोड़ने की धमकी दे तो किसी पर क्या बीतती होगी? यह सब कुछ इसलिए, ताकि हज़ारों करोड़ की ज़मीन एक बिल्डर को दी जा सके और उस हरी-भरी ज़मीन पर कंक्रीट का जंगल पैदा किया जा सके तथा उससे अरबों रुपये की कमाई हो सके. कुछ यही कहानी है मुंबई के वर्सोवा बीच (समुद्र) से ठीक 50 मीटर दूर स्थित आराम नगर इलाक़े की. एक ऐसा ऐतिहासिक इलाक़ा, जिसे संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन नेता, ब्यूरोक्रेट्स और बिल्डर मिलकर उसे तबाह करने की साज़िश रच रहे हैं.

आराम नगर का मकान नंबर 21/1. इसमें नवीन वैगनकर और इनकी बहन कुंदा वैगनकर रहते हैं. 1947 में इनके पिता करांची से मुंबई आए. साराभाई कंपनी में नौकरी मिली और कंपनी की ही सिफारिश से आराम नगर की इस बैरक में रहने को एक छोटा सा घर मिला. बचपन से जवानी तक और अब बुढ़ापा इसी इलाक़े , इसी घर में बीत रहा है, लेकिन अब इनके आशियाने को किसी की नज़र लग गई है. इसी तरह ललिता पाटंकर के पिता मधुकर सदाशिव पाटंकर स्वतंत्रता सेनानी थे. 1946 में मोरारजी भाई देसाई के भाई सी आर देसाई की सिफारिश पर इन्हें आराम नगर की बैरक में मकान नंबर 50 रहने को मिला, लेकिन अब ललिता पाटंकर के सिर से कभी भी छत ग़ायब हो सकती है. इसी तरह सत्यानंद राव, जयंती लाल सोमैय्या, हरिहरण, नसरीन शेख, नरेंद्र जेठवानी, दीपक सरीन, प्रकाश पारकर एवं संजीव बत्रा जैसे सैकड़ों ऐसे परिवार हैं, जो पचासों साल से आराम नगर में रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें इनके घर से बेदख़ल करने की साज़िश रची जा रही है. वजह, कुछ लालची लोगों की निगाह इस इलाक़े की बेशक़ीमती ज़मीन पर पड़ चुकी है.

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) की नज़र में अब यह इलाक़ा स्लम बन चुका है और इसलिए इस इलाक़े के पुनर्विकास की ज़रूरत है. जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है. समुद्र के किनारे बसा आराम नगर मुंबई का शायद सबसे ख़ूबसूरत और हरा-भरा इलाक़ा है, लेकिन म्हाडा 17 हेक्टेयर में फैली इस ऐतिहसिक जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट करना चाहता है. म्हाडा ऐसा इसलिए करना चाहता है, ताकि अरबों की इस ज़मीन से एक खास बिल्डर को फ़ायदा पहुंचे. यहां की ज़मीन की क़ीमत अरबों रुपये है. ज़ाहिर है, बिल्डर, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की नज़र से आख़िर कब तक यह इलाक़ा बचता. नतीजतन, आज आराम नगर के पुनर्विकास के नाम पर यहां के निवासियों को कभी इनके घर ढहाने की नोटिस भेजी जा रही है तो कभी इन्हें लालच दिया जा रहा है. बिल्डर ग़लत ढंग से और फर्जी कंसेट लेटर्स (जिनके मकान हैं उनके नाम के) तैयार कराकर म्हाडा के सामने पेश कर रहा है. चौथी दुनिया के पास वे तमाम दस्तावेज़ उपलब्ध हैं, जो यह साबित करते हैं कि कैसे आराम नगर टिनेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने पाले में लाकर बिल्डर ने फर्जी कंसेंट लेटर तैयार कराया. एक और अहम सवाल, आरएनए को ही क्यों प्रोजेक्ट मिला, वह भी बिना टेंडर निकाले. सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ से परे है कि आख़िर आरएनए बिल्डर्स में ऐसी क्या ख़ूबी थी, जो म्हाडा ने बिना किसी निविदा के यह प्रोजेक्ट उसे दे दिया. क्यों नहीं दूसरे बिल्डरों को भी आमंत्रित किया गया. ज़ाहिर है, म्हाडा का यह क़दम अपने आप में संदेह पैदा करता है.

बहरहाल, आरएनए बिल्डर्स और म्हाडा ने मिलकर आराम नगर टिनेंट एसोसिएशन के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिलाकर एक त्रिपक्षीय समझौता कर लिया, जिसके तहत ग़लत ढंग से कंसेंट लेटर्स भी बनाए गए और लोगों को लालच भी देने की कोशिश की गई. जब ज़्यादातर लोगों ने एसोसिएशन के इस क़दम का विरोध करना शुरू किया और एक बैठक में एसोसिएशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी में विश्वास न होने का प्रस्ताव पारित कर दिया यानी 2 सितंबर, 2009 को हुए ज्वाइंट री-डेवलपमेंट एग्रीमेंट को मानने से इंकार कर दिया. इससे पहले भी आराम नगर के लोगों ने म्हाडा को सूचित किया था कि वे पुनर्विकास की इस योजना से सहमत नहीं हैं और चूंकि बिल्डर को यह पता था कि फर्जी कंसेंट लेटर्स के सहारे वह यह केस अदालत से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने एक नई चाल चली. म्हाडा और बृहन मुंबई महानगर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सत्यानंद राव
(मकान नंबर-10)

मेरी फैमिली 1946 से यहां रह रही है. सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था. बाद में हमने एक टॉयलेट बना लिया, जिसे अब म्हाडा अनॉथराइज्ड बताकर घर तोड़ने की नोटिस दे रही है.

प्रकाश पारकर
(मकान नंबर-7)

मेरे पास 1987 का गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन भी है, जिसमें हमें ओनरशिप देने की बात है. फिर क्यों उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है.

कुंदा वैगनकर
(मकान नंबर-21/11)

झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी मालिकाना हक़ मिल जाता है. हम तो इतने पुराने हैं. इतने सालों से रह रहे हैं तो हमें मालिकाना हक़ क्यों नहीं मिल सकता है?

नसरीन शेख

गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के तहत मुंबई की 18 कॉलोनियों के लोगों को ओनरशिप मिल गई है, सिर्फ़ आराम नगर के लोगों को ही ओनरशिप नहीं मिली है, आख़िर क्यों?

जयंती लाल सोम्मैया
(मकान नंबर-12)

हम बांबे में 1950 में पाकिस्तान से आए. हमें कमरा नंबर 12 मिला. हमने अपनी सुरक्षा के लिए घर के आगे चाहरदीवारी बना ली तो उसे ग़ैर क़ानूनी बताकर हमें नोटिस दिया जा रहा है.

क्या कहते हैं दस्तावेज़

आराम नगर के इन 357 घरों में 65 साल पहले शरणार्थी आए थे. अब इसमें उनके पोते-बेटे रहते हैं. कुछेक घर बाद में दूसरे लोगों ने भी ख़रीद लिए. अब सवाल है कि क्या उन लोगों को, जिनके पिता या दादा को 65 साल पहले भारत या कहें कि महाराष्ट्र सरकार ने बसाया था, फिर से अपने ही देश में शरणार्थी बनाने की मंशा है, उन्हें उनके ही घर से बेदख़ल कर या उनके घरों को तोड़कर और ज़मीन को प्राइवेट बिल्डरों के हाथों बेचकर? एक नज़र दौड़ाते हैं उन सरकारी दस्तावेज़ों पर, जो यह साबित करते हैं कि इन घरों के मालिक कौन हैं.

मासिक किराये की रसीद : जिन लोगों को (शरणार्थी और स्वतंत्रता सेनानी) ये घर आवंटित हुए थे, वे लगातार अपना मासिक किराया देते रहे हैं और अब भी दे रहे हैं. शुरू में और अब भी म्हाडा या नगर निगम की ओर से इस इलाक़े पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया. यहां के लोग ख़ुद मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करते रहे हैं.

गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1987 : 1987 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक रिजोल्यूशन जारी करके यहां के टिनेंट (किरायेदार) को ओनरशिप (मालिकाना हक़) देने की बात कही थी.

बांबे हाउसिंग बोर्ड, 1955 का पत्र: आराम नगर के हाउस नंबर 50 में रहने वाली ललिता पाटंकर के पिता मधुकर सदाशिव पाटंकर के नाम एक पत्र 29 जून ,1955 को बांबे हाउसिंग बोर्ड ने लिखा था, जिसमें कहा गया था कि आप ज़मीन का इस्तेमाल बगीचे के तौर पर कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रति सौ वर्ग फीट के लिए 1 रुपया की दर से अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा. ■

कंसेंट लेटर और आरएनए का झूठ

महाराष्ट्र सरकार के नियम के मुताबिक़, किसी भी एरिया के पुनर्विकास के लिए यह ज़रूरी है कि वहां रहने वाले 70 फ़ीसदी परिवारों की सहमति हो. आराम नगर के पुनर्विकास की योजना म्हाडा ने बना ली और यह प्रोजेक्ट भी आरएनए (जिसका नाम अब ईस्ट एंड वेस्ट हो गया है) नामक एक प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया, वह भी बिना कोई निविदा निकाले. बहरहाल, इसके बाद आरएनए ने सहमति पत्र हासिल करने के लिए एक साजिश रची. चूंकि आरएनए को पता था कि आराम नगर के लोग सहमति पत्र नहीं देने वाले हैं, इसलिए उसने सबसे पहले आराम नगर टिनेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अपने साथ करने की कोशिश की और एक-एक करके फर्जी सहमति पत्र बनाने का काम शुरू हो गया. बाकायदा 70 फ़ीसदी से ज़्यादा कंसेंट लेटर्स बनाकर म्हाडा के पास जमा भी करा दिया गया. यह बात तब सामने आई, जब आराम नगर के लोगों ने आरटीआई क़ानून के तहत म्हाडा से उन सभी कंसेट लेटर्स की कॉपी हासिल की. जब उन लेटर्स का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि महज़ 29 फ़ीसदी कंसेंट लेटर्स ही सही हैं, बाक़ी फर्जी हैं. बानगी के तौर पर, बी के मोम्मैया (कमरा नंबर-14) के कंसेंट लेटर में न तो कोई फोटो है और न हस्ताक्षर. देविंदर सिंह कोचर को कमरा नंबर 31 का टिनेंट बताया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि इस जगह पर एक गुरुद्वारा है. दिलचस्प रूप से यही देविंदर सिंह कोचर कमरा नंबर 32 के मालिक के तौर पर भी अपना कंसेंट लेटर दे देते हैं. एक ही मकान नंबर 97 के लिए दो लोगों (ओनर) कैलाश गुप्ता एवं अशोक गुप्ता के नाम से सहमति पत्र बना लिया जाता है. जो कुछेक कंसेंट लेटर्स सही भी हैं, उनमें से कई में मकान मालिकों ने बिल्डर्स के नाम पर सख्त ऐतराज दर्ज कराया है. ■

सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र से आने की बात तो दूर, राज्य के कम से कम तीन आईएएस अधिकारी केंद्र में जाने का अनुरोध कर रहे हैं.

दिल्ली का बाबू

उत्तर प्रदेश के बाबुओं की चिंता

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी भी उनके प्रशासन में कई लोगों, जिनमें मुलायम सिंह भी शामिल हैं, का हस्तक्षेप है. इस कारण वह कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं. बाबुओं का स्थानांतरण किया गया, लेकिन उससे प्रशासन के सफल संचालन में परेशानी हो रही है. कुछ स्थानों पर तो अखिलेश यादव यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कहां रखा जाए. अब संजय अग्रवाल को ही देख लीजिए. उनका नाम मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के लिए सामने आया था, लेकिन एक दिन बाद ही रद्द हो गया. इसी तरह एक आईपीएस अधिकारी जावेद अख्तर को एक सप्ताह के अंदर तीन अलग-अलग जगहों पर नियुक्त किए जाने की बात की गई. पहले उनका नाम स्टेट प्रोविंसियल आर्म्ड कांउटेबुलरी के आईजी पद के लिए सामने आया, उसके बाद गोरखपुर का आईजी बनाए जाने की बात हुई और बाद में आगरा का आईजी बनाने की. इस तरह के आदेशों से बाबुओं की परेशानी बढ़ गई है. अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि किन बाबुओं को कहां भेजा जाए या फिर उनके फ़ैसले को कोई प्रभावित कर रहा है. लेकिन जो भी हो, इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में परेशानी हो रही है.

दिल्ली से बाहर गए कई बाबू

कुछ समय पहले जब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बाबुओं का स्थानांतरण किया था तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसका विरोध किया था, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही मुख्यमंत्री का तेवर बदल गया. इस बार जब कम से कम 39 आईएएस और कुछ यूटी कैडर के अधिकारियों की बदली की गई तो शीला दीक्षित चुप रहीं. सूत्रों का कहना है कि राजस्व विभाग पर इसकी गाज सबसे अधिक गिरी. उसके नौ में से सात उपायुक्तों को दिल्ली से बाहर भेज दिया गया है. बाहर भेजे गए अधिकारियों में आर के मिश्रा, जी एस मीणा, डी पी द्विवेदी एवं आकाश महापात्र के नाम शामिल हैं. ऊर्जा सचिव परिमल राय और स्वास्थ्य सचिव जयदेव सारंगी का स्थानांतरण गोवा कर दिया गया, जबकि अन्य कुछ अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया.

हिमाचल में बाबुओं की कमी

दिलीप चेरियन

हिमाचल प्रदेश बाबुओं की कमी की समस्या से जूझ रहा है. हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी, जो केंद्र में डेपुटेशन पर हैं, वापस आने में शिथिलता दिखा रहे हैं. राज्य सरकार इस समस्या से काफी परेशान है. राज्य की मुख्य सचिव सुद्रीप्ता राय ने हिमाचल कैडर के बाबुओं से राज्य में आकर काम करने का अनुरोध किया है. सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि राज्य में आईएएस कैडर की संख्या बढ़ाई जाए. राज्य सरकार इसकी संख्या 129 से बढ़ाकर 139 करना चाहती है, लेकिन इसमें तो समय लग जाएगा. अभी तो राज्य सरकार केंद्र में डेपुटेशन पर गए अधिकारियों से कह रही है कि वे अपना काम ख़त्म करके राज्य लौट आएं. सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र से आने की बात तो दूर, राज्य के कम से कम तीन आईएएस अधिकारी केंद्र में जाने का अनुरोध कर रहे हैं. अब देखना यह है कि राज्य सरकार किस तरह बाबुओं की कमी की समस्या से बाहर निकल पाती है.

dilipcherian@gmail..com

महाराष्ट्र सरकार आराम नगर को बेचना चाहती है

पृष्ठ एक का शेष

पालिका से साठगांठ करके 351 डिमोलिशन नोटिस जारी कराई गईं, ताकि मकान मालिकों पर दबाव बनाया जा सके, उन्हें डराया जा सके और वे डरकर असली कंसेंट लेटर दे दें. इस नोटिस का सबसे मजेदार तथ्य यह है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इसे बिना किसी होमवर्क के तैयार किया है. किसी मकान के ग्राउंड फ्लोर को इलीगल और सेकेंड फ्लोर को लीगल बताया गया है और यह नोटिस तब जारी की गई है, जब यह मामला अदालत में विचाराधीन है.

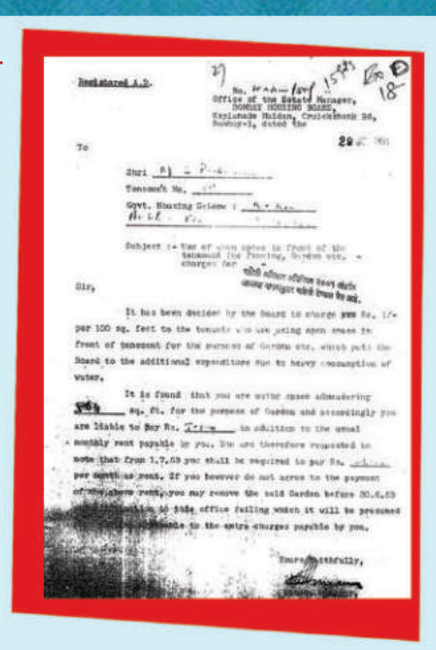

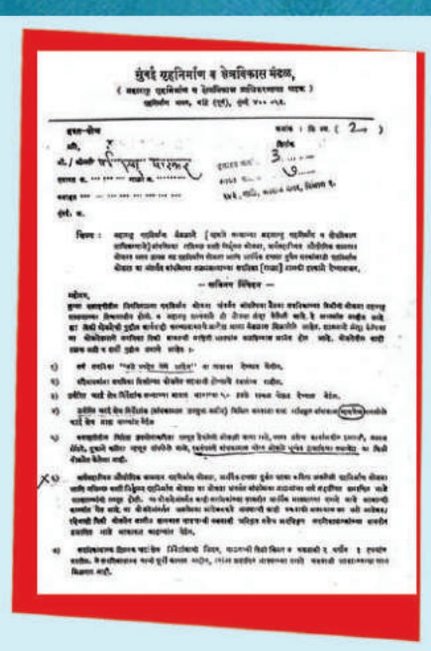

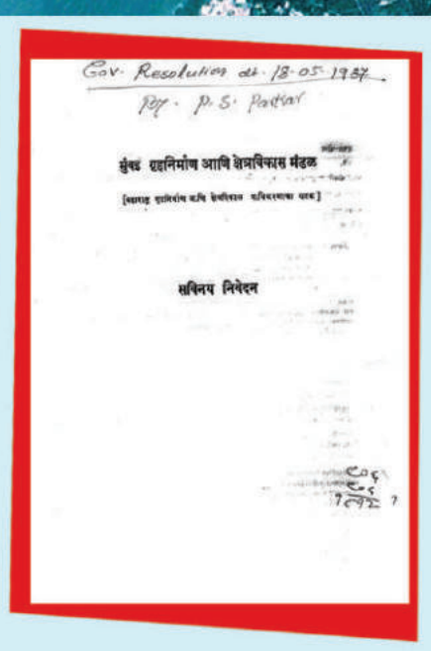

इसके अलावा इस पुनर्विकास योजना से स्थानीय प्राकृतिक संतुलन को भी ख़तरा है, लेकिन इस सवाल पर किसी भी सरकारी एजेंसी ने सोचने की ज़हमत नहीं उठाई. आराम नगर का यह इलाक़ा कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) में आता है, कोस्टल लाइन से महज 60 मीटर दूर है. सीआरजेड के मुताबिक़, कोस्टल लाइन के 100 मीटर के भीतर के प्लॉट पर डेवलपमेंट वर्क नहीं किया जा सकता है. 17.5 हेक्टेयर के इस प्लॉट के पुनर्विकास के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस की भी ज़रूरत होगी. इस इलाक़े की ज़मीन चूंकि समुद्र के किनारे है, इतनी कमज़ोर है कि इस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना ख़तरे को आमंत्रित करने जैसा है. इसी इलाक़े में कुछ समय पहले नाबार्ड की एक सात मंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी, जो काम में आने से पहले ही ढह गई. ऐसे में अगर यहां पचास मंजिला इमारत बनाई जाएगी तो उसका क्या हाल होगा.

बहरहाल, इस मामले को लेकर आराम नगर के निवासियों ने अदालत और लोकायुक्त का दरवाजा भी खटखटाया है. लोकायुक्त के यहां से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया है. जहां तक अदालत का सवाल है तो इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने इनकी याचिका संख्या 2086/2010 खारिज कर दी थी. इसके बाद फिर से इन लोगों ने तमाम दस्तावेज़ जुटाकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है. आराम नगर टिनेंट एसोसिएशन से अलग यहां के लोगों ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर याचिका संख्या 2086/2010 में 7 अक्टूबर, 2010 को जारी आदेश का रिव्यू करने की प्रार्थना की गई है. याचिका के साथ तमाम काग़ज़ी सबूत भी दिए गए हैं. मसलन फर्जी कंसेंट लेटर्स, एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस न होने की बात, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन की कॉपी, आराम नगर टिनेंट एसोसिएशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी का एकतरफा निर्णय. पुनर्विचार याचिका के ग्राउंड के तौर पर बताया गया है कि म्हाडा एक्ट 1976 के तहत यह री-डेवलपमेंट अनॉथराइज्ड है, क्योंकि म्हाडा इस तरह के एग्रीमेंट, जिसमें वह स्वयं एक पक्ष हो, नहीं कर सकता और बिना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के ऐसा टेंडर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है. टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं. साथ ही डीसी (डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स) रूल 1991 की धारा 33(5) के तहत 2004 के कंसेंट लेटर्स मान्य नहीं हो सकते. नए कंसेंट लेटर्स लिए जाने की ज़रूरत है. साथ ही बांबे ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 35 (जिसके तहत आराम नगर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है) के तहत एसोसिएशन को इस समझौते के लिए पहले से स्वीकृति लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई. इस तरह कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ स्थानीय लोगों ने बांबे हाईकोर्ट से आराम नगर को बचाने की गुहार लगाई है.

याचिका में म्हाडा, आरएनए और एसोसिएशन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन को फ़िलहाल रोकने की मांग की गई है. डिमोलिशन नोटिस रद्द किए जाने की बात भी याचिका में की गई है. फ़िलहाल, मामला अदालत में विचाराधीन है. कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, इसका इंतज़ार आराम नगर के लोग बेसब्री से कर रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार की नीति और नीयत पर भी खड़ा होता है, क्योंकि उदारीकरण के इस दौर में सबसे क़ीमती संसाधन ज़मीन है और यह सीमित है, इसलिए इस पर क़ब्ज़ा करने के लिए छल-प्रपंच, साम-दाम-दंड-भेद यानी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. आराम नगर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी और शरणार्थियों के आने और उनके बसने की कहानी को समेटे हुए है. क्या महाराष्ट्र सरकार आराम नगर को बचाएगी या फिर एक प्रॉपर्टी डीलर बन बिल्डरों के हाथ का खिलौना बनकर रह जाएगी? यह सवाल सिर्फ़ आराम नगर का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का है, पूरे मुल्क का है. ■

कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, इसका इंतज़ार आराम नगर के लोग बेसब्री से कर रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र सरकार की नीति और नीयत पर भी खड़ा होता है, क्योंकि उदारीकरण के इस दौर में सबसे क़ीमती संसाधन ज़मीन है और यह सीमित है, इसलिए इस पर क़ब्ज़ा करने के लिए छल-प्रपंच, साम-दाम-दंड-भेद यानी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

ऐतिहासिक है आराम नगर

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुंबई के आराम नगर में सैनिकों के लिए बैरकें बनाई गई थीं. लगभग 17 हेक्टेयर में फैला, हरियाली और समुद्र के किनारे बसा यह इलाक़ा मुंबई की भीड़भाड़ के बीच सुकून और राहत प्रदान करता है. दो भागों यानी आराम नगर-1 और आराम नगर-2 में क़रीब 357 छोटे-छोटे घर हैं. पहले यह बैरक केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी के अधीन थी. बाद में इसे महाराष्ट्र सरकार (म्हाडा-महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) को दे दिया गया. 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान से काफी संख्या में शरणार्थी मुंबई पहुंचे. सरकार ने इन बैरकों में शरणार्थियों और स्वतंत्रता सेनानियों को रहने के लिए जगह दे दी. मासिक किराए के आधार पर उन्हें एक-एक घर आवंटित कर दिया गया. यहां पर रह रहे ज़्यादातर लोगों के पिता या दादा पाकिस्तान से आए थे. मुंबई के वर्सोवा बीच से क़रीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित आराम नगर एक मायने में भारतीय इतिहास के कई अहम पन्नों को ख़ुद में समेटे हुए है. द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी और शरणार्थियों के दर्द को समेटे आराम नगर का अस्तित्व अब ख़तरे में है. इस पर लालची बिल्डरों और नेताओं की नज़र पड़ चुकी है.

साउथ ब्लॉक

राहुल खुल्लर का इंकार

1975 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल खुल्लर ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का चेयरमैन बनने से मना कर दिया है. वह अभी वाणिज्य सचिव हैं. सूत्रों का कहना है कि राहुल खुल्लर ने कैबिनेट सचिव अजीत सेठ से मुलाक़ात की और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन बनने से इंकार कर दिया. ग़ौरतलब है कि राहुल खुल्लर ने इससे पहले भी ऐसा किया था. तब उन्होंने यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत बनने से इंकार कर दिया था. सूत्रों का कहना है कि खुल्लर द्वारा इंकार करने के बाद डीआईपीपी के पूर्व सचिव आर पी सिंह एवं कृषि सचिव प्रदीप कुमार बसु के नाम दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन पद के लिए सामने आ रहे हैं. वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, राहुल खुल्लर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. राहुल खुल्लर के रिटायरमेंट में केवल 11 महीने बचे हैं और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उन्हें इस मंत्रालय से हटाने के लिए ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं.

रतन कुमार सचिव बने

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरके) के निदेशक के तौर पर काम कर रहे डॉ. रतन कुमार सिन्हा को परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईए) में सचिव बनाया जाएगा. वह श्रीकुमार बनर्जी की जगह लेंगे.

अनिल स्वरूप गृह मंत्रालय गए

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल स्वरूप को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह दिलीपराज एस चौधरी की जगह लेंगे.

राज प्रताप और अनुराधा प्रसाद जेएस बने

1983 बैच के आईएएस अधिकारी राज प्रताप सिंह को आयुष विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. इसी तरह 1986 बैच की आईडीएएस अधिकारी अनुराधा प्रसाद को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अजीत कुमार की जगह लेंगी.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 11
दिल्ली, 21 मई-27 मई 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888, 6452888, 011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जनता गले तक महंगाई में डूबी हुई है, उसका दम घुट रहा है. सरकार का रवैया उदासीन है. वित्त मंत्री कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है.

खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश

यह एक छलावा है

मनीष कुमार

तृणमूल कांग्रेस खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध कर रही है और हक़ीक़त यह है कि उसके समर्थन के बिना सरकार इसे लागू नहीं कर सकती है. तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस को इस मुद्दे पर मनाने के लिए हिलेरी क्लिंटन को लगाया गया है. खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश को लाया जाएगा या नहीं, इसका फ़ैसला संसद में होगा.

भारतीय राजनीति में शर्मनाक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं. क्या हमने अमेरिका को भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने की छूट दे दी है. अगर नहीं, तो देश की विपक्षी पार्टियां और मीडिया ने यह बात क्यों नहीं उठाई कि अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने ममता बनर्जी से खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश जैसे विवादित मामले पर क्यों बात की? जबकि सबको यह पता है कि विदेशी पूंजी निवेश एक ऐसा मसला है, जिसे लेकर यूपीए गठबंधन में रस्साकशी चल रही है. विपक्ष हंगामा कर रहा है. यह मामला संसद में बहस का मुद्दा है. यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर सरकार का भविष्य अधर में लटका हुआ है. तृणमूल कांग्रेस खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश का विरोध कर रही है और हक़ीक़त यह है कि उसके समर्थन के बिना सरकार इसे लागू नहीं कर सकती है. तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस को इस मुद्दे पर मनाने के लिए हिलेरी क्लिंटन को लगाया गया है. खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश को लाया जाएगा या नहीं, इसका फ़ैसला संसद में होगा. इस मुद्दे पर देश की राजनीतिक पार्टियों को जनता को जवाब देना होगा, लेकिन सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि उसने इस मुद्दे पर हिलेरी क्लिंटन की ममता बनर्जी से बातचीत पर ऐतराज़ क्यों नहीं जताया? क्या कल हम किसी विदेशी राजनयिक के साथ नक्सली समस्या, पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विवादों के बारे में बातचीत करेंगे?

हैरानी की बात है कि सरकार कहती है कि विदेशी निवेश से रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन बेरोज़गारी की मार सबसे ज़्यादा अमेरिका पर पड़ रही है. यह समझ में नहीं आता है कि अगर खुदरा क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कंपनियों के निवेश से रोज़गार के मौक़े बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को पहले अपने ही देश का उद्धार करना चाहिए. वैसे भी हिंदुस्तानियों को रोज़गार देने के लिए ये कंपनियां भारत में निवेश करेंगी नहीं. सच्चाई तो यह है कि इन बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों का मानना है कि पूरे यूरोप और अमेरिका में ये कंपनियां कर्मचारियों को सबसे कम वेतन देने और ख़राब व्यवहार करने के लिए बदनाम हैं. जो लोग इन कंपनियों में काम करते हैं, वे खुश नहीं हैं. सरकार कहती है कि विदेशी निवेश आने से देश में प्रतियोगिता बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा, लेकिन यह बात भूलने की नहीं है कि खुदरा बाज़ार में हिस्सा लेने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां अत्यधिक पूंजी लगाकर सबसे पहले सप्लाई चेन पर कब्ज़ा करती हैं और फिर क़ीमतें घटा देती हैं. सप्लाई चेन पर कब्ज़ा करने का मतलब यह है कि आज जितने लोग खाद्यान्न, फल, सब्ज़ी और दूसरी रोज़मर्रा की वस्तुओं के उत्पादन से लेकर बाज़ार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल हैं, उनकी आजीविका पर हमला होगा. होता यह है कि बाज़ार में प्रतियोगिता ही ख़त्म हो जाती है. पुराने दुकानदारों को धीरे-धीरे घाटा लगने लगता है. छोटे दुकानदारों को पहले अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ता है, ख़र्च में कटौती करनी पड़ती है और बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है. दुनिया भर में जहां-जहां इस तरह की नीति अपनाई गई, वहां यही हाल है. पुराने बाज़ारों ने दम तोड़ दिया और उनकी जगह पर बड़े-बड़े मॉल्स खुल गए. खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी के निवेश से प्रतियोगिता ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि समूचे बाज़ार पर उनका एकाधिकार हो जाता है. फिर वे जो उत्पाद चाहेंगी, उसे बेचेंगी. लोगों को मन मुताबिक़ सामान नहीं मिलेगा. इसके अलावा पूंजी की ताकत पर ये कंपनियां मनमानी क़ीमत पर सामान बेचती हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर देखती रह जाती है. दरअसल, शुरुआती दौर में ये कंपनियां पुराने बाज़ार और सप्लाई चेन को नष्ट करने के लिए क़ीमतें कम करती हैं, अच्छा सामान बेचती हैं और जब इस क्षेत्र पर कुछ मुट्ठी भर कंपनियों का एकाधिकार हो जाता है, तब ये लोगों का शोषण करने से नहीं चूकतीं.

आज़ादी के 65 सालों के बाद अगर सरकार यह कहे कि अनाज बर्बाद हो रहा है, देश में कोल्ड स्टोरेज की कमी है. तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार इतने दिनों तक देश में कोल्ड स्टोरेज बनाने के भी काबिल नहीं रही, क्या देश में कोल्ड स्टोरेज के लिए ज़मीन की कमी है, क्या देश में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए पूंजी नहीं है और क्या स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए भी विदेशी कंपनियों की ज़रूरत पड़ती है? अगर यह सच है तो हमें शर्मशार होना चाहिए कि इतने सालों में हम किसानों और अनाज को बर्बाद होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके. एक और छलावा सरकार कर रही है कि किसानों को फ़ायदा होगा, उन्हें उनके उत्पाद के लिए ज़्यादा कीमतें मिलेंगी. जहां तक बात किसानों को ज़्यादा क़ीमतें मिलने की है तो यह भी एक मिथ्या है. कई देशों में वॉलमार्ट-टेस्को जैसी कंपनियां चीनी सामान बेचती हैं. अगर भारत में ऐसी स्थिति हो गई तो देश के उत्पादक कहां जाएंगे.

सरकार के एक बयान पर ताज्जुब हुआ. सरकार कहती है कि हर निवेशक को करीब 50 फ़ीसदी पूंजी खुदरा बाज़ार से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं पर ख़र्च करनी होगी. सरकार इसे ऐसे बता रही है, जैसे कि यह कोई प्रतिबंध है या उन पर दबाव है. सच्चाई यह है कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का यह काम करने का तरीका है कि वे अपनी सप्लाई चेन बनाती हैं. मूलभूत सुविधाओं का मतलब यह नहीं कि वे गांवों में सड़क बनवाएंगी और किसानों के लिए बिजली-पानी मुहैया कराएंगी. जिन जगहों पर ये कंपनियां सामान बेचती हैं, वहां इनका अपना कोल्ड स्टोरेज होता है. माल ढुलाई के लिए ट्रक और यातायात के दूसरे साधन होते हैं. इसमें शामिल लोग कंपनी के कर्मचारी होते हैं. उन सब पर भारी ख़र्च होता है, जिसकी वजह से ये कंपनियां सस्ता सामान बेच पाती हैं. विदेशी कंपनियां अगर सीधे खेतों से सामान उठाएंगी तो यह सप्लाई चेन बर्बाद हो जाएगी. इस प्रक्रिया में शामिल लोग बेरोज़गार हो जाएंगे.

यूपीए सरकार और उसके मंत्री खुदरा व्यापार के बारे में ग़लत तथ्यों को पेशकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं. देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इस संदर्भ में सरकार जो कुछ कहती है, उसका ठीक उल्टा होता है. सरकार कहती है कि तीन महीने बाद महंगाई में कमी आएगी, महंगाई बढ़ जाती है. सरकार कहती है कि विकास दर 9 फ़ीसदी होगी. रिपोर्ट आती है कि विकास दर 6.9 फ़ीसदी है. देश की जनता का सरकारी तंत्र से भरोसा उठ ही रहा है, अब तो सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों के ज्ञान से भी भरोसा उठने लगा है. महंगाई इतनी है कि भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों के साथ खड़ा है. दुनिया के 223 देशों की सूची में भारत 202वें स्थान पर है यानी दुनिया में महज 20 ऐसे देश हैं, जहां भारत से ज़्यादा महंगाई है. यह सब तब हो रहा है, जब देश की शीर्ष कुर्सी पर भारत में उदारवाद के जनक एवं अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह विराजमान हैं. इन मुश्किलों से निपटने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने फिर से एक सपना दिखाया है

जनता गले तक महंगाई में डूबी हुई है, उसका दम घुट रहा है. सरकार का रवैया उदासीन है. वित्त मंत्री कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है. खाने-पीने की वस्तुओं की क़ीमतें आसमान पर हैं, लेकिन कृषि मंत्री कहते हैं कि देश में महंगाई बढ़ने का उनके विभाग से कोई लेना-देना नहीं. पेट्रोलियम मंत्रालय हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया है. पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार कहती है कि यह काम पेट्रोलियम कंपनियों का है और कंपनियों की मनमानी हद पार कर रही है. विपक्ष इसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेंकने में लगा है. आखिर जनता क्या करे, किसके पास जाए? ईमानदारी से काम करके मासिक वेतन पाने वाले इंसान के लिए देश में जीने की संभावना ही ख़त्म हो गई है. अगर वह बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टरों और दवा कंपनियों के हाथों मरना पड़ेगा. सरकार ने देश की जनता को ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया है, जहां लोगों के चेहरों पर उदासी है, घरों में अंधेरा है. इस पूरी व्यवस्था से अमीर भी परेशान हैं, ग़रीब की पूछ ही कहां है. हैरानी तो यह है कि किसी को पता तक नहीं है कि ग़रीब कौन है, उसकी क्या परिभाषा है? असल ग़रीब के घर में खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, वह फुटपाथ पर सोता है और उसके लिए बनी सरकारी योजनाओं के नाम पर गुंडे-मवाली मौज कर रहे हैं.

विदेशी पूंजी निवेश का सही फ़ायदा तभी संभव है, जब देश की मूलभूत सुविधाएं पहले से मजबूत हों. देश के किसानों, मज़दूरों एवं व्यापारियों की सुरक्षा और सुविधा ऐसी हो कि वे विदेशी पूंजी का सामना कर सकें. जिन देशों में इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के निमंत्रण दिया गया, वहां का खुदरा बाज़ार तबाह हो गया. भारत में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति क्या है, यह जगज़ाहिर है. फिर भी सरकार इन कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है. यह सबसे सही समय है, जब सरकार को यह बताना चाहिए कि इससे कितना रोज़गार मिलेगा, इन कंपनियों के आने से कितने लोग बेरोज़गार होंगे, कितनी दुकानों को नुक़सान होगा, किसानों को कितना फ़ायदा होगा, मज़दूरों के जीवन पर विदेशी निवेश का क्या असर पड़ेगा, देश के कुटीर उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा और गांव-शहर पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों पर सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि विदेशी पूंजी निवेश से जुड़ी भ्रांतियां ख़त्म हो सकें. ■

manish@chauthiduniya.com

फिर एक नया सपना

देश को फिर से एक सपना दिखाया जा रहा है. फिर से सरकार देश को गुमराह कर रही है. सरकार कह रही है कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश आने दो, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, किसान मालामाल हो जाएंगे, बिचौलिए और दलाल ख़त्म हो जाएंगे, खाद्यान्नों की बर्बादी ख़त्म हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी. मनमोहन सिंह ने बीस साल पहले ऐसा ही एक सपना दिखाया था. 1991 में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति लागू की थी और यह भरोसा दिलाया था कि बीस साल बाद यानी 2010 में भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा. नतीजा यह निकला कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मज़दूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है. शहर और गांवों में इतना अंतर पैदा हो गया है कि देश शीत गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन भारत में एक तबका ऐसा भी है, जो सरकार की नव उदारवादी नीतियों के समर्थन में है. उसका मानना है कि कम क़ीमतों पर अच्छा और ब्रांडेड माल ख़रीदना हर नागरिक का अधिकार है. जिस देश में 80 फ़ीसदी लोगों की दैनिक आय दो डॉलर से कम हो, उस देश में ऐसी दलील देना अमानवीय है. ■

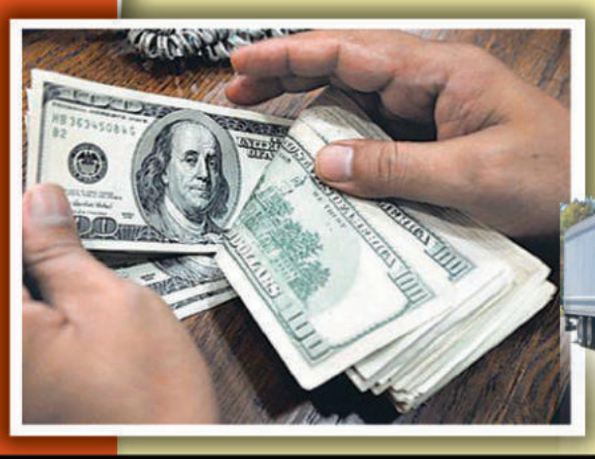

खुदरा व्यापार क्या है

खुदरा व्यापार का मतलब है कि जब कोई दुकानदार किसी मंडी या थोक व्यापारी के माध्यम से माल या उत्पाद ख़रीदता है और फिर अंतिम उपभोक्ता को छोटी मात्रा में बेचता है. खुदरा व्यापार का मतलब है कि उन सामानों की ख़रीद-बिक्री, जिन्हें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं. रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं या माल को हम किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, रेहड़ी और पटरी वालों आदि से ख़रीदते हैं. ये दुकानें घर के आसपास होती थीं. फिर शहरों में एक नया दौर आया, जब बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल खुलने लगे, जहां बिग बाज़ार, रिलायंस आदि जैसे सुपर मार्केट में खुदरा सामान बिकने लगा. एक ही छत के नीचे इन बड़ी-बड़ी दुकानों में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं मिलने लगीं. हर शहर में इसका ट्रेंड चल पड़ा. पिछले कुछ सालों में इन मॉल्स का सबसे ज़्यादा विपरीत असर पारंपरिक खुदरा बाज़ार पर पड़ा. बड़े-बड़े शहरों में लोग मॉल्स का रुख करने लगे. अब इसी बाज़ार में विदेशी पूंजी को निमंत्रण भेजा जा रहा है. इसके बाद देश में बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां शॉपिंग मॉल्स खोलेंगी, जहां रोज़मर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी खुदरा वस्तुएं बिकेंगी. ख़तरा इस बात का है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि खुदरा बाज़ार में इनके आने से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपरेखा बदल जाएगी. इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि जब बड़ी-बड़ी कंपनियां खुदरा बाज़ार में आती हैं तो क्या होता है. ■

वर्ष 2002 में बीईएमएल के एक कर्मचारी के एस पेरियास्वामी ने रक्षा मंत्रालय को लिखे एक पत्र में टेट्रा ट्रकों की ख़रीद के मामले की व्यापक जांच कराने का अनुरोध किया था.

भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का सपना खोखला साबित

हर तरफ़ लूट की खुली छूट

राजेश सिन्हा

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश सरकार भले ही सुशासन की दुहाई देकर भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल डालने के दावे करती हो, लेकिन हक़ीक़त यह है कि भ्रष्टाचारियों को लूट की छूट मिली हुई है. सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावे किए जाने के बावजूद नित्य नए-नए घोटाले सामने आ रहे हैं. बावजूद इसके सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शायद उचित नहीं समझती. सूबे का शायद ही कोई नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालय हो, जहां विभिन्न योजनाओं के नाम पर लाखों-करोड़ों का घोटाला न हुआ हो. महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट से इस बात का ख़ुलासा हो चुका है, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात तो दूर, लूट की संस्कृति पर अंकुश लगाना तक मुनासिब नहीं समझा गया. छपरा, मोतिहारी, सहरसा, खगड़िया एवं बेगूसराय आदि ज़िलों की कौन कहे, पटना नगर निगम कार्यालय भी इस मामले में अछूता नहीं है. महालेखाकार की रिपोर्ट में लगभग 13 करोड़ रुपये की धनराशि डकार लिए जाने के ख़ुलासे के बाद भी दोषियों के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. छपरा नगर परिषद कार्यालय में राजस्व वसूली के नाम पर लगभग दस लाख रुपये डकार लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है. प्रधान महालेखाकार कार्यालय की ऑडिट टीम द्वारा आय-व्यय का लेखा-जोखा लेने के दौरान यह बात सामने आई कि राजस्व के दस लाख रुपये रोकड़पाल द्वारा नगर परिषद निधि में जमा न करके डकार लिए गए. वसूली पंजी एवं रोकड़ बही के मिलान से यह फ़र्ज़ीवाड़ा सामने आने के बाद जांच टीम द्वारा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन दाग़ी कर्मचारी अभी भी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं. ऑडिट टीम द्वारा कई तरह की अनियमितताएं उजागर की गईं, बावजूद इसके मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक़, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि नगर परिषद छपरा द्वारा 2008 से आज तक बजट पेश ही नहीं किया गया. बिना बजट पेश किए मनमाने ढंग से पैसा ख़र्च करने की शायद परंपरा कायम हो चुकी है. नगर परिषद के पदाधिकारियों एवं वार्ड पार्षदों की मनमानी का आलम यह है कि एक द्वादश वित्त के तहत आवंटित 71.3 लाख रुपये में से 50 प्रतिशत धनराशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ख़र्च करने के बजाय डीजल की ख़रीददारी, ट्रैक्टर मरम्मत सहित अन्य मदों में ख़र्च कर दी गई. नगर प्रबंधन की क्षमता वृद्धि और ई-गवर्नेंस पर एक अदद रुपया ख़र्च नहीं किया गया. आवंटित धनराशि के ख़र्च का हिसाब-किताब भी विभाग के पास नहीं है. जानकारों के मुताबिक़, अपशिष्ट प्रबंधन की धनराशि डीजल एवं वाहन मरम्मत के नाम पर ख़र्च किए जाने की अगर जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं. छपरा ही नहीं, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया एवं मोतिहारी सहित कई अन्य ज़िलों में भी इसी तरह सरकारी पैसों की लूट की गई.

महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट में यह ख़ुलासा किया गया है कि पटना नगर निगम कार्यालय में राजस्व घोटाले का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है. राजस्व वसूली के नाम पर अब तक 12 करोड़ 38 लाख 96 हज़ार रुपये का घोटाला हो चुका है. महालेखाकार के आदेशानुसार 1998-99 से लेकर 2004-05 तक का अंकेक्षण करने पहुंचे जांच दल ने करोड़ों की धनराशि के गबन का मामला प्रमाणित करते हुए अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की. रिपोर्ट में कंडिका संख्या 10 (1)2, 19, 22(1), 25, 27, 28, 30,32 एवं 34 के अंतर्गत भारी अनियमितता की बात स्पष्ट करते हुए कंडिका संख्या 10 (1) 2 में एक करोड़ 75 लाख रुपये की अनियमितता पाए जाने की चर्चा की गई है. कंडिका संख्या 19 में सिटी अंचल के नाम पर 36 लाख 63 हज़ार, कंडिका संख्या 22(1) (11) में बांकीपुर अंचल के नाम पर 5 लाख 63 हज़ार और कंडिका संख्या 25 में मेसर्स कामना इंटरप्राइजेज के नाम पर 17 लाख 78 हज़ार रुपये की अवैध निकासी का उल्लेख किया गया है. इसी तरह कंडिका संख्या 27 में कहा गया है कि 4 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से यारपुर डोमखाना का आधुनिकीकरण किया जाना था, लेकिन उक्त धनराशि ख़र्च किए जाने के बाद भी यह काम नहीं हो सका. कंडिका संख्या 28 में 38 लाख 84 हज़ार रुपये की अनियमितता पाए जाने की चर्चा है. कंडिका संख्या 29 में बेकार उपकरणों की मरम्मत के नाम पर 42 लाख 11 हज़ार रुपये ख़र्च किया जाना अनावश्यक क़रार दिया गया. कंडिका संख्या 30 में बांकीपुर अंचल के मछुआ टोली स्थित निर्माणाधीन भवन के मामले में 4 करोड़ 30 लाख 37 हज़ार रुपये की अनियमितता की बात है. कंडिका संख्या 32 में सीमेंट ख़रीद के नाम पर 27 लाख 60 हज़ार रुपये की अनियमितता रेखांकित की गई है. महालेखाकार के एम एन लाल दास द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन (डायरी संख्या 3543/18.05.06) सौंपे जाने के बाद पटना नगर निगम की बैठक में अनियमित भुगतान एवं अंकेक्षण रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया गया था. कार्रवाई न होता देख महालेखाकार ने एक बार फिर अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या 747/2008-09-10) पटना नगर निगम को सौंपा, लेकिन दोनों अंकेक्षण प्रतिवेदन फाइलों में धूल चाट रहे हैं. सूबे का एनआरईपी विभाग भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर रह गया है. पूर्वी चंपारण ज़िले में इस विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में जेब भरने का सिलसिला जारी है. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं लिपिक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. इन अधिकारियों-कर्मचारियों को न सुशासन का भय सता रहा है और न आयकर या निगरानी विभाग का. कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माण, ई-किसान भवन निर्माण सहित कई योजनाओं के नाम पर सरकारी पैसों की लूट की गई. विभागीय नियम-क़ानून को ताख़ पर रखकर एनआरईपी के कार्यपालक अभियंता नीरज वर्मा द्वारा कनीय अभियंता गोरखनाथ सिंह को छौड़ादानों, अरेराज एवं पहाड़पुर प्रखंड के ई-किसान भवन निर्माण के लिए अभियंता बनाते हुए एक करोड़ 60 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया. जबकि गोरखनाथ हरसिद्धि प्रखंड में कार्यरत थे. मजेदार तथ्य यह है कि उनका तबादला भी पश्चिम चंपारण के लिए हो चुका था. आख़िर कार्यपालक अभियंता के समक्ष ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि गोरखनाथ का तबादला होने के बाद भी उनके क्षेत्र से बाहर के प्रखंड के ई-किसान भवन निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया? वैसे जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा के आदेशानुसार एनआरईपी के निदेशक उमाशंकर राम की अध्यक्षता में गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि नियम-क़ानून से अनभिज्ञ कार्यपालक अभियंता नीरज वर्मा द्वारा निज़ी स्वार्थ में वशीभूत होकर उक्त अग्रिम भुगतान किया गया. कनीय अभियंता सह अभिकर्ता गोरखनाथ के निज़ी बैंक खाता (इंडियन बैंक की मोतिहारी शाखा के खाता संख्या 971427380) में 27 जुलाई, 2011 से 10 अक्टूबर 2011 तक 87 लाख से एक करोड़ तक की धनराशि जमा होना यह प्रमाणित करता है कि लूट के मामले में बिहार का कोई सानी नहीं है. राज्य के नौकरशाह कितने संवेदनहीन हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2008 में आई बाढ़ के दौरान तबाह हुए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया एवं पूर्णियां के पीड़ित परिवारों का निवाला भी इन लोगों द्वारा गटक लिया गया. जबकि कोसी की विनाशलीला से हलकान लोगों को देखकर पूरे देश का सीना दहल गया था. इन पांच ज़िलों के 993 गांवों के लगभग 33 लाख लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा न केवल ख़जाना खोल दिए जाने की बात कही गई थी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी पीड़ितों की मदद के लिए मददगार आगे आए, लेकिन कफन में जेब तलाशने के आदी हो चुके अधिकारी-कर्मचारी पीड़ितों की सहायता राशि भी डकारने से बाज़ नहीं आए और महज 15-20 प्रतिशत बाढ़ पीड़ितों के बीच सरकारी धनराशि पहुंच सकी. इतना ही नहीं, काल के गाल में समा चुके लोगों के नाम पर फ़र्ज़ीवाड़ा करके सरकारी पैसा गटक लिया गया. मधेपुरा अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के लोगों की बातों पर अगर विश्वास किया जाए तो मृत दादा-दादी के नाम पर भी बाबुओं द्वारा साठगांठ करके फ़सल क्षतिपूर्ति के रूप में दो-दो हज़ार रुपये निकाल लिए गए. जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पूरे इलाक़े में इस तरह की लूट का खेल खेला गया. सुशासन बाबू को शायद पता नहीं है कि सभी विभागों में भ्रष्ट नौकरशाहों का बोलबाला है. प्रखंड से लेकर ज़िला स्तर तक के पदाधिकारी बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि डकारने से बाज नहीं आ रहे हैं. ■

ट्रक, ज़मीन और नायर

नवीन चौहान

navinchauhan@chauthiduniya.com

टेट्रा ट्रकों की ख़रीद के मामले में जनरल वी के सिंह को रिश्वत की पेशकश के ख़ुलासे के बाद हर दिन यह मामला एक नया मोड़ लेता जा रहा है. अब इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख सचिव रहे टीकेए नायर का नाम सामने आया है. नायर पर आरोप है कि बीईएमएल की को-ऑपरेटिव सोसायटी में उनके नज़दीकी लोगों को ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से प्लॉटों का आवंटन किया गया था. इन नज़दीकी लोगों में उनकी भतीजी प्रीथी प्रभा और मित्र उमा देवी नांबियार शामिल हैं. हालांकि इन ख़बरों का नायर ने खंडन कर दिया है. फिर भी उन पर टेट्रा मामले में जांच को प्रभावित करने के आरोप लगने लगे हैं.

वर्ष 2002 में बीईएमएल के एक कर्मचारी के एस पेरियास्वामी ने रक्षा मंत्रालय को लिखे एक पत्र में टेट्रा ट्रकों की ख़रीद के मामले की व्यापक जांच कराने का अनुरोध किया था. उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि टेट्रा ट्रक का निर्माण चेकोस्लाविया की कंपनी टेट्रा एएस करती है, जबकि बीईएमएल टेट्रा सिपॉक्स से इन ट्रकों की ख़रीद कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि टेट्रा सिपॉक्स एक बिचौलिया कंपनी है, उसे ठेका दिए जाने के पीछे एक षड्यंत्र है. पेरियास्वामी को रक्षा मंत्रालय से कोई जवाब नहीं मिला. पेरियास्वामी बीईएमएल में शेयर धारक भी हैं. उन्होंने टेट्रा का मामला 2002 में कंपनी की वार्षिक बैठक में भी उठाया था. वह यह मामला हर बैठक में उठाते रहे, मगर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. फिर उन्होंने ब्रिटिश उच्चायोग से इसके बारे में जानकारी मांगी. ग़ैर आधिकारिक रूप से डील से संबंधित जानकारियां एकत्र करने के आरोप में उन्हें बीईएमएल से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

इसी संबंध में 2005 में की गई एक शिकायत को केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय (जहां टीकेए नायर उस समय मुख्य सचिव थे) के पास भेज दी गई. जनरल वी के सिंह को रिश्वत की पेशकश के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई इस संबंध में बीईएमएल प्रमुख नटराजन सहित कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है. द हिंदू अख़बार में छपी ख़बर में यह बताया गया है कि बीईएमएल को-ऑपरेटिव सोसायटी में नायर के क़रीबियों, उनकी भतीजी प्रीथी प्रभा और उमादेवी नांबियार को 2400 वर्ग फुट के प्लॉट 10.8 लाख रुपये की क़ीमत पर आवंटित किए गए थे. यह आवंटन 450 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किया गया था, जबकि प्लॉट का बाज़ार मूल्य 2500 से 3000 रुपये प्रति वर्ग फुट था. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के क़रीबियों को प्लॉट आवंटित करने का मामला इसलिए गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसी वक़्त प्रधानमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले की जांच उस संस्था (बीईएमएल) के ख़िलाफ़ कर रहा था. वर्ष 2010 में एक पूर्व बीईएमएल कर्मचारी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत के आधार पर आवंटित प्लॉट को बिना किसी विरोध के वापस कर दिया जाना अंदरूनी साठगांठ के शक को और गहरा करता है.

अगर नायर ने इन आरोपों को एक सिरे से नकार दिया है तो उनके लिए कुछ सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे प्रीथी प्रभा और उमा देवी कभी भी बीईएमएल की कर्मचारी नहीं रही हैं तो उन्हें किस आधार पर प्लॉट आवंटित कर दिए गए, जबकि प्रदेश सरकार ने बीईएमएल को कम क़ीमत पर ज़मीन इसलिए उपलब्ध कराई थी, क्योंकि बीईएमएल सोसायटी के उप नियमों में प्लॉटों का आवंटन बीईएमएल कर्मचारियों के लिए ही करने की बात कही गई थी. उच्चतम न्यायालय ने 1995 में अपने एक आदेश में इस तरीक़े की सोसायटी की सदस्यता को कर्मचारियों तक ही सीमित रखने की बात कही है. ऐसी परिस्थिति में नायर के दोनों क़रीबियों को प्लॉट आवंटित क्यों किए गए, जबकि नायर प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव रहते हुए बीईएमएल के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे, ख़ासकर बीईएमएल प्रमुख नटराजन के ख़िलाफ़. क्या नायर को इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं थी कि बिक्री पत्र में गवाह के रूप में नटराजन के कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और वह भी तब, जब नायर स्वयं नटराजन के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर रहे थे? किस वजह से प्रीथी प्रभा और उमा देवी नांबियार ने आवंटित प्लॉट सोसायटी को वापस कर दिए? इन परिस्थितियों में प्लॉट आवंटन में हुई धांधली के विषय में किसी के ख़िलाफ़ आज तक कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई?

ताक़तवर लोग आरोपों से परे होते हैं और यह बात प्रधानमंत्री के सलाहकार पर भी लागू होती है. आज देश के सर्वोच्च संस्थानों पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ अनियमितताएं बरते जाने का भी शक है. प्रधानमंत्री के सलाहकार पर उठ रहे सवाल देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. देश के उच्चाधिकारियों की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ऐसे मुद्दों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए और ख़ासकर तब, जब मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हो. ■

ताक़तवर लोग आरोपों से परे होते हैं और यह बात प्रधानमंत्री के सलाहकार पर भी लागू होती है. आज देश के सर्वोच्च संस्थानों पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ अनियमितताएं बरते जाने का भी शक है.

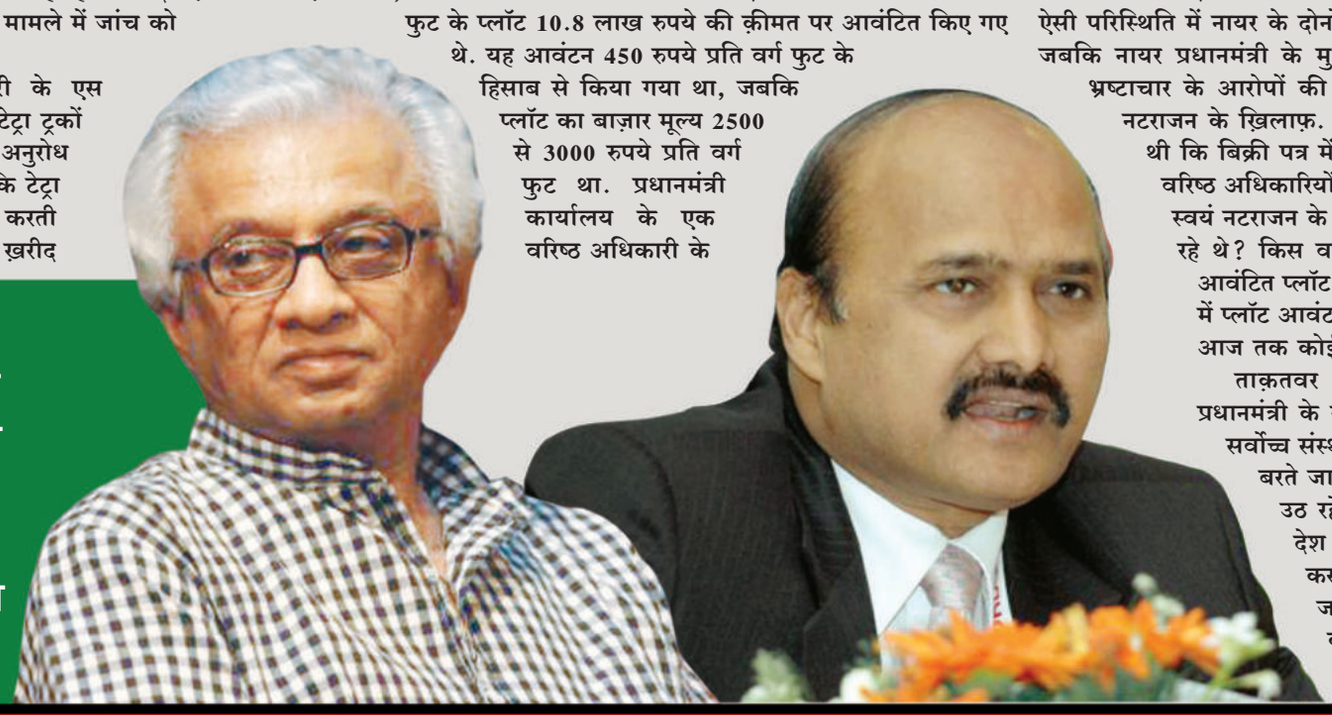

गांधी ने आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के झंडे तले लड़ी थी. सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना देश की आज़ादी के लिए हुई थी.

बापू की वस्तुओं की नीलामी पर तीखी प्रतिक्रिया

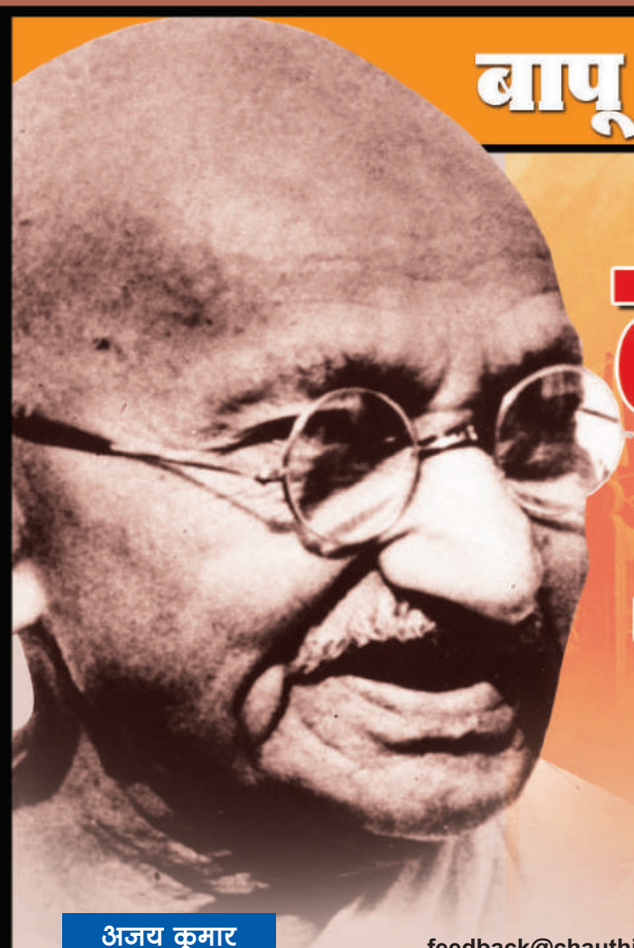

कांग्रेस गांधी की गुनहगार है

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मोहनदास करम चंद गांधी यानी महात्मा गांधी के निधन को 65 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी वह पूरी दुनिया के लिए उतने ही प्रासंगिक नज़र आते हैं, जितने वह जीते जी हुआ करते थे. गांधी जी की समकालीन कई महान हस्तियां इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गई हैं, लेकिन गांधी दर्शन आज भी जीने की कला बना हुआ है. कुछ मामलों में तो लगता है कि आज उनकी प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ गई है. वैश्विक स्तर पर व्याप्त हिंसा, बेरोज़गारी, महंगाई और तनावपूर्ण वातावरण देखकर तो यही लगता है कि गांधी की सोच के सहारे ही हम उक्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. बापू के साथ वाले लोग तो अब कम ही रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़कर जितना लोगों ने समझा है, उसके अनुसार, गांधी जी एक जीवनशैली जैसे थे, जिसमें अहंकार, छूआछूत, द्वेष एवं हिंसा की कोई जगह नहीं थी. इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा कि गांधी जी का जन्म सिर्फ़ हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए हुआ था. वह ताउम्र आज़ादी के लिए लड़ते रहे और जब देश आज़ाद हो गया तो वह दुनिया से रुखसत हो गए.

रामेश्वर नाथ मिश्र

कलराज मिश्र

लाल जी टंडन

गांधी ने आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के झंडे तले लड़ी थी. सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना देश की आज़ादी के लिए हुई थी. 1921 से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे गांधी जी की इच्छा थी कि अपना मक़सद हासिल कर चुकी कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बापू को उस समय करारा झटका लगा, जब कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता सुख उठाने की लालसा में उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया. तबसे लेकर आज तक कांग्रेसी गांधी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं. यह और बात है कि उनका गांधी की विचारधारा से दूर का भी नाता नहीं रह गया है. कांग्रेस ने गांधी के विचारों और धरोहर को जितना नुक़सान पहुंचाया, शायद ही किसी और ने पहुंचाया होगा. सत्ता की चाह में कांग्रेसी पूरी तरह से भूल गए कि गांधी जी हमारे आदर्श थे और उनकी धरोहर से आम हिंदुस्तानी मार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है. उनकी धरोहर एक विरासत की तरह है, जिसे सहेज कर रखना सरकार ही नहीं, आम आदमी का भी नैतिक धर्म है, लेकिन पिछले दिनों गांधी जी की धरोहर की नीलामी के प्रति जिस तरह की बेरुख़ी कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिखाई, उससे आम हिंदुस्तानी की भावनाओं को काफ़ी ठेस लगी. गांधी का नाम बेचने वाले कांग्रेसियों को भले ही इस बात का मलाल न हो, लेकिन भला हो कमल मोरारका फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स का, जिसने समय रहते न केवल ब्रिटेन में हुई नीलामी में भाग लेने के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी कीं, बल्कि एक मोटी रक़म ख़र्च करके महात्मा गांधी से जुड़ी 29 स्मरणीय वस्तुओं को ख़रीद भी लिया. फाउंडेशन जल्द ही इन चीज़ों को भारत लेकर आएगा. गांधी जी से जुड़ी वस्तुओं में उनका चश्मा, चरख़ा, प्रार्थना पुस्तिका और कुछ पत्रों के अलावा नई दिल्ली के बिड़ला हाउस से उठाई गई थोड़ी सी मिट्टी और घास शामिल है, जहां 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी और वह लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़े थे. कमल मोरारका फाउंडेशन की जहां इस बात के लिए तारीफ़ हो रही है कि वह देश की धरोहर को देश में वापस ले आया, वहीं केंद्र सरकार के रवैये से हर वर्ग नाराज़ है. व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, नौकरीपेशा, गृहणियों, छात्र–छात्राओं, युवाओं, राजनेताओं और यहां तक कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी गांधी के प्रति सरकार की बेरुख़ी पर अफ़सोस जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की आत्मा मर चुकी है. उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है.

गांधी को लेकर भारत सरकार भले ही निराशावादी दृष्टिकोण अपना रही हो, लेकिन दुनिया अभी भी गांधी को सम्मान देती है. इस बात का अहसास हाल में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान हुआ. उनके स्वागत में बोलते हुए वहां के राष्ट्रपति ज़ैकब जुमा ने जो कहा, उसका सार यही था कि गांधी दक्षिण अफ्रीका के ख़ून में हैं, उसकी हर सांस में हैं. गांधी भारत में जन्मे, पढ़े, बढ़े और उसे स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी. अपने उसूलों के कारण ही उनकी शहादत भी हुई. क्या भारत में महात्मा गांधी के प्रति इस प्रकार की भावना किसी राजनीतिज्ञ द्वारा व्यक्त की गई? इस सवाल का जवाब लोग आज जानना चाहते हैं. विश्व में अनेक राष्ट्र महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर स्वतंत्र हुए हैं. हाल में इसका उदाहरण अरब राष्ट्रों में देखने को मिला. ताज्जुब होता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है. हम अपने पुरखों की धरोहर सहेज कर रखते हैं, फिर गांधी जी से जुड़ी धरोहर के प्रति उदासीनता का क्या औचित्य है. लंदन में गांधी जी से जुड़ी कुछ चीज़ों की नीलामी में हमारी सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई, यह गांधी जी के प्रति संवेदनहीनता है. इस प्रश्न पर विरोधी पार्टियों की भूमिका भी हैरत में डालने वाली है. गांधीवादी लोगों ने भी

नीरज बोरा

राजेंद्र चौधरी

इस विषय में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, वे केवल सरकार का मुंह ताकते रहे. गांधी जी की धरोहर आज विश्व की धरोहर बन चुकी है. उसके प्रति उपेक्षा का व्यवहार किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता. गांधी जी की धरोहर के प्रति कांग्रेस की बेरुख़ी से दु:खी साहू युवा महासभा ने पिछले दिनों लखनऊ में धरना देकर अपनी नाराज़गी जताई.

उत्तर प्रदेश गांधी आश्रम के क्षेत्रीय मंत्री एवं सुप्रसिद्ध गांधीवादी रामेश्वर नाथ मिश्र ने जब यह ख़बर पढ़ी तो उनके दिल पर गहरी चोट लगी. गांधी जी के प्रति सरकार की उदासीनता से वह काफी दु:खी दिखे. उन्होंने अपने संस्मरण की पोटली खोलते हुए कहा कि पिछले दिनों एक सज्जन स्पेन से और एक सज्जन ग्रीस से आए, दोनों ही खादी प्रेमी हैं और जब भी आते हैं तो खादी के वस्त्र ख़रीद कर ले जाते हैं. दोनों ने बताया कि यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसकी मुख्य वजह यंत्रीकरण का विनाशकारी प्रभाव और अर्थव्यवस्था का केंद्रीयकरण है. आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर नौजवान बेकार हो गए हैं. वे कॉरपोरेट कार्य पद्धति का विरोध कर रहे हैं, बैंकों का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि कॉरपोरेट सेक्टर की काली कमाई इन बैंकों में जमा है. उन महानुभावों का कहना था कि यूरोप में पागलपन की हद तक यंत्रीकरण के विनाशकारी प्रभाव और वर्तमान आर्थिक विसंगति को दूर करने के लिए हमें गांधी जी की आवश्यकता है, किंतु दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है. ऐसे शख्स की धरोहर के प्रति उसके अपने देश में उपेक्षा का भाव कृतघ्नता का द्योतक है. मिश्र का कहना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरोहर को एक भारतीय उद्योगपति कमल मोरारका ने नीलामी से ख़रीद कर अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया है. कमल मोरारका साधुवाद के पात्र हैं. मोरारका गांधी जी की धरोहर राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंपना चाहते हैं. सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया जा सके कि उनके पूर्वजों की नज़र में गांधी का कितना सम्मान था.

लखनऊ के सांसद लाल जी टंडन ने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बापू की वस्तुओं की नीलामी की ख़बर लंदन के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं फैली थी, बल्कि पूरे विश्व में गांधी की इन अमूल्य वस्तुओं को ख़रीदने की होड़ मची थी, लेकिन भारत सरकार इस नीलामी से बेख़बर थी. सत्ताधारी कांग्रेस में उन वस्तुओं को पाने की ललक नहीं दिखी और न प्रधानमंत्री की ओर से कोई क़दम आगे बढ़ाया गया. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि नीलामी होने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की तंद्रा टूटी. आख़िर इस नीलामी पर सरकार में बैठे लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया. सोनिया की बातों से तो यही एहसास होता है कि उनकी सरकार और संगठन पर पकड़ कमज़ोर हो गई है. आज़ादी के बाद गांधी जी की बात मानकर यदि कांग्रेस का विघटन कर दिया जाता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता. जो कांग्रेस गांधी के नाम पर रोटियां सेंकती है, उसका गांधी की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कलराज मिश्र का कहना था कि कांग्रेस को देश में एक ही गांधी परिवार रास आता है. वह उनका स्वयं का परिवार. गांधी जी की आत्मा को जितना दु:ख कांग्रेस से मिला, शायद ही किसी और से मिला होगा. भले ही पूरी दुनिया ने गांधी का सम्मान किया हो, लेकिन कांग्रेस के लिए वह वोट बटोरने के माध्यम से अधिक कुछ नहीं रहे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव का कहना था कि कांग्रेसियों द्वारा बापू की अनमोल वस्तुएं हासिल करने की कोशिश न करना एक बड़ी भूल थी. यह ग़लती पार्टी के लिए और खास तौर से कांग्रेस के गांधीवाद पर धब्बा कही जाएगी. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना था कि कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ था. संघ ने अगर गांधी जी के शरीर को मारा तो कांग्रेस ने गांधी की आत्मा की हत्या करने का काम किया. दोनों बराबर के गुनहगार हैं. साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर गांधी जी की स्मृति से जुड़ी चीजों की नीलामी से इतने आहत हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वह अपना पद्मश्री अवॉर्ड सरकार को लौटा देंगे. उनका कहना था कि इस नीलामी के लिए भारत सरकार पूरी तरह से दोषी है. यह गांधी और देशवासियों का अपमान है. सरकार के पास पर्याप्त समय था और उन्होंने 5 अप्रैल को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था.

प्रसिद्ध संरक्षण विशेषज्ञ एवं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) के पूर्व महानिदेशक ओ पी अग्रवाल कहते हैं कि गांधी जी की वस्तुओं की नीलामी हमारी भावनाओं को आहत करने वाली ख़बर थी, लेकिन हक़ीक़त यहां तक सीमित नहीं है. सच्चाई यह भी है कि भारत में बापू के ख़ून से सनी शॉल और जो दूसरे कपड़े हैं, वे भी समुचित विधि से संरक्षित नहीं हैं. अगर उनके संरक्षण के प्रयास नहीं हुए तो वे भी नष्ट हो जाएंगे. अग्रवाल ने देश में जगह–जगह रखे पत्रों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता जताई. हाल में ही भाजपा में शामिल हुए सुधीर हलवासिया का कहना था कि केंद्र सरकार कोमा में है, उससे कोई उम्मीद करना बेमानी है. गांधी जी के नाम को इन लोगों ने बेचा तो ख़ूब, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपनाई. कांग्रेस चुनाव के वक़्त तो गांधी के चरखे को गीतों में पिरोकर ख़ूब गवाती है, लेकिन गांधी के उसी चरखे को भूल जाती है, जिसे वह स्वयं चलाकर अपने लिए कपड़े बुनते थे. कांग्रेस नेता नीरज बोरा ने कहा कि यह एक ग़लती है, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे गंभीरता से लिया है.■

गांधी को लेकर भारत सरकार भले ही निराशावादी दृष्टिकोण अपना रही हो, लेकिन दुनिया अभी भी गांधी को सम्मान देती है. इस बात का अहसास हाल में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान हुआ. उनके स्वागत में बोलते हुए वहां के राष्ट्रपति ज़ैकब जुमा ने जो कहा, उसका सार यही था कि गांधी दक्षिण अफ्रीका के ख़ून में हैं, उसकी हर सांस में हैं. गांधी भारत में जन्मे, पढ़े, बढ़े और उसे स्वतंत्र कराने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी. अपने उसूलों के कारण ही उनकी शहादत भी हुई. क्या भारत में महात्मा गांधी के प्रति इस प्रकार की भावना किसी राजनीतिज्ञ द्वारा व्यक्त की गई? इस सवाल का जवाब लोग आज जानना चाहते हैं.

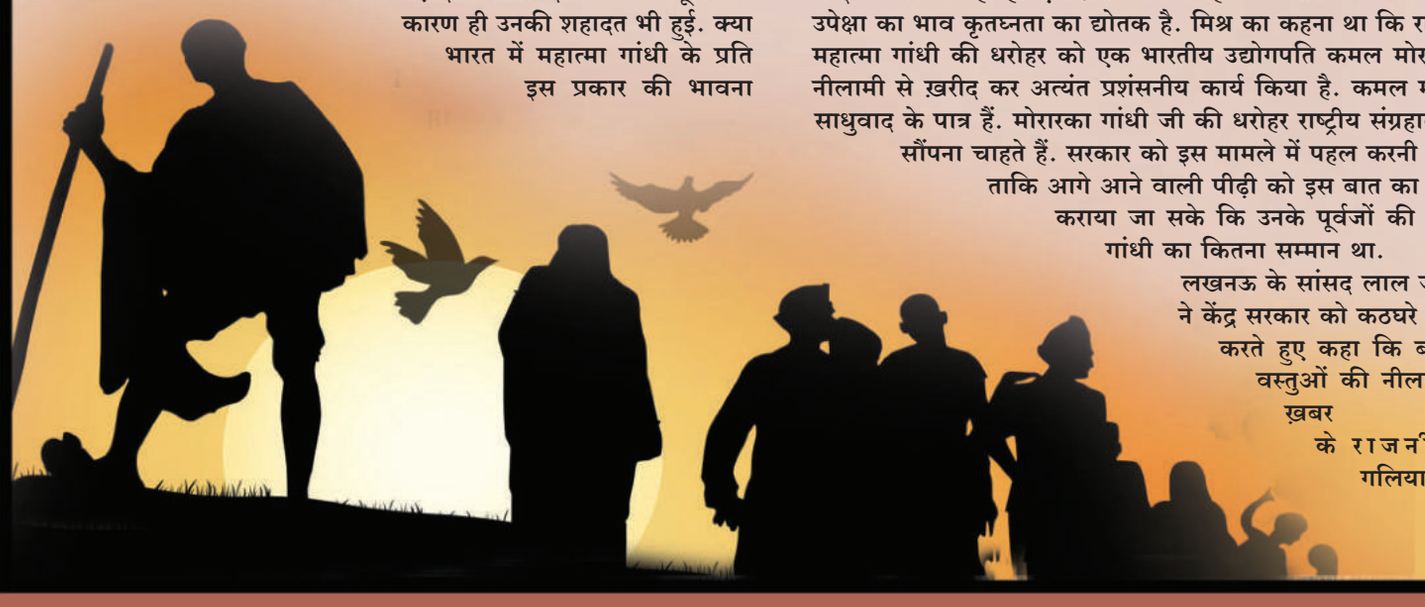

कमेटी ने एक तरफ़ दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा एवं सलमान खुर्शीद जैसे बड़बोले नेताओं पर उंगली उठाई, वहीं दूसरी तरफ़ उसे प्रत्याशी चयन के तरीक़ों पर भी सख्त ऐतराज दिखा.

एंटनी कमेटी की रिपोर्ट

उपेक्षा, गुटबाज़ी और बयानबाज़ी कांग्रेस को ले डूबी

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की समीक्षा कर रही एंटनी कमेटी ने दिल्ली में अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तमाम सिफारिशों और हार के कारणों के ख़ुलासे के साथ सौंप दी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए बड़े नेताओं के नाते-रिश्तेदारों को टिकट देने, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कांग्रेसियों की आपसी गुटबाज़ी और बड़बोलेपन को मुख्य वजह बताया. कमेटी ने सिफारिश की है कि बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच का अंतर ख़त्म हो, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस इकाइयों के अध्यक्ष, सांसद, विधायक आसानी से उपलब्ध रहें. कमेटी ने अनुशासन को सर्वोपरि रखने की भी बात कही है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा एवं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार सफलता न मिल पाने के कारणों का पता लगाने के लिए ए के एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें एंटनी के अलावा सुशील कुमार शिंदे एवं शीला दीक्षित भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश की हार पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ा सदमा रही, राहुल गांधी के सघन प्रचार अभियान के बावजूद पार्टी को मुंह की खानी पड़ी. पार्टी सिर्फ़ 28 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी, जबकि कांग्रेस के नेता बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आला कमान पर दबाव बनाकर अपने परिवार वालों के लिए दिल खोलकर टिकट हासिल किए. कुछ नेताओं को छोड़कर सभी बड़े नेताओं के पुत्र-पुत्रियों, पत्नी एवं भाई आदि को हार का सामना करना पड़ा. कमेटी ने गुटबाज़ी करने वालों और हार के लिए ज़िम्मेदार नेताओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी नेतृत्व और तथाकथित बड़े नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है. कमेटी ने एक तरफ़ दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा एवं सलमान खुर्शीद जैसे बड़बोले नेताओं पर उंगली उठाई, वहीं दूसरी तरफ़ उसे प्रत्याशी चयन के तरीक़ों पर भी सख्त ऐतराज दिखा. कमेटी ने सबसे ज़्यादा आपत्ति गुटबाज़ी को लेकर ज़ाहिर की. कमेटी ने यहां तक कहा है कि अगर अब भी गुटबाज़ी और भितरघात की प्रवृत्ति से तौबा नहीं की गई तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शायद ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी. कमेटी ने हैरानी जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सुधरेंगे, इसकी संभावना कम नज़र आती है. एंटनी कमेटी ने खेद जताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जहां बाक़ी दल बसपा से लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेसी आपस में ही सिर फुटौव्वल करने में लगे थे. जिन नेताओं के कंधों पर जीत की ज़िम्मेदारी थी, वे बयानबाज़ी करके एक-दूसरे से आगे निकलने की गला काट स्पर्धा में जुटे थे. दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए गठित एंटनी कमेटी पार्टी के सभी कमज़ोर पक्ष सबके सामने लेकर आई, लेकिन राहुल गांधी के बारे में उसने चुप्पी साध ली. जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में और उनकी मंशा के अनुरूप लड़ा था. चुनाव के समय ही यह तय हो गया था कि कांग्रेस को हार मिले या जीत, ज़िम्मेदारी राहुल गांधी की होगी. राहुल को काम करने की पूरी छूट दी गई थी. चुनाव में पार्टी की जो हालत हुई, उसके लिए बड़बोले नेताओं को ही नहीं, राहुल गांधी की कमज़ोर रणनीति को भी बराबर का ज़िम्मेदार माना जाना चाहिए. इससे इतर एंटनी कमेटी का कहना है कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जनसंपर्क अभियान और रैलियों के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल पार्टी नेताओं के बयानों ने राहुल के किए-धरे पर पानी फेर दिया. कमेटी प्रियंका की भूमिका पर भी मौन साधे रही, जबकि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही थीं.

एंटनी कमेटी ने कांग्रेस की हार के लिए सांगठनिक कमज़ोरी के अलावा ज़िम्मेदार नेताओं के बड़बोलेपन और टिकट बंटवारे में हुई ग़लती को सबसे बड़ा कारण माना है. एंटनी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल-सोनिया के सघन अभियान के दौरान कांग्रेस को जो सफलता मिली, उसके बाद से प्रदेश में कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर खासी उत्साहित थी, लेकिन चुनाव आने तक जो समीकरण बने, वे सब पार्टी का बंटाधार करने के लिए पर्याप्त थे. टिकट बंटवारे में पार्टी के समर्पित एवं निष्ठावान लोगों से ज़्यादा दलबदलुओं और दागियों को तवज्जो दिया जाना भी नेतृत्व को भारी पड़ा. सारे दिग्गज नेता पार्टी को जिताने के स्थान पर अपने घर-परिवार के लोगों को टिकट दिलाने में लगे रहे. राहुल को छोड़कर प्रदेश के बाक़ी नेता अपने पत्नी-बच्चों को जितवाने में लगे रहे, लेकिन उन्हें वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा. केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, सांसद प्रवीन सिंह ऐरन एवं कमल किशोर की पत्नी और पूर्व अध्यक्ष जगदंबिका पाल के पुत्र भी चुनाव मैदान में थे, सबके सब हार गए. टिकट बंटवारे में जिताऊ-टिकाऊ के नाम पर दलबदलू ही नहीं, जेल में बंद और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग भी कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए. इन सब पर भारी पड़ा दिल्ली से आने वाले नेताओं का बड़बोलापन. राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह चुनाव के दौरान मुस्लिमों को रिझाने के लिए मौलानाओं को कांग्रेस के मंच पर लाने में लगे रहे. चुनाव नतीजे आने से पहले दिग्विजय सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार न बनी तो किसी की भी नहीं बनने देंगे.

केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार न बनी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा. एक अन्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनाव के दौरान ही मजहबी आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कहकर मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे. वैसे एंटनी कमेटी ने हार के जो कारण गिनाए हैं, उनका जिक्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी पहले कर चुकी थीं. उक्त नेताओं द्वारा की गई बयानबाज़ी से होने वाले नुक़सान की आशंका उन्हें पहले से थी. उन्होंने पूरे नतीजे आने से पहले न सिर्फ़ हार की ज़िम्मेदारी ली, बल्कि यहां तक कह दिया कि यदि बड़े नेता बयानबाज़ी करने से बाज आते तो शायद कांग्रेस को यह दिन न देखना पड़ता. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में हार के कई कारण गिनाए गए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसी इन कारणों को नया नहीं मानते. उनका कहना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट एक तरह से राहुल और सोनिया के विचारों को ही आगे बढ़ाती दिखी. आज जो एंटनी कमेटी कह रही है, वही बात सोनिया गांधी ने चुनावी नतीजे आने के बाद कह दी थी. उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रदेश में सांगठनिक कमज़ोरी और प्रत्याशियों के ग़लत चयन के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव से जब एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि रिपोर्ट से जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस को हार से सबक लेकर जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा. लोकसभा चुनाव के लिए समय कम है. सपा और बसपा लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुट गई हैं. सपा ने तो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगने शुरू कर दिए हैं. ■

सोनिया का पुत्र मोह

पुत्र मोह किसी से क्या-क्या नहीं कराता. फिर थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या हर्ज है, वह भी आंकड़ों का जाल बुनकर . एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी का बचाव करते हुए सोनिया गांधी ने पुत्र मोह ही दिखाया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए पार्टी नेताओं की अनुशासनहीनता, गुटबाज़ी और बयानबाज़ी को जिम्मेदार ठहरा दिया तथा राहुल गांधी के माथे पर चुनाव में बढ़े मत प्रतिशत का सेहरा बांध दिया.

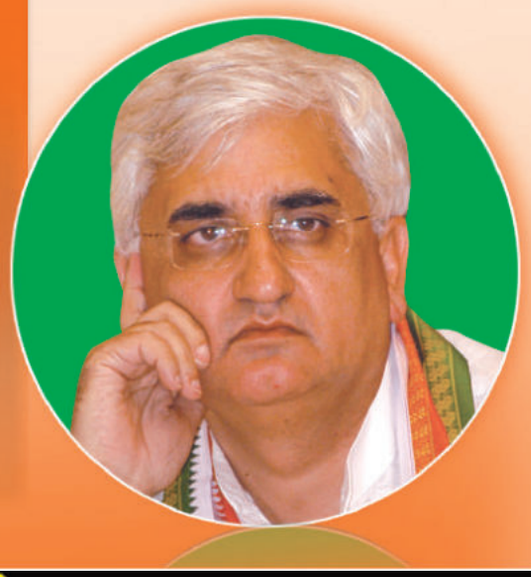

राष्ट्र धर्म पर चिंतन करें

मुझे कई बार ये सुझाव मिले हैं कि सभी धर्मों के लोगों को आंदोलन में साथ लेकर चलना है. मैं इस बात से 100 फ़ीसदी सहमत हूं. आइए आज एक और धर्म की बात करें- राष्ट्र धर्म.

आज की राजनीति धर्मों, जातियों, समाजों पर आधारित है. मैं मुसलमानों का नेता हूं तो मैं मुस्लिम वोट बैंक बनाऊंगा, मैं बनिया समाज से हूं तो मेरा वोट बैंक बनिया है, वग़ैरह-वग़ैरह. इस तर्ज़ पर कई राजनीतिक पार्टियां बन गईं और कई राजनेताओं की रोटी चलती है. मुझे आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं कि कितनी पार्टियों के नाम या संविधान में देश का नहीं, बल्कि धर्मों या समाजों के नाम शामिल हैं. मेरा अनुभव कहता है कि यह राजनीतिक पार्टियां इस धर्म, जाति और समाज के अंतर को कम नहीं करतीं, बल्कि बढ़ाने का काम करती हैं.

क्यों कोई पार्टी राष्ट्र धर्म की बात नहीं करती? इस धर्म का पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है. फिर वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बनिया हो या पंडित. क्या इसलिए कि राष्ट्र धर्म लोगों को बांटता नहीं, बल्कि जोड़ता है? भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ना राष्ट्र धर्म है और शायद इसलिए इस आंदोलन में आपको हर धर्म, जाति और समाज के लोग साथ आते हुए दिखे. अमीरी और ग़रीबी का कोई अंतर नहीं दिखा. समूचा भारत वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ सड़कों पर उतरा.

अब अंग्रेजों से मिली राजनीति के ढर्रे पर सवाल उठाने का वक़्त आ गया है. यह राजनीति सिवाय राजनेताओं के किसी का भला नहीं करती. समाज का तो क़तई नहीं. मैं संसद की इज्ज़त करता हूं, लेकिन इसमें बैठे राजनेताओं और उनकी बंटवारे वाली राजनीति की नहीं. आज की राजनीति बहुत ही संकुचित सोच में चलाई जा रही है, जिसमें देश का तो कोई स्थान ही नहीं है.

आप अपनी प्रतिक्रिया हमें 09718500606 पर फोन करके या पर ई-मेल करके भेज सकते हैं.
इस बार आपके चर्चा समूह में कितने लोग आए, यह आप हमें SMS **करके ज़रूर बताएं.** SMS **करने का वही तरीक़ा है-**DF<space **आपका पिन कोड** <space>
चर्चा समूह में कितने लोग आए. जैसे मान लीजिए, आपका पिन कोड 110001 है और आपके समूह में मान लीजिए, पांच लोग आए तो आप 09212472681 नंबर पर निम्न SMS **करेंगे-**DF **110001 5**

आप इस हफ्ते इस विषय पर चिंतन और चर्चा करें कि कैसे हम राजनीति के परिपेक्ष को नया रूप दे सकते हैं? यह बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं. क्या इसके लिए हम मौजूदा पार्टियों से कोई उम्मीद रख सकते हैं? या हमें आज की राजनीति के नियम बदलने पड़ेंगे? यह चर्चा करते वक़्त अगर आप यह सोचें कि आप सरकार चला रहे हैं तो शायद आपको चर्चा करने में आसानी होगी. याद रखिएगा कि हमें ऐसा प्रारूप तैयार करना है, जिसको किसी अन्ना हजारे या अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत न हो. वह प्रारूप अपने आप ही राष्ट्र धर्म का पालन करने में सक्षम हो.

जयहिंद
अरविंद केजरीवाल

अन्ना की महाराष्ट्र यात्रा का ब्यौरा

दिनांक/वार	ज़िला	कार्यक्रम स्थल	शहर	आयोजक का नाम	फोन नंबर
01/05/ 2012, मंगलवार	अहमद नगर	ह.भ.प.गोंदकर विद्यालय, कणकवडीरोह शिरडी	शिरडी	अशोक सब्बन ॲड. शाम आसावा	9422083206 /9403969920
02/05/ 2012, बुधवार	औरंगाबाद	श्री सरस्वती भवन, शिक्षण संस्था मैदान औरंगपुरा	औरंगाबाद	रामराव बोर्डे	9860206825
03/05/2012, वीरवार	जालना	जालना, स्वामी विवेकानंद मा व कनिष्ठा महा, जि.प. रोड अंबड चौफुली जालना	जालना	प्रा. भगवान दिरंगे	9421653818, 8698616415
04/05/ 2012, शुक्रवार	बीड	सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स, बीड	बीड	ॲड अजित देशमुख	9422744640
05/05/ 2012, शनिवार	उस्मानाबाद	पुष्पक मंगल कार्यालय पटांगण	उस्मानाबाद	बोबडे गुरुजी	9970095523
06/05/ 2012, रविवार	लातुर	टाउन हॉल	लातुर	प्रा. सुधीर देशमुख	9422658463
07/05/ 2012, सोमवार	परभणी	शनिवार बाज़ार मैदान/पाथरी	परभणी	डॉ. विलासमोरे	9881587087
08/05/ 2012, मंगलवार	नांदेड़	नांदेड़, मल्टीपर्पज हाईस्कूल वज़ीराबाद, शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज	नांदेड़	प्रा. बालाजी कॉपलवार	9970033125
09/05/ 2012, बुधवार	हिंगोली	हिंगोली, गांधी चौक, रामलीला मैदान, पुलिस ग्राउंड	हिंगोली	डॉ. अनिल सवनेकर ज्ञानेश्वर धायगुडे	9421385441, 7385215084
10/05/ 2012, वीरवार	वाशिम	शिवाजी चौक	वाशिम	अविनाश पसारकर	9420102557
11/05/ 2012, शुक्रवार	यवतमाल	आज़ाद मैदान	यवतमाल	शैलेश पिसालकर	9422868986
12/05/ 2012, शनिवार	चंद्रपुर	पुलिस फुटबॉल मैदान	चंद्रपुर	अविनाश अबंडेकर	9423619187
13/05/ 2012, रविवार	गडचिरोली	इंदिरा गांधी चौक मैदान	गडचिरोली	चंद्रशेखर भंडारके, डॉ. शिवनाथ कुंभारे	9422152195, 9422154945
14/05/ 2012, सोमवार	गोंदिया	सिंधी शाला मैदान	गोंदिया	सुरेश धुर्वे	9970454300
15/05/ 2012, मंगलवार	भंडारा	दसरा मैदान	भंडारा	शंकरदादा बड़वाईक, प्रभाकर वाड़ीभस्मे	9422833234, 07183233429
16/05/ 2012, बुधवार	नागपुर	नागपुर, चिटणी पार्क/ रेशिम बाग़ मैदान	नागपुर	डॉ. गोपाल बेले	9423683057
17/05/ 2012, वीरवार	वर्धा	न्यू इंगलिश हाई स्कूल मैदान, जेल रोड	वर्धा	संदीप वरू	9923402554
18/05/ 2012, शुक्रवार	अमरावती	हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल मैदान	अमरावती	अनिल ठाकरे	9730004596, 9960313344
19/05/ 2012, शनिवार	अकोला	रूपनाथ महाराज मंदिर मैदान, दहीहाडा	अकोला	गजानन हरणे, गजानन माली	9822942623, 9423160848
20/05/ 2012, रविवार	बुलढाना	कॉटन मार्केट नांदौरा	नांदौरा	प्रा. जयप्रकाश	9850596842
21/05/ 2012, सोमवार	जलगांव	एम.जे. कॉलेज लॉ कॉलेज शेजारी	जलगांव	सुरेश पाटिल	9822485311, 9420658763
22/05/ 2012, मंगलवार	धुले	महाराणा प्रताप चौक	धुले	शशिकांत शर्मा	9421530799
23/05/ 2012, बुधवार	नंदुरबार	सुभाष चौक	नंदुरबार	सदाशिव पाटिल	9422287285
24/05/ 2012, वीरवार	नासिक	बी.डी.भालेकर मैदान कालीदास नाट्यगृहसमोर	नासिक	हेमंत कवडे	9422254776
25/05/ 2012, शुक्रवार	पुणे	बाबा भिंडे पुल, डेक्कन जवल	पुणे	राधेश्याम जगताप	9890541069
26/05/ 2012, शनिवार	सोलापुर	वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान	सोलापुर	बसंतराव आप्टे, अंड गोविंद पाटिल	9657167137, 9822955056
27/05/ 2012, रविवार	सतारा	तालिम संघ मैदान	सतारा	संदीप जगताप	9822394934
28/05/ 2012, सोमवार	सांगली	सांगली	सांगली	प्रा. बालासाहेब हाके	9822394934
29/05/ 2012, मंगलवार	कोल्हापुर	सासणे मैदान, दाभोलकर कॉर्नर जवल	कोल्हापुर	नारायण पोवार	9422428672
30/05/ 2012, बुधवार	सिंधु दुर्ग	कणकवली	सिंधुदुर्ग	जयानंद मठकर	9422078694
31/05/ 2012, वीरवार	रत्नागिरी	रत्नागिरी	रत्नागिरी	युयुत्सु आर्ते	9422351926
01/06/ 2012, शुक्रवार	रायगढ़	रोहा-रायगढ़	रायगढ़	अलाउद्दीन शेख़	9869828040
02/06/ 2012, शनिवार	मुंबई	मुंबई-दादर	मुंबई शहर	भावेस पटेल	932214079
03/06/ 2012, रविवार	दिल्ली	जंतर मंतर, एक दिन का आंदोलन	-	-	-
04/06/ 2012, सोमवार	ठाणे	ठाणे	ठाणे	असलम शेख़	-
05/06/ 2012, मंगलवार	नवी मुंबई	नवी मुंबई	नवी मुंबई	असलम शेख़	-

अन्ना चर्चा समूह से जुड़े सवाल आप हमें *ईमेल: sawal@chauthiduniya.com* पर भेज सकते हैं.

बैंकों द्वारा उधार देने की ब्याज दर क्या होनी चाहिए, यह भी पूंजी बाज़ार पर ही निर्भर है. जब ज़्यादा लोगों को नकद रुपयों की ज़रूरत हो और कम लोगों के पास फालतू रुपये हों तो निश्चय ही ब्याज की दर ऊंची होगी.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

रुपयों के किराए का नियंत्रण

अर्थशास्त्रियों की गणना अजीब है. उनका कल्पनातीत हिसाब है. जमा पूंजी का हिसाब लगाने के उनके तरीक़े को अगर आप ग़ौर से देखें तो यही लगेगा कि ऐसी बातें करने वालों को क्यों न जल्दी से पागलखाने भिजवा दिया जाए. उदाहरण स्वरूप, अगर एक बैंक के पास लोगों के खातों में जमा रुपये, मान लीजिए 5 करोड़ हैं तो वे अर्थशास्त्री कहते हैं कि 5 करोड़ जमा हैं. ऐसा होने से 5 करोड़ उस बैंक की साख बन गए. अतएव 10 करोड़ वह बैंक उधार दे सकता है या रिजर्व फंड रख सकता है. इसी तरह उधार लेने वालों की उधार योग्यता जानने के लिए अर्थशास्त्री कहता है, जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपये उधार लिए, उसने, मान लें, अपनी 10 लाख की संपत्ति बैंक में सिक्युरिटी के समय में जमा कर दी है तो उसकी 5 लाख की उधार योग्यता और समझनी चाहिए. बड़ी ही अजीब पद्धति है यह, हर व्यक्ति या संस्था की उधार योग्यता मापने की.

बैंकों द्वारा उधार देने की ब्याज दर क्या होनी चाहिए, यह भी पूंजी बाज़ार पर ही निर्भर है. जब ज़्यादा लोगों को नकद रुपयों की ज़रूरत हो और कम लोगों के पास फालतू रुपये हों तो निश्चय ही ब्याज की दर ऊंची होगी. इसके विपरीत कम लोगों को नक़द रुपयों की आवश्यकता हो और ज़्यादा लोगों के पास फालतू रुपये हों तो ब्याज की दर कम होगी. यह परिस्थिति मांग और पूर्ति के सिद्धांत से संबंधित है. यों मांग का अर्थ यह नहीं है कि हमेशा ही रुपये की मांग सबको बनी रहती हो.

अर्थशास्त्र में सही माने में मांग का अर्थ है उधार लेने वाले की शक्ति समय पर वापस लौटाने की हो. उसी आवश्यकता को मांग कहते हैं. भारत की अर्थ नीति में आपको

फालतू रुपये की इतनी मांग हो जाएगी कि फ़ौरन रिज़र्व बैंक के डायरेक्टरों की असाधारण सभा बैंक रेट 10 पर्सेंट कर देगी. चूंकि बैंकों में रुपया जमा करने वाले सब लोग बैंकों से निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे. दोपहर के पहले क़रीब-क़रीब सब बैंक रुपये में 25 नए पैसे चुकाने के बाद बोर्ड लगा देंगे कि बाक़ी रुपये उधार पर तथा शेयर सिक्यूरिटी में लगे हुए हैं. वे आशा व्यक्त करेंगे कि अल्प समय में ही रुपये वसूल होते ही वे दे सकेंगे. वे ऋण स्थगन की घोषणा कर देंगे. अगर बैंक रेट 10 प्रतिशत भी कर डालें तो भी रुपया मिलने वाला नहीं.

मालूम ही होगा कि 1947 में भयानक तूफान आया था. उस वक्त के वित्त मंत्री मो. लियाकत अली खान ने वार्षिक बजट में कई ऐसे ही क़ानून बनाए, करों के प्रस्ताव रखे. फलस्वरूप बहुत से लोगों को नकद रुपये की आवश्यकता एक साथ आ पड़ी. लोगों को नकदी के लिए अपनी संपत्ति, जो अधिकतर शेयर या सिक्युरिटी के रूप में थी, बरबस बेचनी पड़ी. जब अधिकांश लोग बेचने लगे तो ख़रीददार कम हो गए और भावों में काफी मंदी का दौर आया. उस वक्त देश का जो आर्थिक ढांचा एक बार बिगड़ा, सरकार के हज़ारों प्रयत्न करने पर भी आज तक 1960 में भी सुधर नहीं पाया. आप पूछेंगे 1 वर्ष के बजट में ऐसी भयानक चीज क्या हो गई, जिससे देश का आर्थिक संतुलन ही बिगड़ गया

ज़रा ग़ौर कीजिए, मान लीजिए, किसी विचित्र महत्वाकांक्षी व्यापारी की सलाह से या किसी क्रांतिकारी मंत्री की कृपा से सरकार ने यह क़ानून बना दिया कि जो संपत्ति कर लगाया गया है, उसकी दर 1 या 2 प्रतिशत से 40 या 50 प्रतिशत कर देंगे, साथ ही यह भी कह दिया कि हर व्यक्ति पर संपत्ति कर के साथ-साथ खास टैक्स यानी आपको कितना रुपया उधार मिल सकता है, उस पर भी उसी अनुपात से यानी 40 से 50 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. परिणाम होगा, हर आदमी अपना टैक्स अदा करने के लिए नकद रुपये की व्यवस्था करने के लिए दौड़ पड़ेगा. सब लोग बैंकों से अपनी कुल जमा रकम निकाल लेंगे और जितनी ज़्यादा रकम उधार मिलेगी, लेने की कोशिश करेंगे. पर चूंकि जमा वाले सब अपनी जमा पूंजी वापस ले लेंगे तो बैंकों के पास किराए पर देने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं. तमाम लोग अपने-अपने शेयर और सिक्युरिटी बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ़ दौड़ेंगे.

फालतू रुपये की इतनी मांग हो जाएगी कि फ़ौरन रिज़र्व बैंक के डायरेक्टरों की असाधारण सभा बैंक रेट 10 पर्सेंट कर देगी. चूंकि बैंकों में रुपया जमा करने वाले सब लोग बैंकों से निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे. दोपहर के पहले क़रीब-क़रीब सब बैंक रुपये में 25 नए पैसे चुकाने के बाद बोर्ड लगा देंगे कि बाक़ी रुपये उधार पर तथा शेयर सिक्यूरिटी में लगे हुए हैं. वे आशा व्यक्त करेंगे कि अल्प समय में ही रुपये वसूल होते ही वे दे सकेंगे. वे ऋण स्थगन की घोषणा कर देंगे. अगर बैंक रेट 10 प्रतिशत भी कर डालें तो भी रुपया मिलने वाला नहीं. तमाम लोग अपने-अपने शेयर और सिक्युरिटी बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ़ दौड़ेंगे.

फालतू रुपये की इतनी मांग हो जाएगी कि फ़ौरन रिज़र्व बैंक के डायरेक्टरों की असाधारण सभा बैंक रेट 10 पर्सेंट कर देगी. चूंकि बैंकों में रुपया जमा करने वाले सब लोग बैंकों से निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे. दोपहर के पहले क़रीब-क़रीब सब बैंक रुपये में 25 नए पैसे चुकाने के बाद बोर्ड लगा देंगे कि बाक़ी रुपये उधार पर तथा शेयर सिक्यूरिटी में लगे हुए हैं. वे आशा व्यक्त करेंगे कि अल्प समय में ही रुपये वसूल होते ही वे दे सकेंगे. वे ऋण स्थगन की घोषणा कर देंगे. अगर बैंक रेट 10 प्रतिशत भी कर डालें तो भी रुपया मिलने वाला नहीं. टैक्स चुकाने के लिए लोग कहें कि कि यह बंडल शेयरों का है, आप ले लीजिए. टैक्स के लाखों- करोड़ों रुपये देने हैं, पर हज़ारों रुपये भी उन शेयरों के बंडल के काग़ज़ों पर कोई नहीं देगा, क्योंकि सब बेचू ही बेचू हैं तो लेने वाला कौन होगा? तथाकथित समाजवादी विचार वाले एक वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ऐसा होता है तो होने दो. जब भारत की 99 फ़ीसदी आबादी पहले से ही ऐसी दुर्दशा में है तो 1 फ़ीसदी को भी ऐसा भुगतना पड़े तो क्या हर्ज है? समझ में यह नहीं आया कि इससे देश की आर्थिक नीति को क्या फ़ायदा हुआ? गुस्से में आकर यह धमकी दे दी गई कि साल में एक ही बार नहीं, बल्कि अनेक बार नए-नए टैक्सों के प्रस्ताव लेकर वह संसद के सम्मुख आएंगे. इसी मनोवृत्ति को अगर उसकी तार्किक परिणति तक ले जाया जाए तो परिणाम होगा कि किसी के पास रोकड़ा रुपया होगा ही नहीं. शाम को खाने के लिए अन्न या पीने के लिए चाय भी कोई जुटा नहीं पाएगा. भारी उपद्रव होंगे और जब सारी प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगेगी तो सब यही प्रार्थना करेंगे कि कोई हिटलर, मुसोलिनी या नेपोलियन जैसा तानाशाह आकर हमें इस कष्ट से बचाए और शासन का स्वरूप सुधार कर हमारा उद्धार करे.

कहने का तात्पर्य यही है कि जब देश की आर्थिक नीति इस तरह से अदूरदर्शियों के हाथ में खिलवाड़ बन जाती है तो वे उसका इतना सत्यानाश कर डालते हैं कि शायद उससे छुटकारा पाने के लिए अंतिम मार्ग वही तानाशाही का ही रह जाता है. प्रजातंत्र को ताक पर रख देना पड़ता है, क्योंकि वर्ग युद्ध होने लगता है, जिसकी वजह से सारे बैंकों को फेल कराना, सब शेयर बाज़ारों को ताला लगवाना इत्यादि अनहोने काम हो जाते हैं. संसार में ऐसी घटनाएं अनेक देशों में कई बार हुई हैं. इतिहास साक्षी है कि जहां- जहां इस तरह विचार मूढ़ों ने यह किया, वहां-वहां अर्थ तंत्र का सर्वनाश ही हो गया.■

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

ग्रामीण विकास और महिला जनप्रतिनिधि

अशोक सिंह
feedback@chauthiduniya.com

एक बार फिर हमेशा की तरह महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा बिल ठंडे बस्ते में रहा. सरकार भी आम सहमति बनाने के मूड में नज़र नहीं आई. सभी राजनीतिक दल एक सुर में महिला अधिकारों की बात करते हैं, परंतु बिल पारित कराने के विषय पर बंटे नज़र आते हैं. कुछ राजनीतिक दल आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वह इस दिशा में कोई ठोस पहल करे और एक ऐसा बिल प्रस्तुत करे, जो सर्वमान्य हो. सबसे अधिक आश्चर्य उन महिला जनप्रतिनिधियों के रुख़ पर होता है, जो इसके समर्थन में आवाज़ बुलंद करने की बजाय पार्टी की विचारधारा का समर्थन करती नज़र आती हैं. देश के विकास में समान भागीदारी के लिए संसद में भले ही महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, परंतु ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में यह व्यवस्था की गई है. बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत में आ रही हैं. झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में भी बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि निकल कर सामने आई हैं, विशेषकर दलित एवं आदिवासी समुदाय की महिलाओं की संख्या उत्साहजनक रही है. आरक्षण प्रदान करने के पीछे मूल भावना यह है कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार हो.

पंचायतों को महिलाओं के लिए एक सशक्त माध्यम बनाने की जो कल्पना की गई थी, वह शायद अब तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है. यह एक बहुत अहम प्रश्न है कि पंचायतों में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार सशक्त होनी चाहिए? महिलाएं आज प्रधान, उप प्रधान, पंच, सदस्य, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पंचायत समिति और ज़िला पार्षद यानी सभी पदों पर चुनी जा रही हैं, परंतु इसके बावजूद उनके कार्यक्षेत्र में कोई विशेष प्रगति होती नहीं दिख रही है. इस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है. इन खामियों को खोजने और दूर करने की ज़रूरत है. पंचायत एवं समाज को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि वे महज़ चुनी गई गुड़िया नहीं हैं कि उनके सारे काम पुरुष करेंगे और वे केवल हस्ताक्षर करेंगी, बल्कि उन्हें लोगों के साथ विश्वास एवं सम्मान का एक रिश्ता कायम करना है. महिला जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यक्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण

अपनाने की आवश्यकता है. वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक शख्स को आदर-सम्मान के साथ सुनें और उनकी परेशानियों का निदान खोजें. उनका लक्ष्य पूरे क्षेत्र का समेकित विकास होना चाहिए. अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बनाना और महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य महिला संगठनों को सशक्त करने के साथ-साथ उन्हें गतिशील बनाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए. वे जब भी कुछ कहें तो उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण झलके. इससे न केवल वे अपनी बात समझाने और मनवाने में कामयाब होंगी, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा भी बढ़ेगी.

महिलाओं को अपनी भूमिका के निर्वाह हेतु इन तीन चीजों पर ध्यान देना ज़रूरी है, स्वयं की क्षमता, पुरुषों एवं समाज का सहयोग, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच तालमेल और महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि. इसके लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम है. वास्तविकता यह है कि आज भी पंचायतों में महिलाएं इतनी सशक्त और सक्रिय नहीं हैं. 73वें संविधान संशोधन ने उन्हें आगे आने, नेतृत्व एवं अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने का मौक़ा प्रदान किया है. पंचायत में प्रधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. एक महिला प्रधान की भूमिका तो और भी ज़िम्मेदारी भरी और चुनौतीपूर्ण होती है. महिला प्रतिनिधियों को पंचायत की बैठक में नियमित एवं सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. महिला प्रतिनिधि अन्य महिला ग्रामसभा सदस्यों का सहयोग लेकर पंचायत के विकास के लिए फ़ैसले ले सकती हैं. महिला प्रतिनिधि महिलाओं की समस्याओं को ठीक से समझ सकती हैं, साथ ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने की दिशा में पहल कर सकती हैं. इसके लिए गांव में सक्रिय महिला मंडलों एवं स्वयं सहायता समूहों से नियमित सहयोग लेने की ज़रूरत है. अगर पंचायत की बैठक में कोई महिला समस्या लेकर आती है तो उसे ध्यानपूर्वक सुनें और संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करें. प्रखंड विकास कार्यालय या अन्य सरकारी विभाग में जाना पड़े तो अपने अन्य सहयोगियों, खासकर महिला प्रतिनिधियों एवं महिला मंडलों का सहयोग लें.

किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो. अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उसे सारे नियम-अधिनियम पढ़ने चाहिए, विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए और उनका आदान-प्रदान करना चाहिए. समय-समय पर पंचायत सचिव एवं अन्य बुद्धिजीवियों से सलाह-मशविरा भी करना चाहिए. वे ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता-संचालन स्वयं करें. जाति, धर्म, वर्ण, लिंग एवं क्षेत्रवाद आदि से ऊपर उठकर गांव और पंचायत के विकास पर जोर देना चाहिए. गांव वालों को सबसे अधिक आशा सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता से होती है. महिला जनप्रतिनिधियों को लाभार्थियों का चयन दबाव-भेदभाव से परे हटकर करना चाहिए. पंचायत के विकास कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त भूमिका निभाने की ज़रूरत है. सामाजिक कुरीतियों जैसे शराब, दहेज, पर्दा एवं शोषण आदि को ख़त्म करने में महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका न सिर्फ़ पंचायत, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकती है. (चरखा) ■

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

जल संरक्षण बहुत ज़रूरी

हर साल गर्मियों के मौसम में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है. इससे निपटने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपये ख़र्च करती है. इसके बावजूद समस्या ज्यों की त्यों रहती है. देखने में यह भी आता है कि एक तरफ़ किसी एक इलाक़े में लोग अपनी गाड़ियां धोने में ख़ूब पानी बहा रहे हैं, उसी शहर में दूसरे इलाक़े के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं. पानी की यह बर्बादी रोकनी होगी. इसके लिए ज़रूरी है कि लोग जल संरक्षण के महत्व को समझें. जल संरक्षण से हम काफ़ी हद तक जल संकट पर क़ाबू पा सकते हैं. लोगों को व्यर्थ पानी बहाते वक़्त यह सोचना चाहिए कि यह पानी किसी का गला तर कर सकता है. इसलिए इसे व्यर्थ न बहाएं और जल बचाएं.

-बॉबी, *जयपुर, राजस्थान.*

रैगिंग पर अंकुश लगे

देश में रैगिंग के नाम पर छात्र-छात्राओं के साथ अमानवीय या अश्लील व्यवहार करना आम बात हो चुकी है. अदालत के सख्त आदेश के बावजूद कॉलेजों का प्रबंध तंत्र अभी तक रैगिंग पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सके हैं. जब कोई छात्र नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश करता है तो उसकी आंखों में अनेक सपने होते हैं. नए शिक्षण संस्थान को लेकर एक अलग तरह का उत्साह होता है, लेकिन जब पहले ही दिन उसके वरिष्ठ उसके साथ ग़लत बर्ताव करते हैं तो वह टूट जाता है. ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब रैगिंग के नाम पर छात्र की हत्या कर दी गई या उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली. कॉलेज प्रशासन को रैगिंग से निपटने के लिए सख्त क़दम उठाने चाहिए.

-**सरफ़राज़ ख़ान,** *हिसार, हरियाणा.*

सरकार ध्यान दे

कहते हैं कि अच्छा कार्य चाहे कोई भी दल या संस्था करे, महज़ विरोध के लिए उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के कारण तहसील और थाना दिवसों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो आज भी जारी है. सभी लोग अपने कार्य के लिए लखनऊ आने-जाने का व्यय वहन करने में सक्षम नहीं हैं. लखनऊ में शुरू होने वाले दरबार में एकत्रित भीड़ यह साबित करती है कि ज़िला और मंडल स्तर के अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं. सरकार को चाहिए कि वह निचले स्तर पर भी दरबारों का आयोजन करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

-**शिवकुमार फ़ैज़ाबादी,** *फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

वोट की शक्ति का सही इस्तेमाल हो

अगर हमारी संसद के सदस्य अपराधी हैं तो इसके लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन्हें चुनकर संसद में भेजते हैं. हमें मालूम होता है कि वे किस प्रवृत्ति के लोग हैं. राजनीतिक दल उन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम आंख मूंदकर उनके नाम पर मुहर लगा देते हैं. देश में अनेक समस्याएं हैं. सभी लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. हम ऐसे सांसदों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो ख़ुद भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त बताए जाते हैं. क्या हम ऐसे लोग चुन पाएंगे, जो ईमानदार हों और जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर हों. वोट की शक्ति हमारे पास है, हमें केवल उसका सही इस्तेमाल करना होगा.

-**रंजन कुमार सिंह राजपूत,** *पटना, बिहार.*

पत्रकारिता आज भी ज़िंदा है

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-साज़िश का पर्दाफ़ाश और देशद्रोहियों के चेहरों से नक़ाब हटाइए पढ़कर यही कह सकता हूं कि देश में पत्रकारिता आज भी ज़िंदा है. आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब सेना और उसके उच्च पदस्थ लोगों को लेकर एक के बाद एक, इतने सारे विवाद सामने आए हैं. पहले उम्र विवाद, फिर पत्र लीक मामला और फिर सेना के विद्रोह की ख़बरें. सेना को लेकर शंका का वातावरण भी पैदा हो गया. सेना के लिए सामान ख़रीदने में घोटालों का क्रम बदस्तूर जारी है. इस पर अंकुश लगना चाहिए.

-विभा झा, *सरस्वती गार्डन, नई दिल्ली.*

मेरा भारत महान

मेरा भारत महान या महान बनाने की कोशिश? शायद इस सवाल का जवाब कोई दे पाए. एक ओर देश के लिए लड़ते अन्ना हजारे तो दूसरी ओर समोसे-टिक्की खिलाकर अपने भक्तों का इलाज करते निर्मल बाबा हैं. एक ओर हम खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुपोषण के मामले में भारत आगे है. एक ओर पंजाब के मुख्यमंत्री के हत्यारे की फांसी रुकवाने के लिए देश भर में आंदोलन हो रहे हैं तो दूसरी ओर कसाब के मामले में सब मौन हैं. क्या सचमुच यह वही भारत है, जिसे महात्मा गांधी जैसे देशभक्तों ने महान बनाया था.

-रुचिन भाटिया, *करनाल, हरियाणा.*

अंत में

कभी जीत कभी हार से डर लगता है
ऐ वक़्त तेरी रफ्तार से डर लगता है
तेरी सूरत से नहीं हमें कोई ख़ौफ़
ऐ आदमी तेरे किरदार से डर लगता है.

-शिबली रामपुरी, *सहारनपुर, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

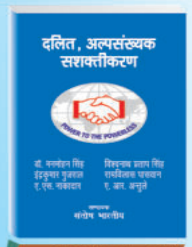

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448 राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

इस सच को कहने की हिम्मत कौन करेगा?

चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हार के कारणों की तलाश में की गई कोशिश और उसका क्या परिणाम निकला, यह जानना ज़रूरी है. पहले चुनावों में हार की वजह तलाशने और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए पार्टी की समीक्षा बैठकें हुआ करती थीं. अब इन बैठकों का चलन बंद हो गया है. अब पार्टी एक कमेटी बनाती है, जिसमें 3 या 4 सदस्य होते हैं और उन्हें यह ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वे पार्टी की हार के कारणों का पता लगाएं. कमेटी कई बैठकें करती है और एक रिपोर्ट दे देती है. उस रिपोर्ट पर न पार्टी के भीतर बातचीत होती है और न पार्टी के बाहर. यह राजनीतिक दलों के सिकुड़ते जाने का एक प्रमाण है. कम से कम दो पार्टियों के बारे में तो हमेशा बात होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां दो गठबंधनों की अगुवा पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की और कांग्रेस यूपीए की.

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी, यह जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य शीला दीक्षित, सुशील कुमार शिंदे एवं ए के एंटनी थे. ए के एंटनी इस कमेटी के संयोजक थे, इसलिए इसे एंटनी कमेटी का नाम दिया गया. इस कमेटी ने कितनी बैठकें कीं, कितने लोगों से बातचीत की, नहीं पता. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की या नहीं, नहीं पता. इस कमेटी ने एक रिपोर्ट लिखी, जिसने न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंतित किया, न कांग्रेस अध्यक्ष को चिंतित किया और न प्रधानमंत्री को. इस रिपोर्ट ने कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया, जैसे सांगठनिक कमज़ोरी, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कांग्रेसी नेताओं की आपसी गुटबाज़ी, नेताओं का बड़बोलापन, नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देना, प्रत्याशी चयन की ग़लत प्रक्रिया, बाटला हाउस एवं मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे उठाने का ग़लत असर और पार्टी में अनुशासनहीनता. इसके अलावा दो और छोटे कारण इस कमेटी ने बताए. जैसे पर्सेप्शन ऑफ करप्शन. मतलब भ्रष्टाचार कांग्रेस की वजह से है, इसका प्रचार और महंगाई.

इन सारे कारणों को देखें और इस कमेटी की रिपोर्ट की भाषा को देखें तो पाएंगे कि जैसे कांग्रेस संगठन कांग्रेस कार्यकर्ता चला रहे हैं, न कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह. ये दोनों बेचारे हैं, क्योंकि जितने कारण दिए गए, उनका ज़िम्मा एक तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही थोप दिया गया. संगठन कमज़ोर है तो कार्यकर्ताओं की ग़लती, नेता बड़बोलापन कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी, प्रत्याशी चुने गए तो कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी. सवाल यह है कि इस कमेटी ने इन सारी चीज़ों या सारे कारणों के ज़िम्मेदार लोगों के नाम क्यों नहीं दिए या ज़िम्मेदारी क्यों नहीं तय की.

हम जब बाहर से देखते हैं और हमें देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं हैं. ये इस देश में लोकतंत्र को चलाने वाले दो मुख्य हथियार हैं. अगर इन दोनों हथियारों में गड़बड़ी आती है तो देश के लोकतंत्र के ऊपर इसका सीधा असर होता है. इसलिए हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि एंटनी कमेटी ने जितने कारण गिनाए हैं, उनके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है या इस हार की ज़िम्मेदारी तय होती है तो वह सीधी-सीधी सोनिया गांधी की ज़िम्मेदारी है, उनकी कोर कमेटी की ज़िम्मेदारी है, उनके महामंत्रियों की ज़िम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूल्हे, चुनाव प्रचार के दूल्हे राहुल गांधी की ज़िम्मेदारी है. इन्हीं लोगों की वजह से संगठन कमज़ोर है, इन्हीं लोगों की वजह से नेताओं में गुटबाज़ी चल रही है, इन्हीं के अनदेखेपन की वजह से नेताओं ने बड़बोलापन किया, नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट इनकी आंख और नाक के नीचे जानते-बूझते दिए गए. प्रत्याशियों के चयन का सिस्टम राहुल गांधी और उनके परम सखा कनिष्क सिंह ने तय किया. फ्रंट में दिग्विजय सिंह एवं परवेज हाशमी को रखा गया. इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल बोरा! इन सभी के रहते पार्टी में अनुशासनहीनता कैसे बढ़ गई, कौन ज़िम्मेदार है? अगर माना जाए तो ये सभी ज़िम्मेदार हैं. उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने इनकी महान बुद्धि और महानतम समझ का फ़ायदा उठाया है.

जिस एक बात को यहां रेखांकित करना चाहिए, वह यह है कि हमारे देश में जब पार्टी होती है तो पार्टी प्रमुख नहीं होती, सरकार प्रमुख हो जाती है. सरकार जो करती है, उसका फ़ायदा या नुक़सान पार्टी को मिलता है. देश या उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का फ़ायदा या ख़ामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है.

जिस एक बात को यहां रेखांकित करना चाहिए, वह यह है कि हमारे देश में सरकार में जब पार्टी होती है तो पार्टी प्रमुख नहीं होती, सरकार प्रमुख हो जाती है. सरकार जो करती है, उसका फ़ायदा या नुक़सान पार्टी को मिलता है. देश या उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के क्रियाकलापों, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का फ़ायदा या ख़ामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है. हार का अगर कोई और बड़ा कारण है तो वह यह है कि लोगों का यह मान लेना कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकती, बल्कि वह भ्रष्टाचारियों को बचाने का रास्ता तलाशती है, जिसे एंटनी कमेटी ने पर्सेप्शन ऑफ करप्शन कहा. देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी है. ये दोनों चीज़ें सोनिया गांधी से कम और मनमोहन सिंह से ज़्यादा जुड़ी हैं. पर्सेप्शन ऑफ करप्शन के लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो मनमोहन सिंह हैं और प्राइस राइज का भी अगर कोई ज़िम्मेदार है तो मनमोहन सिंह हैं.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में कई प्रधानमंत्री हैं. मनमोहन सिंह जी के पास समय नहीं है कि वह उन प्रधानमंत्रियों से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं. ये प्रधानमंत्री अपने-अपने मंत्रालयों में मनमाने फ़ैसले लेते हैं. कोई कॉर्डिनेशन नहीं है और कॉर्डिनेशन न होने का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को मिलता है, जो ऑर्गनाइज्ड या सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार के एक्सपर्ट हैं. इसलिए जो भ्रष्टाचार पहले व्यक्तिगत हुआ करता था या व्यक्तिगत आधार पर होकर कुछ लाख या कुछ करोड़ में बंधकर रह जाता था, अब वह लाखों करोड़ में पहुंच चुका है, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने मनमोहन सिंह की अगुवाई में भ्रष्टाचार को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में बदल दिया है. इसलिए महंगाई बढ़ रही है और महंगाई जानबूझ कर बढ़ाई जा रही है. दुनिया में यह चीज़ महंगी है, दुनिया में वह चीज़ महंगी है, दुनिया में ऐसा है, दुनिया में वैसा है, कहकर देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है.

हमने कई बार आंकड़े दिए और रिपोर्ट छापी कि यह ग़लत है, लेकिन उस ग़लत को सही साबित करने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है. अफसोस इस बात का है कि इस कांग्रेस पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है, जो हिम्मत करके यह कह सके कि इन कारणों को, जिन्हें एंटनी कमेटी ने शीला दीक्षित और सुशील कुमार शिंदे के साथ मिलकर रेखांकित किया है और पहचान की है, उनके लिए किसे ज़िम्मेदार माना जाए. यह मांग कांग्रेस के भीतर उठाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है. 125 साल पुरानी कांग्रेस, जो अपने सीने पर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे शानदार तमगे लगाए हुए है, उसमें आज एक भी ऐसा आदमी नहीं है, जो यह सवाल उठाए कि अगर कारण ये हैं तो इनका ज़िम्मेदार कौन है. न कोई यह कहने की हिम्मत रखता है कि पर्सेप्शन ऑफ करप्शन और प्राइस राइज की ज़िम्मेदार तो सरकार है. सरकार ने क्यों इस मामले पर इतनी ढील दे रखी है या क्यों पर्सेप्शन ऑफ करप्शन और प्राइस राइज के साथ खड़ी दिखाई दे रही है. अगर कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठाने वाला कोई नहीं है तो इस तरह की कमेटियां सिवाय बुद्धि विलास के और कुछ नहीं हैं.

भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ऐसी ही बातें कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी लगभग हर जगह असफल हुए हैं, लेकिन वह दूसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए जोड़-तोड़ बैठा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में वह क्यों सिमट गए, इसके बारे में वह बात नहीं करना चाहते हैं. शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करना चाहता. भारतीय जनता पार्टी भी उसी अवसाद का, उसी रोग का शिकार है, जिसकी शिकार कांग्रेस पार्टी है. अब भारतीय जनता पार्टी में तब तक कोई चेतना नहीं आएगी, जब तक लालकृष्ण आडवाणी अपने गुस्से का इज़हार सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे. अफसोस इस बात का है कि हार के कारण सबको पता हैं, आईडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन उन कारणों को दूर करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया जाता. हम जनता को एक और नए भ्रम में पड़ते हुए देखते रहते हैं. ■

संपादक

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

हमारे सांसदों को इतनी इज़्ज़त क्यों चाहिए

बीते एक मई को द डेली मेल के एक पत्रकार क्वेनटीन लेट्स ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के स्पीकर के बारे में एक टिप्पणी की. उन्होंने स्पीकर बेरकाऊ की तुलना एक कार्टून करेक्टर मटले सी की, जो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता था, जिसके कारण वह कभी सफल नहीं हो पाता था. इसी तरह कुछ साल पहले मैथ्यू पेरिस ने द टाइम्स में पार्लियामेंट्री स्केच नामक कॉलम शुरू किया था. वह स्वयं भी सांसद रह चुके थे. वह अपने सहयोगी रहे सांसदों के ऊपर तीखी टिप्पणी करते थे. उनकी इस विधा ने उन्हें पाठकों का लाडला बना दिया. मैथ्यू को पाठकों ने खूब पसंद किया. बाद में इसका प्रचलन हो गया. संसद की बैठक होती थी और लंदन के प्रमुख अख़बार में उसका मजाक उड़ाया जाता था. इसके बावजूद ब्रिटिश संसद के किसी सदस्य ने शायद ही इस अख़बार के ख़िलाफ़ कोई अभियान चलाया. जबकि हर दिन उनकी एक तरह से बेइज़्ज़ती की जाती थी. ब्रिटिश समाचारपत्र अपने सांसदों को एक तरह के हिंसक व्यक्ति की तरह देखते थे. इन अख़बारों ने ही सांसदों के ख़र्चों में हुई गड़बड़ी का पर्दाफ़ाश किया था और इसके कारण कुछ सांसदों को जेल जाना पड़ा था. कमोबेश ऐसा ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सांसदों के साथ भी होता था, लेकिन ब्रिटेन के लोकतंत्र में सांसदों को आवश्यकता से अधिक इज़्ज़त नहीं दी जाती है. यही वहां के लोकतंत्र की विशेषता है.

अब भारत की बात करते हैं. यहां के सांसद इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं. वे इससे सहमत नहीं कि कोई उनकी बुराई करे और वे चुप बैठे रहें. इसे बाबा रामदेव या टीम अन्ना द्वारा सांसदों के ऊपर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन जन प्रतिनिधियों को बहुत अधिक इज़्ज़त देना अच्छा नहीं होता है. भारतीय मीडिया सांसदों एवं विधायकों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, इसलिए शायद ही उनके ऊपर टिप्पणी करता है. ब्रिटिश हास्य पत्रिका प्राइवेट आई ने तो यहां तक कहा था कि उसके सांसदों की सांस में बदबू होती है, क्योंकि वे शराब बहुत पीते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि हमने अपने सांसदों एवं विधायकों को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है. यह विचार कि सांसद लोग आलोचना से परे हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह तो सामंती मानसिकता का द्योतक है. लोकतंत्र अपनाने के पैंसठ सालों बाद भी हमारी मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं हो पाई है, बल्कि सामंती ही रही है. यह अफ़सोस की बात है. हमारे सांसद और विधायक जब चुनकर आते हैं तो उनकी सोच यही होती है कि वे अब सामान्य लोग नहीं हैं. वे अपने आपको लोकतंत्र का राजकुमार/राजकुमारी समझने लगते हैं. हालांकि उनके प्रतिदिन के कार्यकलापों से यही लगता है कि वे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में ख़ुद ही नाकाम रहे हैं. भारतीय सांसद जिस तरह का व्यवहार सदन में करते हैं, उससे कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सांसदों का व्यवहार हमारे सांसदों से काफ़ी अच्छा होता है. ब्रिटिश सांसद कम से कम संसद के वेल में नहीं जाते, वे दूसरे सांसदों को बोलने का मौक़ा देते हैं और बीच में चीखते-चिल्लाते नहीं हैं. शायद ही किसी सांसद को उसके इस तरह के व्यवहार के लिए सज़ा होती हो.

भारतीय मीडिया सांसदों एवं विधायकों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, इसलिए शायद ही उनके ऊपर टिप्पणी करता है. ब्रिटिश हास्य पत्रिका प्राइवेट आई ने तो यहां तक कहा था कि उसके सांसदों की सांस में बदबू होती है, क्योंकि वे शराब बहुत पीते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि हमने अपने सांसदों एवं विधायकों को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है. यह विचार कि सांसद लोग आलोचना से परे हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह तो सामंती मानसिकता का द्योतक है.

हमारे यहां जब भी कोई बोलना शुरू करता है तो बीच में चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष बैठ जाइए, बैठ जाइए बोलती रहती हैं. उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है और वह कुछ नहीं कर पाती हैं. अगर सर्वे कराया जाए, जहां लोगों को अपनी बात कहने का मौक़ा मिल सके तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोगों के दिलों में अपने प्रतिनिधियों के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है. मुझे तो इस बात में भी संदेह है कि दस प्रतिशत मतदाता भी नेताओं की इज़्ज़त करते हैं. लोग अपने नेताओं का समर्थन ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका कारण भारतीय राजनीति की प्रकृति है, जिसे सही मायने में लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता है. भारत के लोग अपने अधिकारों या फिर जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उसकी शिकायत तक नहीं करते हैं. भारतीय राजनीति क्लाइंटलिस्ट हो गई है. यहां मतदाता अपने को क्लाइंट समझते हैं और अपने मत के बदले नेताओं से उसका मूल्य वसूलते हैं. नेता भी मत ख़रीद कर खुश हो जाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं. नेता लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र को अपना राज्य समझते हैं, जहां के वे राजा/रानी होते हैं तथा मतदाता उनकी प्रजा, जिसे उनके मत का मूल्य चुनाव के समय दे दिया जाता है.

लेकिन, अब ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चलने वाला है. परिवर्तन की बयार बहनी शुरू हो गई है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनकी निर्भरता उनके सांसद पर नहीं है. इनमें अधिकांश शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं. आरटीआई ने पहले ही लोगों को उनके जन प्रतिनिधियों का असली चेहरा दिखाने का मार्ग दिखा दिया है. जिस किसी के पास मोडेम मोबाइल है, फोटो ले सकता है और उसे टीवी चैनल पर अपलोड कर सकता है. प्रतिदिन होने वाले अपराधों को अब पहले से ज़्यादा दिखाया जा सकता है. भारतीय युवा अपने नेताओं की हक़ीक़त दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोकसभा में इस पर सेंसर लगाने के लिए बिल लाया जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

आर्थिक तंगी से आजिज आकर डेनियल ने उन पैसों को फोन बॉक्स में फेंक दिया और पहाड़ों के बीच बिना पैसे वाली अर्थव्यवस्था में जीने का फ़ैसला किया.

मनरेगा का हिसाब-किताब कैसे लें

नरेगा अब मनरेगा ज़रूर हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है. गांव के ग़रीबों–मजदूरों के लिए यह योजना एक तरह से संजीवनी का काम कर रही है. सरकार हर साल लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है, लेकिन देश के कमोबेश सभी हिस्सों से यह ख़बर आती रहती है कि कहीं फर्जी मस्टर रोल बना दिया गया तो कहीं मृत आदमी के नाम पर सरपंच–ठेकेदारों ने पैसा उठा लिया. साल में 100 दिनों की जगह कभी–कभी सिर्फ़ 70–80 दिन ही काम दिया जाता है. काम के बदले पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता. ज़ाहिर है, यह पैसा उन ग़रीबों के हिस्से का होता है, जिनके लिए यह योजना बनाई गई है. मनरेगा में भ्रष्टाचार का सोशल ऑडिट कराने की योजना का भी पंचायतों एवं ठेकेदारों द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया जाता है. कभी–कभी तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है, हत्या तक हो जाती है. अब सवाल यह है कि इस भ्रष्टाचार का मुक़ाबला कैसे किया जाए? इसका जवाब बहुत आसान है. इस समस्या से लड़ने का हथियार भी बहुत कारगर है, सूचना का अधिकार. आपको केवल अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना है. इस बार का आवेदन मनरेगा से संबंधित है. यह आवेदन इस योजना में हो रही धांधली सामने लाने और जॉब कार्ड बनवाने में मददगार साबित हो सकता है. हम पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि वे गांव–देहात में रहने वाले लोगों को भी इस कॉलम के बारे में बताएंगे और दिए गए आवेदन के प्रारूप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे. सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़ने की चौथी दुनिया की मुहिम में आपका साथ भी मायने रखता है. यहां हम मनरेगा योजना से जुड़े कुछ सवाल आवेदन के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं. आप इस आवेदन के माध्यम से मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड, मस्टर रोल, भुगतान, काम एवं ठेकेदार के बारे में सूचनाएं मांग सकते हैं. चौथी दुनिया आपको इस कॉलम के माध्यम से वह ताक़त दे रहा है, जिसके माध्यम से आप पूछ सकेंगे सही सवाल. एक सही सवाल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. हम आपको हर अंक में बता रहे हैं कि कैसे सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हैं घूस को घूंसा. किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी होने पर हम आपके साथ हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का स्वरूप

(मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, रोज़गार एवं बेरोज़गारी भत्ते का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.....ब्लॉक के ग्राम.....के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत जॉब कार्ड बनाने केलिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन संख्या.
ग. आवेदन की तारीख.
घ. आवेदन पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण (जॉब कार्ड बना/जॉब कार्ड नहीं बना /विचाराधीन).
ड. यदि जॉब कार्ड नहीं बना तो उसका कारण बताएं.
च. यदि बना तो किस तारीख़ को.
2. जिन लोगों को जॉब कार्ड दिए गए हैं, उनमें से कितने लोगों ने काम के लिए आवेदन किया है, उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन करने की तारीख़.
ग. दिए गए कार्य का नाम.
घ. कार्य दिए जाने की तारीख़.
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि एवं भुगतान की तारीख़
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज है.
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?
3. उपरोक्त गांव से एनआरईजीए के तहत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया अथवा दिया जा रहा है, उनकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:-
क. आवेदक का नाम एवं पता.
ख. आवेदन करने की तारीख़.
ग. बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की तारीख़.
ड. बेरोजगारी भत्ता के लिए भुगतान की गई राशि एवं भुगतान की तारीख़.
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां भुगतान से संबंधित विवरण दर्ज है.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं
अथवा
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

ज़रा हट के

कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं

आजकल लोग पैसे के लिए क्या-क्या नहीं करते. कहा भी जाता है कि बाप बड़ा न भैय्या, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन एक शख़्स ऐसा भी है, जिसे पिछले कई सालों से पैसे की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. इस शख़्स का नाम है डेनियल सुएलो. 51 वर्षीय डेनियल पिछले 12 सालों से बिना पैसों के रह रहा है. उसने पहाड़ों के बीच एक गुफा को ही अपना घर बना लिया है और पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हो चुका है. गुफा में ही उसने कुछ ज़रूरी सामान रख लिए हैं. वह किसी से कोई सहायता नहीं लेना चाहता. पहाड़ों के बीच जो भी खाने-पीने लायक चीज मिलती है, उसे खा लेता है. झील या झरने के पानी को पीने और बाक़ी काम के लिए इस्तेमाल करता है. अगर कोई उसके साथ वहां एक-दो दिन बिताना चाहता है तो उसे काफी ख़ुशी होती है.

अमेरिका के डेनियल सुएलो नामक इस शख़्स ने पिछली बार 12 साल पहले पैसे देखे थे, जब उसके पास अंतिम बचे 1500 रुपये थे. आर्थिक तंगी से आजिज आकर डेनियल ने उन पैसों को फोन बॉक्स में फेंक दिया और पहाड़ों के बीच बिना पैसे वाली अर्थव्यवस्था में जीने का फ़ैसला किया. कई अमेरिकी मानते हैं कि अगर लोग इस तरह रहने लगें, तो न कोई कभी किसी अर्थव्यवस्था का गुलाम होगा और न कभी आर्थिक संकट होगा. डेनियल के जीवन से प्रभावित होकर उन पर किताब भी लिखी जा चुकी है. डेनियल का कहना है कि वह अब पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और न सरकार से मदद लेना चाहते हैं. उनका मानना है कि प्रकृति द्वारा जो भी चीजें मुफ्त में उपलब्ध हैं, उन्हीं से ज़िंदगी चलानी चाहिए. ऐसा करने से वह किसी अर्थव्यवस्था के गुलाम नहीं बनेंगे. डेनियल ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी फेंक दिया. उनका नाम शेलाबार्गर था, जिसे बदल कर उन्होंने सुएलो कर लिया. सुएलो का स्पैनिश अर्थ सतह या भूमि होता है.

न उम्र की सीमा हो...

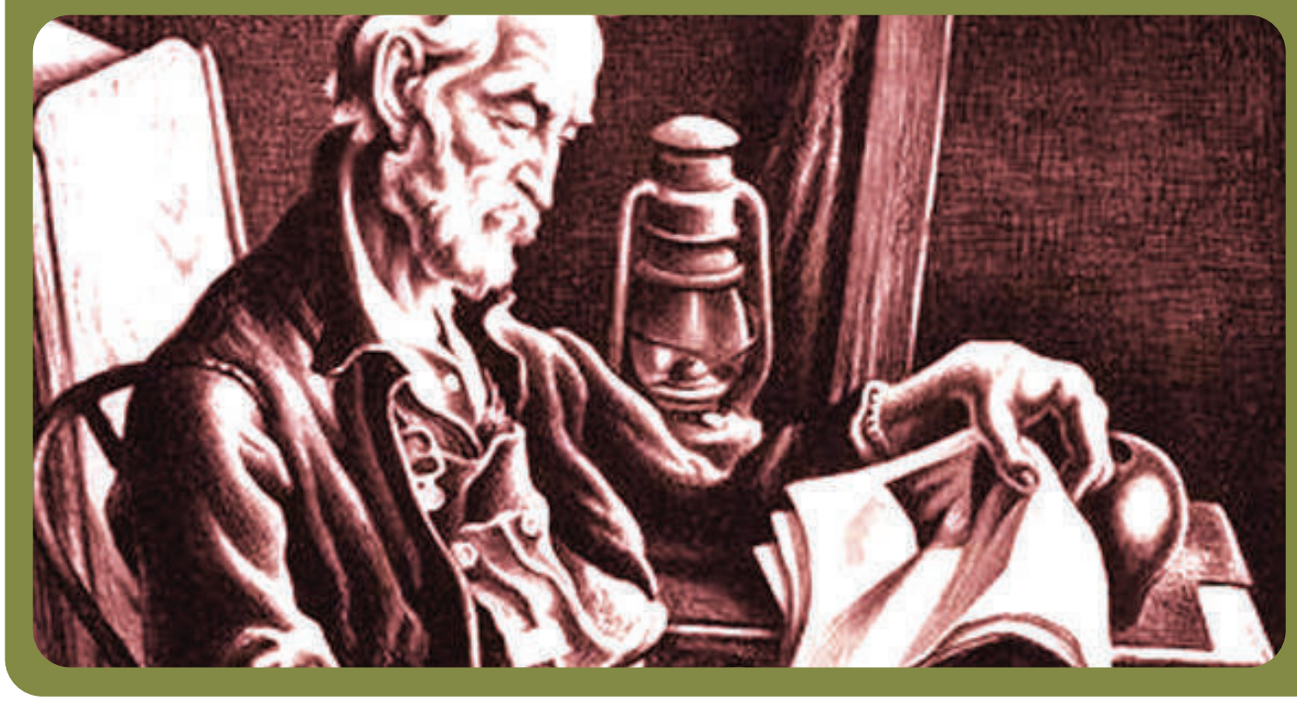

अगर पढ़ने की ललक हो तो उम्र उसमें बाधा नहीं बनती. आप किसी भी उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं. इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के एलन स्टीवर्ट हैं. 97 वर्षीय एलन स्टीवर्ट मास्टर्स की डिग्री पाने वाले दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के व्यक्ति बन गए हैं. मजे की बात यह है कि उनके नाम दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के ग्रेजुएट होने का रिकॉर्ड पहले से दर्ज है. एलन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है. वर्ष 2006 में 91 वर्ष की उम्र में विधि स्नातक की डिग्री लेकर एलन पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आए थे और अब उन्हें सर्दन क्रॉस यूनिवर्सिटी से क्लीनिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री मिली है. एलन का पढ़ाई का शौक नया नहीं है. उन्होंने 1936 में डेंटिस्ट्री में डिग्री हासिल की थी और तबसे यह उनकी चौथी डिग्री है. ख़ुद को मानसिक रूप से सक्रिय रखने के लिए उन्होंने 80 के दशक में फिर से पढ़ाई शुरू की थी. एलन स्टीवर्ट का जन्म 1915 में हुआ था. उनके छह बच्चे, 12 पोते-पोतियां और छह परपोते-परपोतियां हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन परिवार के लिए उचित समय बचाकर चलें. स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी. सफल होने के लिए मेहनत की ज़रूरत है. अपनी एकाग्रता बनाए रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग आर्थिक रूप से अच्छा करेंगे. उदर विकार से परेशान रहेंगे. विद्यार्थी अच्छा करेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप प्रसन्न रहेंगे और आपका उत्साह चरम पर रहेगा. माता-पिता से वैचारिक मतभेद न बढ़ने दें. संतान सुख सर्वोत्तम रहेगा. नौकरीपेशा लोगों की दौड़-भाग बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपको भरपूर सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग की व्यस्तता बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति आम तौर पर अच्छी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे. ऐश्वर्य की वस्तुओं पर पैसे खर्च होंगे. किसी संपत्ति के क्रय संबंधी विचार पर भी बहुत जोर रहेगा. आप अपनी कार्यशैली में पैनापन लाएंगे और मज़बूत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा. कोई भी निर्णय आपसी सूझबूझ से लें, जल्दबाज़ी न करें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह कोई नई चीज सीखने की इच्छा प्रबल रहेगी. प्राकृतिक रूप से सुंदर जगह की सैर की योजना बन सकती है. पारिवारिक रूप से ख़ुशनुमा माहौल रहेगा. किसी अच्छे निवेश का मौक़ा मिलेगा, केवल क़ानूनी ध्यान रखने की ज़रूरत है. आर्थिक रूप से बढ़िया सप्ताह है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
यह सप्ताह ख़र्च बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल समय रहेगा. नौकरी-पेशा लोग मन लगाकर कार्य करेंगे. व्यापारी आर्थिक परेशानी की वजह से थोड़े विचलित रहेंगे. कार्यशैली में नयापन लाने का विचार बनेगा. तनाव को न बढ़ने दें, इसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
क्रोध को नियंत्रण में रखें, अन्यथा नुक़सान होगा. आर्थिक दृष्टि से शुभ समय रहेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों वर्ग ख़ुश रहेंगे. पारिवारिक सहयोग मिलेगा. मांगलिक कार्य के लिए सटीक समय है. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र तनाव में रहेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
यह आपके परिश्रम का सप्ताह रहेगा. शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, सतर्क रहें. आर्थिक रूप से कुछ उतार-चढ़ाव रहेगा. भाई-बहनों से संबंध में तनाव बढ़ेगा. सामाजिक तौर पर आप मज़बूत रहेंगे. किसी नई संपत्ति के क्रय की योजना बनेगी. स्वास्थ्य आम तौर पर ठीक रहेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप अपनी सोच को सबके साथ न बांटें, अन्यथा आपके कार्य में बाधा आएगी. कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ेगी. कार्यालय से संबंधित किसी कार्य के लिए यात्रा का योग बनेगा. आर्थिक रूप से मज़बूती आएगी. व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित रहेंगे. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आएगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
वाद-विवाद से बचें और ख़र्च को नियंत्रण में रखें, अन्यथा तनाव में रहेंगे. किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णय न लें. नौकरीपेशा लोग ज़्यादा बदलाव नहीं देखेंगे. व्यापारी अपने निवेश को बढ़ाएंगे. पारिवारिक माहौल सुखकारी रहेगा. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यह आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन का सप्ताह रहेगा, नम्रता आएगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा. व्यापारी वर्ग को जोखिम वाले बाज़ार से बचने की ज़रूरत है. आपकी रुचि नया ज्ञान प्राप्त करने के प्रति बढ़ेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य में मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और कोई भी कार्य आसानी से पूरा कर लेंगे. किसी अज्ञात भय से बचें, उसे हावी न होने दें. वाहन सावधानी से चलाएं. अपनी कल्पनाशीलता पर नियंत्रण रखते हुए कार्यों को संपादित करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
कोई नया कार्य, जो आपके उत्तरदायित्व में है, उसे प्रारंभ करने में सफल होंगे. इस सप्ताह पारिवारिक सदस्य वस्त्र और आभूषण की ख़रीद की जिद करेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. भावना में बहकर कोई निर्णय न लें. आर्थिक रूप से अच्छा समय है.

cshekhar_3@hotmail.com

अब फ्रांस में सोशलिस्ट राष्ट्रपति हैं, जो यूरोपीय संधि पर पुनर्विचार करने और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं है.

ममता-हिलेरी की मुलाकात के मायने

राजीव कुमार

rajiv@chauthiduniya.com

अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भारत आईं. उनके आने से पहले ही उनकी यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दे दी गई. उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को मंजूरी दिलाने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना और ईरान से भारत में किए जा रहे तेल आयात को कम करके ईरान पर दबाव बनाना था. हालांकि इन दोनों अहम मुद्दों के अलावा भारत में निवेश करने की अमेरिकी इच्छा भी हिलेरी क्लिंटन ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष रखी. अमेरिकी विदेश मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने तीस्ता नदी विवाद, पश्चिम बंगाल में अमेरिकी निवेश एवं खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को मंजूरी देने संबंधी मुद्दों पर बातचीत की. हालांकि ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने इस बात से इंकार कर दिया कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर हिलेरी क्लिंटन से उनकी कोई बातचीत हुई है, लेकिन अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से जारी प्रेस वक्तव्य में साफ तौर पर कहा गया कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ हिलेरी क्लिंटन की बातचीत हुई. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के दौरे को भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने भारत आकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर राज्यस्तरीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि केंद्र स्तर के मुद्दों पर बातचीत की, यह एक साथ कई सवाल खड़े करता है.

सबसे पहली बात यह है कि हिलेरी को खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर ममता बनर्जी के समर्थन की ज़रूरत क्यों पड़ी. कुछ महीने पहले भारतीय खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी, इसे कैबिनेट ने मंजूर भी कर लिया था, लेकिन इसे संसद से मंजूर कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं था. सरकार के सहयोगी दल ही इस मुद्दे पर उसे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे. इसलिए सरकार ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया. खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश का विरोध करने वालों में ममता बनर्जी अग्रिम पंक्ति में खड़ी थीं. अमेरिकी अर्थव्यस्था की हालत कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती है. ऐसे समय में उसे बाज़ार की ज़रूरत है. भारत खुदरा क्षेत्र का बड़ा बाज़ार है. केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका को सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है. ऐसे में अगर केंद्र को ममता का समर्थन मिल जाए तो उम्मीद यही है कि खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश को मंजूरी मिल जाए. इसलिए अमेरिका को ममता बनर्जी का सहारा लेना पड़ रहा है. ममता बनर्जी को प्रलोभन दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अमेरिका निवेश करेगा. अमेरिका के इस प्रयास का नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन इससे यह तो साबित होता ही है कि यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घटक यानी कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को खुदरा बाज़ार के मुद्दे पर समझाने में नाकामयाब रही. इसी कारण अमेरिका को मोर्चा संभालने की ज़रूरत महसूस हुई.

अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा ममता बनर्जी से मुलाक़ात करने का एक कारण पश्चिम बंगाल में हुआ राजनीतिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है. यहां कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गया है. कम्युनिस्टों का अमेरिका विरोधी रवैया सर्वविदित है. ममता और क्लिंटन की इस मुलाक़ात पर भी बंगाल के कम्युनिस्टों की प्रतिक्रियाएं आईं. राज्यसभा में प्रश्न भी उठाया गया कि हमारी विदेश नीति प्रभावित करने की अमेरिकी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. केंद्र सरकार को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए. हालांकि कम्युनिस्ट अमेरिका के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के पक्ष में नहीं रहते, इसलिए उनका विरोध बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन तीस्ता नदी विवाद सुलझाने के लिए ममता बनर्जी का हिलेरी क्लिंटन से बात करना कोई अच्छा संकेत नहीं है. भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के समय तीस्ता नदी के जल विभाजन का मुद्दा अहम था. उस समय ममता बनर्जी ने अपना अड़ियल रुख दिखाया था. वह इस समझौते का विरोध भी करती रही हैं. हिलेरी क्लिंटन बांग्लादेश की यात्रा के बाद भारत आई हैं. संभव है, बांग्लादेश ने तीस्ता का मुद्दा उनके सामने उठाया होगा. इसके बाद ही उन्होंने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से बात की. अगर अमेरिकी विदेश मंत्री दक्षिण एशिया की समस्याओं के प्रति अपनी गंभीरता दिखाना चाहती हैं तो उन्हें भारत के विदेश मंत्री से बात करनी चाहिए थी, न कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से.

अमेरिकी विदेश मंत्री की यह भारत यात्रा ममता के साथ उनकी मुलाक़ात के कारण पहले की यात्राओं से कुछ अलग है. इस मुलाक़ात में उठाए गए मुद्दे विदेश नीति से जुड़े हैं. इससे भारत की विदेश नीति में केंद्र के कम होते प्रभाव का पता चलता है. भारत की विदेश नीति में क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है. कुछ समय पहले भी भारत ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान किया था. श्रीलंका विरोधी मतदान का कारण केंद्र सरकार की नीति नहीं, बल्कि तमिलनाडु सरकार का केंद्र पर दबाव था. इसके बाद श्रीलंका ने भी परमाणु मुद्दे और कश्मीर में मानवाधिकार हनन पर भारत का विरोध करने का मन बना लिया था. केंद्र की कमज़ोर गठबंधन सरकार अब विदेश नीति तय करने में भी सक्षम नहीं दिखाई दे रही है. इसे हमारे पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप और अमेरिका भी समझ गए हैं. यही कारण है कि बांग्लादेश की विदेश मंत्री भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठाती हैं कि तीस्ता जल समझौते के लिए क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बात की जा सकती है. पता नहीं, भारतीय विदेश नीति किस दिशा में जा रही है. एक समय था, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद लाल बहादुर शास्त्री ने श्रीलंका के साथ समझौता किया था, लेकिन आज एक राज्य हमारी विदेश नीति के सिद्धांतों को उलट देता है. अपने पड़ोसी देशों के ख़िलाफ़ मतदान के लिए बाध्य कर देता है. यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है. अगर ऐसी ही कमज़ोर सरकार केंद्र में रही तो फिर भारतीय विदेश नीति की दिशा बदल जाएगी. ■

ओलांद के हाथों में फ्रांस की बागडोर

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है. सरकोज़ी चुनाव हार गए हैं और फ्रांस्वा ओलांद अब देश के नए राष्ट्रपति होंगे. सोशलिस्ट पार्टी के ओलांद ने फ्रांस की जनता से कुछ वायदे किए हैं. अब उन वायदों को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी. सरकोज़ी की हार की सबसे बड़ी वजह यूरो ज़ोन का आर्थिक संकट और उससे निपटने में नाकामयाबी है. यूरोप के राष्ट्र आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए मितव्ययता की नीति अपना रहे हैं. फ्रांस ने भी इसी रास्ते को अपनाया हैं. बजट, सरकारी ख़र्च और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले धन में कटौती करके वह इस आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करना चाहता हैं, लेकिन पिछले तीन सालों से इन नीतियों पर चलकर भी उसे कामयाबी नहीं मिली. सरकोज़ी से पहले यूरोप के क़रीब दस देशों में सत्ता परिवर्तन हो चुका है. ग्रीस में हुए चुनाव में भी सत्तारूढ़ दल की वही स्थिति रही. इसके अलावा सरकोज़ी की जीवनशैली भी शायद लोगों को पसंद नहीं आई, जो उनकी हार का कारण बनी. वहीं किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहे ओलांद की ओर लोगों का ध्यान गया. यही बात चुनाव में उनके लिए फ़ायदेमंद रही. फ्रांस के लोगों को उनमें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी. उन्होंने लोक लुभावन चुनावी वायदे भी किए. ओलांद ने यूरोपीय संधि पर पुनर्विचार करने का मामला उठाया, जिसमें आर्थिक मितव्ययता की बात कही गई है. उन्होंने लोगों से वायदा किया कि अगले तीन महीनों तक पेट्रोल के दामों में किसी तरह की कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी और साथ ही रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे.

ओलांद ने कहा कि जिन कर्मचारियों या मज़दूरों ने 18 वर्ष की आयु में काम करना शुरू किया है, उन्हें 60 साल की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा. उन्होंने क़रीब एक लाख शिक्षकों की भर्ती और क़रीब डेढ़ लाख बेरोज़गारों को रोज़गार देने का वायदा किया. उन्होंने कर संबंधी नियमों में बदलाव की भी बात कही है. उनका कहना है कि जिन लोगों की आमदनी कम है, उन्हें कर में रियायत दी जाएगी और जिनकी आमदनी ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ेगा. ओलांद ने कहा कि जिन लोगों की आमदनी दस लाख यूरो या उससे अधिक है, उन्हें 75 प्रतिशत कर देना होगा. स्वाभाविक है कि ऐसे वायदों और सरकोज़ी की नीतियों की विफलता के कारण ओलांद को अधिक मत मिलने ही थे. दूसरी ओर आईएमएफ के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रॉस कान, जो राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे थे, यौन उत्पीड़न के मामले में फंसने के कारण इस दौड़ से बाहर हो गए. इसका फ़ायदा भी ओलांद को हुआ.

बहरहाल, अब फ्रांस में सोशलिस्ट राष्ट्रपति हैं, जो यूरोपीय संधि पर पुनर्विचार करने और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं है. अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए उन्हें विश्व बैंक एवं आईएमएफ जैसी संस्थाओं के सहारे की ज़रूरत है, जो कर्ज दे सकें. इसके लिए उन्हें अन्य यूरोपीय देशों को अपने साथ लेकर चलना होगा. खासकर जर्मनी के साथ उन्हें अपने संबंध मज़बूत करने होंगे. जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल सरकोज़ी का समर्थन कर रही थीं, लेकिन ओलांद की जीत के बाद उन्होंने न केवल जीत की बधाई दी, बल्कि उन्हें जर्मनी आने का न्योता भी दिया है. अब दोनों मिलकर किस रणनीति पर काम करते हैं, यह तो समय बताएगा, लेकिन उम्मीद तो यही है कि यूरोप को संकट से उबारने के लिए फ्रांस और जर्मनी साथ मिलकर काम करेंगे. इसके अलावा ओलांद को अपने समाजवादी नज़रिए में संतुलन भी बनाना होगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं. उन्होंने दस लाख यूरो या इससे अधिक आमदनी वाले लोगों से 75 प्रतिशत कर लेने की बात कही है. इतनी आमदनी वाले लोगों का पलायन भी हो सकता है, जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा. ओलांद को इस ओर भी ध्यान देना होगा. कई चुनौतियों के बीच नए राष्ट्रपति पर न केवल फ्रांस के लोगों को भरोसा है, बल्कि पूरा यूरोप उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है. अब ओलांद को इन उम्मीदों पर खरा उतरना है. रणनीति कैसी भी हो, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती फ्रांस के साथ-साथ यूरोप को आर्थिक संकट से उबारना है. फ्रांस की भूमिका अहम है और अब उसकी ज़िम्मेदारी ओलांद के कंधों पर है. ■

राजीव कुमार

rajiv@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

सेव योर वॉयस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि आईटी एक्ट को हटाया जाए और उसकी जगह एक ठोस क़ानून लाकर इंटरनेट को मज़बूती प्रदान की जाए.

अभिव्यक्ति की आज़ादी क़ायम रहे

भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कबीर दास का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है. मध्य काल में कबीर दास ने तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ तीखे व्यंग्य किए. अगर उनके दोहों को पढ़ा जाए तो उन्होंने धर्म के ठेकेदारों और ख़ुद को समाज का रहबर मानने वालों को अपने शब्दबाणों से छलनी कर दिया. कबीर जिस युग में पैदा हुए, उस दौर में देश धार्मिक अंधविश्वास के दुष्चक्र में फंसा था. ऐसे में कबीर के दोहे सामाजिक चेतना का संचार करने वाले थे. बावजूद इसके तत्कालीन शासकों ने उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ताधीशों की कोई आलोचना करे, यह उन्हें पसंद नहीं है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि ब्लॉगर, पत्रकार, कार्टूनिस्ट, रंगकर्मी और साहित्यकार खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते. आईटी एक्ट-2011 द्वारा एक साज़िश के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

अभिषेक रंजन सिंह
arsingh@chauthiduniya.com

अगर आप अपने गांव और शहर से सैकड़ों मील दूर हैं, तो इसकी संभावना न के बराबर है कि अख़बारों और न्यूज चैनलों पर आप अपने गृह जनपद की छोटी-बड़ी ख़बरें देख पाएं. भारत में इंटरनेट क्रांति आने के बाद यह सपना साकार होने लगा. लिहाज़ा सात समंदर पार रहने वाले लोग भी इंटरनेट पर वेबसाइटों और ब्लॉगों पर हर वह चीज़ पढ़ पाते हैं, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले नहीं की जा सकती थी. इंटरनेट के इस युग में ही सोशल मीडिया का जन्म हुआ, जिसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अब देश के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं के बारे में लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाती है. इसके बावजूद केंद्र सरकार आईटी एक्ट के ज़रिए इंटरनेट क्रांति और सोशल मीडिया के बधियाकरण पर तुली है.

यही वजह है कि इंटरनेट सेंसरशिप के ख़िलाफ़ सेव योर वॉयस के कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल फ्रीडम फास्ट इसी महीने पुलिस द्वारा जबरन ख़त्म करा दी गई. सेव योर वॉयस के कार्यकर्ता राजधानी के जंतर-मंतर पर फ्री इंटरनेट और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग को लेकर बीती दो मई से अनशन कर रहे थे. उन लोगों को जंतर-मंतर पर अनशन करने के लिए महज़ दो दिन की ही अनुमति दी गई थी और सरकार इसे आगे बढ़ाने को राज़ी नहीं थी. हालांकि इन आंदोलनकारियों को पीछे हटने का विकल्प पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया है कि वे सरकारी मंज़ूरी के बिना जंतर-मंतर पर अपनी भूख हड़ताल तब तक जारी रखेंगे, जब तक सरकार और राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस बारे में उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता. वैसे तो जंतर-मंतर पर साल भर कोई न कोई धरना-प्रदर्शन होता रहता है. देश की मीडिया के लिए यह स्थान ख़बरों के संकलन के लिए बेहद मुफ़ीद है. हालांकि इंटरनेट सेंसरशिप के ख़िलाफ़ जब असीम त्रिवेदी और आलोक दीक्षित अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो मीडिया ने इसे ख़ास तवज्जो नहीं दी. दरअसल, यह उनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि उन्हें पकी-पकाई ख़बरें लेने की आदत है. ऐसे में भला उन्हें असीम, आलोक और इंटरनेट की आज़ादी के पक्षधर लोगों से क्या मतलब. इन दोनों की लड़ाई ख़ुद के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख़्स के लिए है, जो इंटरनेट पर ब्लॉगों के ज़रिए अपनी खरी बात बेबाकी से रखता है और रखना चाहता है. सेव योर वॉयस बेशक एक छोटा और लोकप्रिय संगठन न हो, लेकिन उसके इरादे बेहद मज़बूत हैं. वैसे भी देश में सत्ता और व्यवस्था के ख़िलाफ़ जिस तरह एक लहर पैदा हुई है, उसमें ऐसे संगठनों की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है. जिस तरह बाढ़ में चारों तरफ़ पानी ही पानी दिखाई देता है और यह फ़र्क़ कर पाना मुश्किल होता है कि इतने बड़े सैलाब में कौन सा पानी कहां से आया है. उसी तरह हर स्तर पर होने वाले आंदोलन मिलकर ही एक बड़ा जनांदोलन बनते हैं. सेव योर वॉयस आईटी एक्ट-2011 में किए गए संशोधन के विरुद्ध है. सरकार अभिव्यक्ति के आख़िरी बचे माध्यम वेबसाइट पर भी असीमित और अराजक सेंसरशिप लागू करना चाहती है. इस बारे में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, जिन्हें पुलिस ने जबरन राममनोहर लोहिया अस्पताल में दाख़िल कराया. उनका कहना है कि यूपीए सरकार पूरी तरह निरंकुश हो गई है. अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि वह एक कार्टूनिस्ट हैं और एक कलाकार अपनी भावनाओं को अलग-अलग तरीक़े से व्यक्त करता है. असीम त्रिवेदी की कार्टून अगेंस्ट करप्शन नाम से एक वेबसाइट हुआ करती थी, जिसे बीते साल 27 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दिया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया.

ग़ौरतलब है कि असीम ने पिछले साल एक कार्टून बनाया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई थी. वहीं सेव योर वॉयस से जुड़े आलोक दीक्षित का कहना है कि यूपीए सरकार पूरी तरह बेलगाम हो गई है. उसके शासन में आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ऐसे में जो लोग सरकार की आलोचना अपनी कला के माध्यम से करते हैं, उन पर सरकार को एतराज़ है. आलोक के मुताबिक़, आईटी एक्ट-2011 में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, वह पूरी तरह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है. बक़ौल आलोक, अगर आपने अपने ब्लॉग पर कोई विचार पोस्ट किया है, उस पोस्ट पर किसी ने आपत्ति ज़ाहिर कर दी तो ब्लॉगर बिना किसी पड़ताल के 26 घंटे के भीतर लेखक के ब्लॉग को ब्लॉक कर सकता है या पोस्ट किए गए कंटेंट को डिलीट कर सकता है. आईटी एक्ट-2011 के बारे में ब्लॉग लेखकों का कहना है कि बिना किसी सुनवाई के, बग़ैर किसी का पक्ष जाने इंटरनेट पर लिखी हुई सामग्री को हटाना या साइट को ब्लॉक करना सरासर नाइंसाफ़ी है और यह सब कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पर. दरअसल, यूपीए सरकार चौतरफ़ा आलोचनाओं की शिकार है. सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध हो रहा है. जब इंटरनेट पर बुद्धिजीवियों ने सरकार में शामिल लोगों की करतूतों को उजागर करना शुरू किया तो वह जनता की आवाज़ दबाने के लिए आईटी एक्ट का सहारा ले रही है. कई लोगों की राय में यह एक ऐसा क़ानून है, जो साफ़ तौर पर संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी आत्मा को मारने की साज़िश करता है.

सेव योर वॉयस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि आईटी एक्ट को हटाया जाए और उसकी जगह एक ठोस क़ानून लाकर इंटरनेट को मज़बूती प्रदान की जाए. केरल के सीपीएम सांसद पी. राजीव इस क़ानून को हटाने के लिए राज्यसभा में एक एनलमेंट मोशन लाए हैं, जिस पर सांसदों को वोट करना है. हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने इस मोशन पर वोट करने के लिए अपनी सहमति ज़ाहिर नहीं की है. इसकी एक वजह यह भी है कि ज़्यादातर लोगों को इस क़ानून के बारे में जानकारी ही नहीं है और सरकार इसी का फ़ायदा उठाना चाहती है. अगर यह क़ानून संसद के इसी सत्र में ख़त्म नहीं होता है तो इसे निरस्त कराने में कई साल लग जाएंगे. ग़ौरतलब है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को पूरी तरह ख़त्म करता हुआ आईटी एक्ट फ़िलहाल राज्यसभा में विचाराधीन है. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती असीम त्रिवेदी और आलोक दीक्षित ने बताया कि टीम अन्ना के सदस्य और वरिष्ठ रंगकर्मी अरविंद गौड़ अपनी थिएटर टीम के साथ जंतर-मंतर पहुंचे और इंटरनेट की आज़ादी की वकालत की. अरविंद गौड़ ने कहा कि इंटरनेट एक आम आदमी की अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए इंटरनेट की आज़ादी लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है. इंटरनेट की आज़ादी के लिए यह अपनी तरह की पहली भूख हड़ताल थी. यह पहला मौक़ा था, जब देश के इंटरनेट यूज़र्स और ब्लॉगर्स अपने अधिकारों के लिए वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर ज़मीन पर उतरे हैं. हाल में पत्रकारों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एनिमी ऑफ द इंटरनेट नाम से एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें भारत का नाम भी शामिल था. इस सूची में बर्मा, चीन, क्यूबा, ईरान, सउदी अरब, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और वियतनाम को इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया था.

दुनिया का हर संविधान प्रीजम्शन ऑफ इनोसेंस के सिद्धांत को मानता है, यानी नागरिक तब तक इनोसेंट है, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि उसने कोई गुनाह किया है. संविधान कहता है कि भले ही कई अपराधी बग़ैर सज़ा के बरी हो जाएं, लेकिन एक बेक़सूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. हालांकि इसके बरअक्स साइबर मीडिया को सेंसर करने और उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले इस सिद्धांत को ही ख़ारिज दिया. ■

जनरल, जनता और जंतर-मंतर

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

आप इसे सही मान सकते हैं. ग़लत मान सकते हैं, लेकिन सेना के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जो पहली बार हो रहा है, मसलन एक सेनाध्यक्ष का अपनी जन्मतिथि मामले में कोर्ट जाना. कोर्ट द्वारा कोई निर्णय न देकर मामले को सुलझाने की नसीहत देना. रामदेव और टीम अन्ना के बाद जनता का जनरल वीके सिंह के समर्थन में आना. बीती 6 मई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुछ इसी तरह का दृश्य था. हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए 3-4 हज़ार लोगों ने खुलकर जनरल वीके सिंह का समर्थन किया.

सर्वधर्म समाज संघर्ष समिति की ओर से आयोजित इस रैली में वैसे तो ज़्यादातर लोग हरियाणा से आए थे, लेकिन इस रैली को स्वामी रामदेव और टीम अन्ना ने भी समर्थन दिया. रैली के दौरान दिए जा रहे भाषणों का मुख्य निशाना केंद्र सरकार की नीतियां थीं. लोगों का मुख्य सवाल जय जवान और जय किसान यानी जवान और किसान की दुर्दशा से ही जुड़ा हुआ था, मसलन भीड़ में शामिल कई लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा हुआ था, फ़ौज लड़े सीमा पर, छोड़ मां-बाप, बच्चे घरवाली, ग़द्दार खाएं माल, कर गोला बारूद की दलाली. कुछ तख्तियों पर यह भी लिखा था कि फ़ौज बचाओ देश बचाओ. ज़्यादातर वक्ताओं का यही कहना था कि किसान का बेटा फ़ौज में जाता है. एक तरफ़ तो किसानों की हालत ख़राब हो रही है और दूसरी तरफ़ सरकार जो कुछ भी कर रही है, उससे जवानों का मनोबल भी गिर रहा है. रैली को वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता वेद प्रताप वैदिक ने भी संबोधित किया और जनरल वीके सिंह की तुलना भगवान राम से कर दी. वेद प्रताप वैदिक का कहना था कि जनरल वीके सिंह ने इस देश की अदालत, रक्षामंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार की इज़्ज़त बचा दी. केंद्र सरकार के रुख़ पर वह कहते हैं कि इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है. सर्वधर्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदपाल सिंह तंवर इस मसले पर काफ़ी उग्र दिखे. वह कहते हैं कि वीके सिंह के साथ अन्याय हुआ है और हम इस अन्याय के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे. बहरहाल, इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा? इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नए जनरल के नाम की घोषणा हो चुकी है. 31 मई को जनरल वीके सिंह रिटायर भी हो जाएंगे. उसके बाद क्या तस्वीर बनती है, वीके सिंह का निर्णय क्या होता है? वह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होते हैं, राजनीति में आते हैं या कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं, तभी कोई तस्वीर साफ़ होगी.

> स्वच्छ चादर के नीचे छिपी बुराइयों को मैं सभी बुराइयों से ज़्यादा ख़तरनाक मानता हूं. मनमोहन सिंह ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस स्वच्छ छवि की चादर के नीचे जो भ्रष्टाचार है वह ख़तरनाक है. जनरल वीके सिंह ने अपने त्याग से अदालत, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार की प्रतिष्ठा बचा ली.

वेद प्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता

बहरहाल, सेना और सेनाध्यक्ष के समर्थन में जनता का सड़क पर उतरना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत देता है. आमतौर पर सेना और सेना में होने वाली नियुक्तियों से जुड़े मामले कभी भी जनता और मीडिया के बीच बहस का मुद्दा नहीं होते थे. यह सब पहली बार हो रहा है. वर्तमान परिस्थितियों में भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच जो संदेश गया है, फिर जनलोकपाल और कालेधन के मामले पर जिस तरह से जनता के बीच जागृति आई है, वह कम से कम राजनीतिक दलों के लिए शुभ तो नहीं ही मानी जा सकती है. ■

इक़बाल की शुरुआती तालीम मदरसे में हुई. बाद में उन्होंने मिशनरी स्कूल से प्राइमरी स्तर की शिक्षा शुरू की. लाहौर से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया.

रिश्तों की गर्माहट का संग्रह

अनंत विजय
anant.ibn@gmail.com

चौथी दुनिया में लगभग तीन साल से ज़्यादा समय से लिख रहे अपने स्तंभ में कविता और कविता संग्रह पर बहुत कम लिखा. साहित्य से जुड़े कई लोगों ने शिकायती लहज़े में इस बात के लिए मुझे उलाहना भी दिया. कइयों ने कविता के प्रति मेरी समझ पर भी सवाल खड़े किए. दोनों चीजें जायज़ हैं. शिकायत भी लाज़िमी है, क्योंकि इतने लंबे समय से हर हफ्ते लिखे जाने वाले स्तंभ में मैंने दो या तीन बार कविता की पुस्तकों की चर्चा की. जहां तक समझ की बात है, वह भी बहुत हद तक सही ही है. कविता में मेरी रुचि इस वजह से नहीं है या फिर समझ विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह की, ज़्यादातर कविताएं पिछले तीन–चार दशकों में लिखी गईं, वे या तो बहुत दुरुह हैं या फिर उनमें बेहद सपाट बयानी है. दोनों हालत में कविता का जो रस होता है, वह ग़ायब है, लिहाज़ा उसे समझना कम से कम मेरे लिए आसान नहीं है. उस तरह की कविताओं में क्रांति, यथार्थ एवं सामाजिक विषमताओं का इतना ओवरडोज है कि वे आम हिंदी पाठकों से दूर होती चली गईं.

यह अनायास नहीं है कि आज कविता के पाठक क्यों कर कम होते जा रहे हैं, क्यों कवि सम्मेलनों का आयोजन सिमटता चला जा रहा है. जो हो भी रहे हैं, वे दस–बीस कवियों के बीच बैठकर एक–दूसरे की कविताओं को सुन लेने भर जैसे आयोजन होते हैं. पाठकों और कविता प्रेमियों से कविता दूर होती जा रही है. मुझे जो वजह समझ में आती है, वह यही है कि कविता में जो रस तत्व होता था या जिसे सुनना अच्छा लगता था, वह यथार्थ की बंजर ज़मीन पर सूख गया. लिहाज़ा कविता में एक रूखापन सा आ गया. कविताएं नारेबाज़ी में तब्दील हो गईं, कविताएं क्रांति कराने में जुट गईं. मेरे तर्कों को कविता प्रेमी यह कहकर खारिज करने की कोशिश करेंगे कि यह बहुत पुराना तर्क है और तुकांत और अतुकांत कविताओं को लेकर उठे विवाद में ये तर्क लंबे समय से दिए जाते रहे हैं. चलिए, अगर एकबारगी यह मान भी लिया जाए कि तर्क पुराने हैं और उनकी बिनाह पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो फिर मैं उन आलोचकों को चुनौती देता हूं कि वे इस बात की खोज करें और हिंदी साहित्य को यह बताएं कि कविता की लोकप्रियता कम क्यों हो रही है. मैं यहां जानबूझ कर लोकप्रियता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जन और लोक की बात करने वाले कवियों और आलोचकों ने ही कविता को लोकप्रिय होने से रोक दिया है. कविता को शोध आधारित कथ्य और अति बौद्धिक बनाने के चक्कर में यथार्थ से भर दिया गया. इसी अति बौद्धिकता और भोगे हुए यथार्थ ने कविता को लोक और जन से दूर कर दिया और उसे किताबों या फिर आलोचकों के लेखों का विषय बना दिया. अंग्रेजी के कवि विलियम वड्र्सवर्थ का भी मानना था कि पॉएट्री इज द स्पांटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फीलिंग्स रीकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटीज.

काफी दिनों पहले मुझे कवि मित्र तजेंदर लूथरा के घर पर आयोजित छोटी से कवि गोष्ठी में जाने का अवसर मिला था, जहां मैंने विष्णु नागर, मदन कश्यप, लीलाधर मंडलोई, पंकज सिंह, सविता सिंह, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी एवं राजेंद्र शर्मा समेत कई दिग्गज कवियों को सुना था. उस कवि गोष्ठी में कुछ कवियों को छोड़कर वैसी ही दुरुह कविताएं सुनने को मिलीं. मैं उन कवियों का नाम लेकर नाहक विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन कई कवियों की कविताएं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थीं. मैं उनकी कविताओं को नहीं, बल्कि अपनी समझ को इसके लिए ज़िम्मेदार मानता हूं. हां, उस कवि गोष्ठी में कई कवियों की कविताएं बेहतरीन थीं और समझ में आने वाली भी. मैं उन कवियों का भी नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इससे भी एक अलग तरह का ख़तरा है. हिंदी साहित्य की राजनीति जानने वालों के लिए उस ख़तरे को समझना आसान है. मैं यहां सिर्फ़ एक कवयित्री का नाम ले रहा हूं, जिनकी कविताएं मुझे पसंद आई थीं. उनका नाम है ममता किरण. मैं उनकी कविताओं का जिक्र चौथी दुनिया के अपने स्तंभ में पहले भी कर चुका हूं. ममता किरण का नाम मैंने ज़रूर सुना था, लेकिन कविता की राजनीति और उसका भविष्य तय करने वालों की सूची में कभी उनका नाम देखा–पढ़ा नहीं था. अगर मेरी स्मृति मेरा साथ दे रही है तो पहली कवि गोष्ठी में उन्होंने स्त्री और नदी नामक कविता का पाठ किया था. कविता मुझे पसंद आई. गोष्ठी ख़त्म होने के बाद मैं उन्हें बधाई देना चाहता था, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा संभव नहीं हो सका. छह–आठ महीने बाद एक बार फिर से तजेंदर जी के यहां गोष्ठी हुई. फिर से अन्य कवियों के अलावा ममता किरण ने अपनी कविताएं सुनाकर वहां मौजूद लोगों की प्रशंसा बटोरी. दूसरी गोष्ठी के बाद मैंने उन्हें उनकी कविताओं के लिए बधाई दी, स्त्री और नदी कविता के लिए भी.

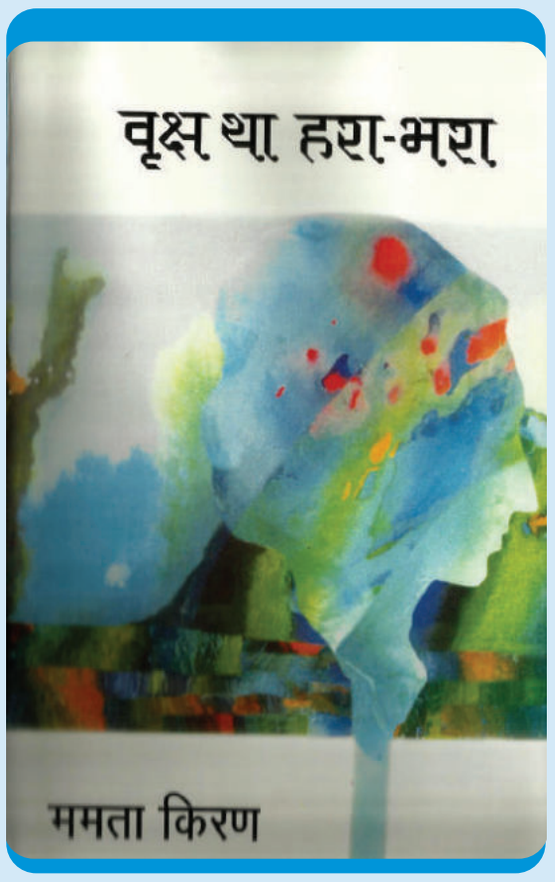

अभी हाल में जब मुझे डाक से ममता किरण का नया कविता संग्रह– वृक्ष था हरा भरा (किताबघर प्रकाशन, अंसारी रोड, नई दिल्ली) मिला तो मैंने संग्रह की 56 कविताएं एक झटके में पढ़ लीं. कविताओं से गुजरते हुए मुझे अच्छा लगा. कवयित्री की रेंज बहुत व्यापक है. उनकी कविताओं में परिवार प्रमुखता से आता है. वहां मां है, मां का हठ है, बेटी है, बड़े भैया हैं. मां पर लिखते हुए कवयित्री परोक्ष रूप से बेटे के नौकरी या फिर कारोबार (जो भी कवयित्री ने सोचा हो) करने को लेकर बाहर चले जाने के बाद मां के दर्द को समेटा है. मां अपने बेटे को खत लिखवाती है–अब ज़रूरत नहीं/तुम्हारे भेजे/पैसे और दवाओं की/सिर्फ़ तुम आ जाओ/बैठो मेरे पास/तुम्हारे बचपन की स्मृतियों में/तलाशूं/अपना अतीत/अपने जीवन की संतुष्टि.

इस एक छोटी सी कविता में गांव से लेकर महानगर तक की मां का दर्द है. जिस बच्चे को पढ़ा–लिखाकर अपने सीने से लगाकर पाला–पोसा, बड़ा किया, वह उसे छोड़कर चला गया है. उसका ख्याल भी रखता है. उम्र के उस पड़ाव पर जब देखभाल से ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, तब मां को अकेलेपन का दंश झेलना पड़ता है. ठीक उसी तरह बड़े भैया कविता में भी कवयित्री ने एक पूरी पीढ़ी के ट्रांसफॉर्मेशन पर रोशनी डाली है. एक लड़का जब पिता बनता है तो उसमें अपने मां की वही सारी आदतें आ जाती हैं, जिनका वह जवानी में मज़ाक उड़ाया करता था. उम्र के साथ संतान मोह में किस तरह से लोगों की मानसिकता बदलती है, उसका चित्रण है इस कविता में. इस संग्रह में एक कविता है संबोधन–कंक्रीट के इस जंगल में/एकदम अप्रत्याशित/एक बुजुर्ग से अपने लिए/बहूरानी संबोधन सुनकर/जिस तरह मैं चौंकी/उसी तरह अनायास/श्रद्धा से झुक भी गई/बहूरानी कहने वाले के सामने. इस कविता के बारे में संग्रह के ब्लर्ब पर कवि केदारनाथ सिंह लिखते हैं–इस संग्रह में जहां जाकर मैं रुका, वह संबोधन शीर्षक कविता थी. इन पंक्तियों में एक मानवीय संस्पर्श है, जो अच्छा लगता है. कहीं–कहीं शुभाकांक्षा की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ती है कुछ पंक्तियों में और शायद इस रचनाकर्मी की कविता का मूल स्वर भी यही है. केदार जी को इस बात का संशय क्यों है कि शुभाकांक्षा की प्रतिध्वनि ममता किरण की कविताओं का मूल स्वर है. मूल न भी कहें तो अनेक स्वरों में से एक स्वर यह भी है, जो एक छुपी हुई धारा की तरह कमोबेश हर जगह मौजूद है. इस कविता की भूमिका अनामिका ने लिखी है और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि ग्रहण के समय खाने–पीने की चीजों में मां तुलसी पत्र डाल देती थी, जैसे हम किताबों में फूल डाल देते थे. परंपरा के पन्नों में ममता किरण जी की कविता ऐसा ही कुछ डाल देती है और काफी नफासत से. अब यहां मैं पाठकों पर छोड़ता हूं कि वे तय करें कि कविता को लेकर मेरी जो राय है, उसे अनामिका का कथन पुष्ट करता है या नहीं, क्योंकि अनामिका ग्रहण और तुलसी पत्र के प्रतीकों में बहुत बड़ी बात कह गई हैं. सोचिए, समझिए और निष्कर्ष पर पहुंचिए. आमीन. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

काव्य दुनिया

अस्तित्व

लौट पड़े थे मेरे क़दम
एक बार फिर वहीं
जहां मौजूद है तू
और तेरा अक्स
सिर्फ़ इस चाह में
कि कभी न कभी
किसी न किसी पल
टूटेगी कुंभकर्णी नींद
जागेगी तेरी संवेदना
जो बन गई पत्थर
बाज़ारवाद के स्पर्श से
लेकिन, ठगा सा
रह गया उस दिन
यह देखकर कि
तू स्वयं है तत्पर
बनने को बाज़ार का हिस्सा

संवेदनाओं के सारे
बंधन तोड़कर!
इसलिए...
थके क़दमों से
वापस हो चला हूं
उस मोड़ की तरफ़
जहां से खोज सकूं
एक ऐसा रास्ता
जो तेरे बाज़ार से
होकर तो गुज़रे
लेकिन...
जिंदा रखे वह दर्शन
जो है मेरा
साथी व मार्गदर्शक
और जिस पर अवलंबित है
मेरा समूचा अस्तित्व!

महेंद्र अवधेश

तुझे क्या मिलेगा नमाज़ में

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

हज़ारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा

उर्दू और फ़ारसी शायरी के चमन का यह दीदावर यानी मोहम्मद अल्लामा इक़बाल 9 नवंबर, 1877 को पाकिस्तान के स्यालकोट में पैदा हुआ. उनके पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन क़रीब तीन सौ साल पहले उन्होंने इस्लाम क़ुबूल कर लिया था और कश्मीर से पंजाब जाकर बस गए थे. उनके पिता शेख़ नूर मुहम्मद कारोबारी थे. इक़बाल की शुरुआती तालीम मदरसे में हुई. बाद में उन्होंने मिशनरी स्कूल से प्राइमरी स्तर की शिक्षा शुरू की. लाहौर से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया. 1905 में दर्शनशास्त्र की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए. उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की. इसके बाद वह ईरान चले गए, जहां से लौटकर उन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफ़िज़िक्स इन पर्शियन नामक एक किताब भी लिखी. इसी को आधार बनाकर बाद में जर्मनी के म्युनिख विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी. इक़बाल की तालीम हासिल करने की फ़ितरत ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया. बाद में उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की. वह लंदन विश्वविद्यालय में छह माह तक अरबी के शिक्षक भी रहे. 1908 में वह स्वदेश लौटे. लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर प्रोफेसर उनकी नियुक्ति हो गई. इस नौकरी के साथ वह वक़ालत भी कर रहे थे, लेकिन कुछ वक़्त बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वकालत को ही अपना पेशा बना लिया.

यूं तो इक़बाल को बचपन से ही शायरी का शौक़ था और वह अपनी रचनाएं डाक के ज़रिये उर्दू के मशहूर शायर एवं उस्ताद दाग़ देहलवी को भेजा करते थे, लेकिन उनकी शायरी की विधिवत शुरुआत लाहौर आकर हुई. उस वक़्त उनकी उम्र बाइस साल थी. अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने वहां एक मुशायरे में अपनी ग़ज़ल पढ़ी. इस मुशायरे में मिर्ज़ा अरशद गोरगानी भी थे, जिनकी गिनती उन दिनों चोटी के शायरों में होती थी. जब इक़बाल ने ग़ज़ल का यह शेअर पढ़ा:–

मोती समझ के शाने–करीमी ने चुन लिए
क़तरे जो थे मेरे अर्क़–इंफ़आल के

यह शेअर सुनकर मिर्ज़ा अरशद साहब तड़प उठे. उन्होंने इक़बाल की प्रशंसा करते हुए कहा, मियां साहबज़ादे! सुब्हान अल्लाह, इस उम्र में यह शेअर!

उसी उम्र में मिर्ज़ा दाग़ ने भी इक़बाल की रचनाएं यह कहकर वापस करनी शुरू कर दीं कि उनकी रचनाएं संशोधन की मोहताज नहीं हैं. उस वक़्त की मशहूर उर्दू पत्रिका मख़ज़न के संपादक शेख़ अब्दुल क़ादिर अंजुमन–ए–हिमायत–ए–इस्लाम के जलसों में इक़बाल को नज़्में पढ़ते देख चुके थे और वह इक़बाल से बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने इक़बाल की नज़्में मख़ज़न में प्रकाशित करनी शुरू कर दीं. मख़ज़न के अप्रैल 1901 के अंक में प्रकाशित उनकी पहली नज़्म हिमालय ने उनकी ख्याति दूर–दूर तक पहुंचा दी. शेख़ अब्दुल क़ादिर इक़बाल के बारे में कहते थे, अगर मैं तनासख़ (आवागमन) का क़ायल होता तो ज़रूर कहता कि ग़ालिब को उर्दू और फ़ारसी से जो इश्क़ था, उसने उनकी रूह को अदम (परलोक) में जाकर भी चैन नहीं लेने दिया और मजबूर किया कि वह फिर किसी इंसानी जिस्म में पहुंच कर शायरी के चमन की सिंचाई करें और उन्होंने पंजाब के एक गोशे में जिसे स्यालकोट कहते हैं, दोबारा जन्म लिया और मोहम्मद इक़बाल नाम पाया.

उन्होंने उर्दू की बजाय फ़ारसी में ज़्यादा लिखा. फ़ारसी की वजह से उनका कलाम न सिर्फ़ हिंदुस्तान, बल्कि ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, टर्की और मिस्र तक पहुंचा. 1915 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह असरारे–ख़ुदी के अंग्रेजी अनुवाद ने उन्हें अमेरिका और यूरोप में भी विख्यात कर दिया. ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सर की उपाधि से भी नवाज़ा था. रवींद्र नाथ टैगोर के बाद इक़बाल ही वह दूसरे व्यक्ति थे, जिन्हें यह उपाधि मिली.

उन्होंने अपनी क़ौम को बुलंदी का सबक़ दिया और हर उस बात का विरोध किया, जो बुलंदी की राह में रुकावट बने. वह क़िस्मत के आगे हार नहीं मानते और हालात का मुक़ाबला करने का संदेश देते हैं:–

ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले
ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है

उनकी शायरी इस बात की गवाह है कि वह ताउम्र अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे. उनके गीत पर सारा देश झूम उठता है और मन में देशभक्ति की भावना हिलोरें लेने लगती हैं:–

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा

उन्होंने प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को भी अपनी नज़्मों में जगह दी. पहाड़ों, झरनों, नदियों, लहलहाते हुए फूलों की डालियों और ज़िंदगी के हर उस रंग को उन्होंने अपने कलाम में शामिल किया, जो इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करता है. उनकी नज़्म आज भी स्कूलों में बच्चे गाते हैं:–

लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी
ज़िंदगी शमा की सूरत हो ख़ुदाया मेरी
दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए
हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए

वह साहित्य में प्रयोगवाद के विरोधी थे. विचारों के बिना सुंदर शब्दों का कोई महत्व नहीं है. उन्होंने अपनी भाषा शैली की बजाय अपने विचारों को बेहद पुख्ता तरीक़े से पेश किया. बानगी देखिए:–

अज़ान अज़ल से तेरे इश्क़ का तराना बनी
नमाज़ उसके नज़ारे का इक बहाना बनी
अदा–ए–दीदे–सरापा नयाज़ है तेरी
किसी को देखते रहना नमाज़ है

उनके कलाम में दर्शन–चिंतन मिलता है. उन पर इस्लाम का गहरा प्रभाव रहा. उन्होंने अतीत के महिमा गान के ज़रिये मुसलमानों को जागरूकता का संदेश दिया:–

कभी ऐ हक़ीक़त–ए–मुंतज़र, नज़र आ लिबास–ए–मजाज़ में
कि हज़ारों सज्दे तड़प रहे हैं तेरी जबीन–ए–नियाज़ में
तरब आशना–ए–ख़रोश हो तू नवा है महरम–ए–गोश हो
वो सरूद क्या के छिपा हुआ हो सुकूत–ए–पर्दा–ओ–साज़ में
तू बचा–बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना
कि शिकस्ता हो तो अज़ीज़तर है निगाह–ए–आईना–साज़ में
न कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली
मेरे जुर्म–ए–ख़ानाख़राब को तेरे उफ़्वे–ए–बंदा–नवाज़ में
न वो इश्क़ में रहीं गर्मियां न वो हुस्न में रहीं शोख़ियां
न वो ग़ज़नवी में तड़प रही न वो ख़म है ज़ुल्फ़–ए–अयाज़ में
मैं जो सर–ब–सज्दा कभी हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा
तेरा दिल तो है सनम–आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज़ में...

उनकी नज़्मों और ग़ज़लों में सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है:–

सच कह दूं ऐ ब्रह्मन गर तू बुरा न माने
तेरे सनम क़दों के बुत हो गए पुराने
अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा
जंग–ओ–जदल सिखाया वाइज़ को भी ख़ुदा ने

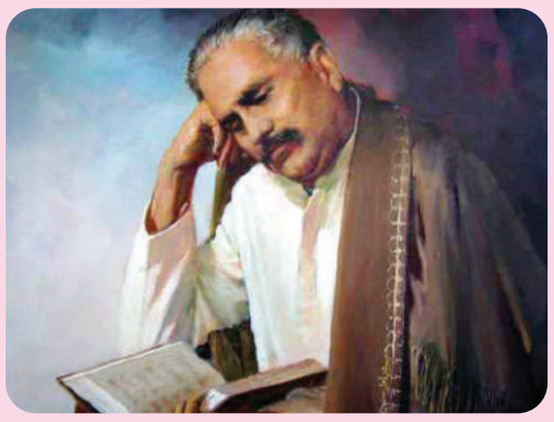

तंग आके आख़िर मैंने दैर–ओ–हरम को छोड़ा
वाइज़ का वाज़ छोड़ा, छोड़े तेरे फ़साने
पत्थर की मूरतों में समझा है तू ख़ुदा है
ख़ाक–ए–वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है
आ ग़ैरत के पर्दे इक बार फिर उठा दें
बिछड़ों को फिर मिला दें नक़्श–ए–दुई मिटा दें
सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती
आ इक नया शिवाला इस देस में बना दें
दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ
दामान–ए–आस्मां से इसका कलश मिला दें
हर सुबह मिलके गाएं मंतर वो मीठे–मीठे
सारे पुजारियों को मय प्रीत की पिला दें
शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है
धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है

उनके कई काव्य संग्रह हैं, जिनमें फ़ारसी का 1917 में प्रकाशित रुमुज़े–बेख़ुदी, 1923 में पयामे–मशरिक़, 1927 में ज़बूरे–अजम, 1932 में जावेदनामा, 1936 में पास चेह बायद कर्द ए अक़वामे–शर्क़ 1938 में अरमुगाने–हिजाज़, 1924 में उर्दू काव्य संग्रह बांगे–दरा, 1935 में बाले–जिब्राइल और 1936 में ज़र्बे–कलीम शामिल हैं. इक़बाल मर्दे–मोमिन ख़ुदा के मुक़ाबले में अपनी श्रेष्ठता जताने में भी गुरेज़ नहीं करते. उनकी फ़ारसी की नज़्म ख़ुदा और इंसान को ही लीजिए:–

ख़ुदा इंसान से–

मैंने मिट्टी और पानी से एक संसार बनाया
तूने मिस्र, तुर्की, ईरान और तातार बना लिए
मैंने धरती की छाती से लोहा पैदा किया
तूने उससे तीर, ख़ंजर, तलवारें और नेज़े ढाल लिए
तूने हरी शाख़ाएं काट डालीं और फैलते हुए पेड़ तोड़ गिराए
गाते हुए पक्षियों के लिए तूने पिंजरे बना डाले

इंसान ख़ुदा से–

तूने ऐ मेरे मालिक! रात बनाई, मैंने दीए जलाए
तूने मिट्टी पैदा की, उससे प्याले बनाए
तूने धरती को वन, पर्वत और मरुस्थल प्रदान किए
मैंने उनमें रंगीन फूल खिलाए, हंसती हुई वाटिकाएं सजाईं
मैं विष से तिरयाक़ बनाता हूं और पत्थर से आईनाश
ऐ मालिक! सच–सच बता, तू बड़ा है या मैं?

21 अप्रैल, 1938 को यह महान शायर हमारे बीच से चला गया. उनकी मौत के बाद दिल्ली की जौहर पत्रिका के इक़बाल विशेषांक में महात्मा गांधी का एक पत्र छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, डॉ. इक़बाल मरहूम के बारे में क्या लिखूं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि जब उनकी मशहूर नज़्म हिंदोस्तां हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया और मैंने बड़ौदा जेल में तो सैकड़ों बार इस नज़्म को गाया होगा. बेशक, इक़बाल का कलाम शायरों और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा. ■

किताब मिली

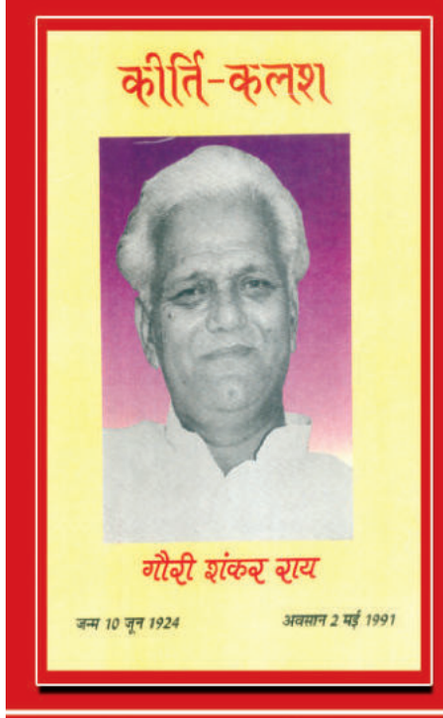

पुस्तक का नाम
कीर्ति कलश
संपादक
ईश्वर देव मिश्र
प्रकाशक
गौरी शंकर राय स्मृति समिति
मूल्य
300 रुपये

इस पुस्तक में समाजवादी आंदोलन से जुड़े स्वर्गीय गौरी शंकर राय द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लिखे गए आलेख और उनके बारे में अन्य लोगों द्वारा लिखे गए आलेख शामिल हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

केवल हेडफोन से ही नहीं, लोग घर पर हों तो बढ़िया क्वालिटी का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं.

आईबॉल का टैबलेट पीसी

एंड्रॉएड 2.3 से चलने वाले इस टैबलेट में 8 जीबी की मेमोरी दी गई है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें मेमोरी एक्सपेंशन की भी सुविधा है.

दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट आकाश के भारत में लांच होने के बाद भारतीय मार्केट में टैबलेट की जंग तेज़ हो गई है. देश में एक और सस्ता एंड्रॉएड टैबलेट लांच हुआ है. डिजिटल लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट के लिए मशहूर आईबॉल ने स्लाइड पीसी टैबलेट बाज़ार में उतारा है. इसकी स्क्रीन 7 इंच है. इस टैबलेट में 1 गीगा हर्ट्ज एआरएम कार्टेक्स ए8 प्रोसेसर लगाया गया है, जिससे इसकी स्पीड में कोई बाधा नहीं पड़ती है.

एंड्रॉएड 2.3 से चलने वाले इस टैबलेट में 8 जीबी की मेमोरी दी गई है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें मेमोरी एक्सपेंशन की भी सुविधा है. इसकी मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. 7 इंच की इस टैबलेट में वाई–फाई, ब्लूटूथ जैसी कनेक्टिविटी के साथ 3जी कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी गई है. दूसरे बड़े अन्य टैबलेट और लैपटॉप इत्यादि की तरह इसमें भी अपने कंफर्ट के हिसाब से यूएसबी के माध्यम से माउस और की–बोर्ड भी लगाया जा सकता है.

इसमें 4,400 एमएएच की बैट्री लगाई गई है, जिससे 6.5 घंटे का संगीत और 5 घंटे तक वीडियो चलाई जा सकती है. इसमें ड्युअल कैमरा ऑपशन है, जिसमें एक वीजीए कैमरा भी दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा दिया गया है. इसे टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए एचडीएमआई पोर्ट भी दिया गया है. इतनी सारी ख़ूबियों के साथ आईबॉल स्लाइड आई–7218 तक़रीबन 12,449 रुपये में उपलब्ध है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ट्रिपल सिम मोबाइल फोन

गैजेट लवर्स को हर वक़्त इंतज़ार रहता है कि कोई नया प्रयोग हो और उन्हें न केवल इसकी जानकारी मिले, बल्कि जल्द से जल्द उचित क़ीमत पर बाज़ार में उपलब्ध भी हो. भारत में ड्युअल सिम फोन का चलन अब आम हो चुका है. ज़्यादातर स्मार्टफोन में ड्युअल सिम की सुविधा के साथ कई फीचर दिए जा रहे हैं, मगर क्या कभी आपने ट्रिपल सिम फोन के बारे में सुना है. एक्सएज ने हैंडसेट बाज़ार में नया ट्रिपल सिम फोन लांच किया है, जिसमें यूजर जीएसएम और सीडीएमए दोनों में से कोई भी नेटवर्क का प्रयोग कर सकता है. एम288 जील नाम से लांच किए गए नए हैंडसेट में 2.2 इंच की कलर स्क्रीन है, जो 1280/960 पिक्सल रेज्योलूशन देती है और 1.3 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है. कंपनी का दावा है कि फोन में दी गई 2000 एमएएच की बैटरी 12 घंटे का बैकअप प्रोवाइड करती है. इतना ही नहीं कम क़ीमत के बावजूद फोन में 8 जीबी मैमोरी एक्सपैंड करने का ऑप्शन दिया गया है. कंपनी ने फोन को सिल्वर ब्लैक, रेड ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लांच किया है. अगर आप ट्रिपल नेटवर्क का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक्सएज एम288 भारतीय बाज़ार में 3,915 रुपये में उपलब्ध है. एक्सएज एम288 में ब्लूटूथ, वाईफाई सपोर्ट दिए गए हैं. यह विशेष फोन मात्र 3,915 रुपये में उपलब्ध है. ■

एलजी के नए प्रोजेक्टर

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सून क्वोन ने कहा कि भारत में इन दो मॉडलों के लांच होने से एलजी का फोकस अपने पोर्टफोलियो के विस्तार पर होगा. कंपनी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं. इन उत्पादों में ऐसी ख़ूबियां और तकनीक होती हैं, जो उपभोक्ताओं का जीवन आरामदायक बनाती हैं.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में दो हाई ब्राइटनेस प्रोजेक्टर बीएक्स503बी और बीएक्स403बी लांच करके नई ऊंचाई हासिल की है. ये हाई रेज्योलूशन प्रोजेक्टर डीएलपी तकनीक का इस्तेमाल करके शार्ट प्रोजेक्शन डिस्टेंस देते हैं. डीएलपी तकनीक से लैस इन प्रोजेक्टर का रंग फीका नहीं पड़ता है और इन्हें लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है. साथ ही इनमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्टर फ्री डिजाइन पर आधारित है, यानी बार–बार फिल्टर बदलने और इसे साफ़ करने का कोई झंझट नहीं. इससे न केवल सपोर्ट स्टाफ का समय बचेगा, बल्कि कंपनियों और स्कूलों का पैसा भी बचेगा.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सून क्वोन ने कहा कि भारत में इन दो मॉडलों के लांच होने से एलजी का फोकस अपने पोर्टफोलियो के विस्तार पर होगा. कंपनी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं. इन उत्पादों में ऐसी ख़ूबियां और तकनीक होती हैं, जो उपभोक्ताओं का जीवन आरामदायक बनाती हैं. ये प्रोजेक्टर 1024/768 का एक्सजीए नेटिव रेज्योलूशन और 2800:1 का कंट्रास्ट अनुपात देते हैं. बीएक्स503बी में 5000 एएनएसआई ल्यूमेंस है, जबकि बीएक्स403बी में 4000 एएनएसआई ल्यूमेंस है. इन प्रोजेक्टरों में छह सेगमेंट कलर व्हील हैं, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता, रंग और रंगों की विविधता साफ़ देखी जा सकती है. बीएक्स503बी और बीएक्स403बी में एचडीएमआई 1.3वी डीप कलर ख़ूबी है, जिससे स्क्रीन पर सभी रंग पूरी तरह उभरकर आते हैं.

इन प्रोजेक्टरों में इस्तेमाल की गई शानदार तकनीक की बदौलत हर तस्वीर शानदार और पूरी रंगत में दिखती है. वीआईडीआई तकनीक वीडियो की क्वालिटी में सुधार के साथ डार्क पल्स के कारण बेहतर कंट्रास्ट आता है और लाइट कंट्रोल बेहतर बनता है. दोनों प्रोजेक्टर लैन सुविधा से लैस हैं और लैंप की सामान्य मोड में क्षमता 2000 घंटे और इको मोड में 2500 घंटे है. साथ ही इनमें क्विक ऑन/ऑफ की सुविधा भी है. इससे ख़ाली समय में ऊर्जा की बचत हो सकती है. इन प्रोजेक्टरों की पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन है और ये होम थिएटर के लिए आदर्श हैं. दोनों प्रोजेक्टरों का वज़न 5.8 किलोग्राम है और इनमें फ्रंट एक्जॉस्ट तथा ऑटो एल्टीट्यूड डिटेक्शन सुविधा है. इनकी क़ीमत क्रमश: 165000 रुपये और 110000 रुपये है.■

दमदार सबवूफर स्पीकर

आजकल जिधर देखिए उधर कानों में हेडफोन लगाए हर उम्र, वर्ग के लोग नज़र आ जाएंगे. कोई काम करते समय, कहीं ट्रेवल करते समय, किसी बहस के दरम्यान या कोई भी रास्ता तय करते हुए, किसी की बात इग्नोर करने के लिए या कहीं और, और तो और अपना ध्यान काम में लगाने के लिए भी लोग कान में हल्का म्यूजिक बजते रहना पसंद करते हैं.

यह आदत बच्चे या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को भी है. यूं कह सकते हैं कि म्यूजिक आजकल हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है. केवल हेडफोन से ही नहीं, लोग घर पर हों तो बढ़िया क्वालिटी का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. इसके लिए चाहिए बढ़िया म्यूजिक सिस्टम जिसके साथ लगा स्पीकर और वूफर्स साउंड क्वालिटी को और भी बेहतर बना दें. बाज़ार के इसी ट्रेंड को देखते हुए बार्वस और विल्किन ने ऑडियो बाज़ार में नए पीवी 1 डी सबवूफर लांच किए हैं. स्टाइलिश लुक और नई तकनीक के साथ सबवूफरों में, वूफरों में ब्रांड न्यू लिड डिसप्ले की सुविधा दी गई है. कंपनी ने स्पीकरों को व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ लांच किया है. स्पीकरों को सीधे टीवी और ऑडियो प्लेयर से कनेक्ट किया जा सकता है. क़ीमत के मामले में यह अन्य सबवूफरों से काफ़ी महंगे हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते है तो बार्वस और विल्किन के नए सबवूफर आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये बाज़ार में 24,665 रुपये की अनुमानित क़ीमत में उपलब्ध हैं. ■

सस्ता कीबोर्ड और माउस

अगर आप बाज़ार में कोई भी कीबोर्ड लेने जाएंगे तो वह 600 रुपये की शुरुआती क़ीमत से कम नहीं मिलेगा, मगर लेट्स बाय डॉट कॉम द्वारा मात्र 399 रुपये में आप फ्रंटटेक कीबोर्ड के साथ माउस भी ख़रीद सकते हैं.पीसी एसेसरीज बनाने वाली फ्रंटटेक भारतीय बाज़ार की जानी मानी कंपनी है.

ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज आजकल युवाओं में बढ़–चढ़कर देखने को मिल रहा है. इस पर लगातार आते नए ऑफर और प्राइस कम्पैटिबिलिटी भी इसकी एक ख़ास वजह है. अगर आप बाज़ार में कोई भी कीबोर्ड लेने जाएंगे तो वह 600 रुपये की शुरुआती क़ीमत से कम नहीं मिलेगा, मगर लेट्स बाय डॉट कॉम द्वारा मात्र 399 रुपये में आप फ्रंटटेक कीबोर्ड के साथ माउस भी ख़रीद सकते हैं.

पीसी एसेसरीज बनाने वाली फ्रंटटेक भारतीय बाज़ार की जानी मानी कंपनी है. इसलिए क्वालिटी पर भरोसा कर सकते हैं. कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की के साथ–साथ न्यूमरिक की भी दी गई हैं. कीबोर्ड के साथ दिया जाने वाले फ्रंटटेक माउस में 3डी वॉयर कनेक्टर दिया गया है. इसके अलावा माउस 800 डीपीआई सपोर्ट दिया गया है. माउस का साइज देर तक काम करने के लिहाज़ से बनाया गया है. फ्रंटटेक 1665 कीबोर्ड माउस ब्लैक और रेड कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है. यह यूएसबी इंटरफेस पर काम करती है. इसका आकार ऐसा है कि यह ज़्यादा जगह नहीं लेती और इस्तेमाल में भी काफ़ी कंफर्टेबल है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

गांव की मिट्टी और देश का गौरव

नवीन चौहान
navinchauhan@chauthiduniya.com

हाल में दीपिका कुमारी ने तीरंदाज़ी विश्वकप में स्वर्ण पदक जीता. वह भी लंदन ओलंपिक खेलों के आयोजन के कुछ महीने पहले. देशवासी दीपिका से ओलंपिक मेडल की आस लगाने लगे हैं. आस लगाने वालों में हमारी सरकार भी शामिल है. खिलाड़ी पदक जीतते ही देश के लाल हो जाते हैं, सरकार कुछ दिन तक खिलाड़ियों का गुणगान करती है. खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं की बात होती है और फिर वही ढाक के तीन पात वाली हालत हो जाती है. परिणामस्वरूप खिलाड़ी गुमनामी में अपना जीवन गुज़ारने लगते हैं.

स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल केडी जाधव ने जीता था. महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के गांव कराद के रहने वाले जाधव ने 1952 में हेलंसिकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, लेकिन तब भी जाधव को भेदभाव पूर्ण चयन और पैसे की कमी से जूझना पड़ा था. तब जाधव 7000 रुपये में अपना मकान गिरवी रखकर ओलंपिक में भाग लेने गए थे और पदक जीतकर देश को गौरान्वित किया था. जाधव ने महाराष्ट्र पुलिस में इंसपेक्टर के रूप में काम किया. उनका बुढ़ापा बदहाली में गुज़रा और गुमनामी में ही वह पंचतत्व में विलीन हो गए.

1951 में भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ. आज़ादी मिलने के बाद पहली बार देश कोई आयोजन कर रहा था. इस आयोजन के बाद देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिली, लेकिन खेलों के विकास के लिहाज़ से कुछ नहीं हो सका और न ही देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो पाया. जाधव के ओलंपिक पदक जीतने के 56 साल बाद लिएंडर पेस देश के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने में कामयाब हुए. ऐसा नहीं था कि भारतीय एथलीट अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे. खिलाड़ी अपने दम पर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे आयोजनों में पदक जीत रहे थे, मगर वे ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि खेल के अलावा तब खिलाड़ियों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था. आज़ादी के 65 साल बाद भी भारत सरकार खेलों के विकास में जीडीपी का लगभग आधा प्रतिशत भी निवेश नहीं करती है, जबकि अन्य देश अपनी जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत खेलों के विकास में लगाते हैं. आज़ादी के बाद भारत में ओलंपिक में भाग लेने को ही सम्मान का विषय समझा जाता था. जीत को वरीयता नहीं दी जाती थी, लेकिन इससे पहले हम जीतने से ज़्यादा हारने की तैयारी रखते थे. हमारे पास हारने के कई बहाने होते थे. कभी हम अपनी कमज़ोर शारीरिक बनावट का बहाना बनाते थे, तो कभी संसाधनों की कमी का, तो कभी पैसों और प्रायोजकों की कमी का.

2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेल भारत के लिए सबसे अच्छे परिणाम लेकर आए. भारत को कुल तीन पदक मिले. पदक जीतने वालों में अभिनव बिंद्रा को छोड़ दिया जाए तो अन्य दो पदक जीतने वाले खिलाड़ी गांव से जुड़े हुए हैं. सरकार शहरों में तो खेलों के मैदान बना रही है, मगर गांवों और छोटे शहरों में संसाधनों की कमी है. न ही गांवों और छोटे शहरों में समतल खेल के मैदान हैं और न वे संसाधन, जिनसे शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जा सके. इन बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2008 में पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान की शुरुआत की थी. खेल के मैदान के समतलीकरण की योजना को मनरेगा से भी जोड़ा गया. इस अभियान के तहत गांवों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रावधान है. मगर पंचायत युवा खेल एवं क्रीड़ा अभियान को भी भ्रष्टाचार का कीड़ा लग गया और चार साल बाद भी अच्छे परिणाम नहीं आए. गांवों में न ही खेल के मैदानों का निर्माण हो सका और न ही प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सका. एक ओर गांवों में सरकारी ज़मीनों पर क़ब्ज़े की वजह से मैदानों के निर्माण के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, दूसरी ओर दस हज़ार रुपये में ख़रीदे जाने वाले सामानों की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है. इस योजना में भी अन्य सरकारी योजनाओं की तरह पैसे की बंदरबांट हो रही है. सरकार काग़ज़ों में तो योजना बना रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है.

संवैधानिक रूप से खेल राज्य सूची का विषय है. राज्य भी खेलों के विकास के लिए कोई विशेष काम करते नहीं दिख रहे हैं. राज्य हमेशा पैसों की कमी को लेकर रोने बैठ जाते हैं. केंद्र से खेलों के विकास के लिए पैसे मिलने के बाद भी राज्य कोई काम करते नहीं दिखाई देते हैं. वे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में वर्षों लगा देते हैं. इन सभी की वजह से नुक़सान देश को ही होता है. हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सरकारें खेलों पर ध्यान दे रही हैं. दूसरे राज्यों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, नहीं तो हमेशा की तरह ओलंपिक में सवा अरब की आबादी वाला देश कुछ मेडलों के लिए भी तरसता नज़र आएगा. चीन और अमेरिका जैसे देशों के सामने खेलों के मामले में आर्थिक ताक़त बनकर भी भारत बौना ही नज़र आएगा.■

कृष्णा ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड

भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया ने अमेरिका के हवाई में हुई एल्टियस ट्रैक क्रू थ्रोडाउन प्रतियोगिता में रजत पदक जीत कर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. कृष्णा ने 64.76 मीटर दूरी तक डिस्कस फेंका और सीमा अंतिल के 8 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड (64.64 मी.) को तोड़ दिया. प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अमेरिका की स्टेफनी ब्राउन (66.86 मी.) के नाम रहा. कांस्य पदक अमेरिका की जिया लुइस स्मालवुड (63.97 मी.) ने जीता. दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल की स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा ने इस प्रतियोगिता में दो रजत पदक जीते हैं. ■

दीपिका ने स्वर्ण पदक जीता

महिला तीरंदाज़ दीपिका कुमारी ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. दीपिका ने तुर्की में हुई विश्व कप प्रतियोगिता में कोरिया की ली सुंग जिन को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है. यह दीपिका का विश्वकप तीरंदाज़ी में पहला पदक है. दीपिका ने कोरियाई खिलाड़ी को पांच सेट तक चले मुक़ाबले में 6 सेट पॉइंट से हराया. झारखंड की इस युवा तीरंदाज़ के इस प्रदर्शन से लंदन ओलंपिक में पदक जीतने की आशा प्रबल हो गई है. फ़िलहाल दीपिका जूनियर विश्व चैंपियन हैं और लंदन ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी हैं. ■

नरसिंह को ओलंपिक टिकट

नरसिंह यादव लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पांचवें पहलवान हो गए हैं. नरसिंह ने फिनलैंड के हेलंसिकी में हुए विश्व ओलंपिक क्वालीफायर के फाइनल में पहुंचते ही ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया. नरसिंह से पहले सुशील कुमार (66 किग्रा), योगेश्वर दत्त (60 किग्रा), अमित कुमार (55 किग्रा), महिला पहलवान गीता (55 किग्रा) ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. यह नरसिंह के पास ओलंपिक के लिए क्वालीफाइ करने का आख़िरी मौक़ा था. और वो इस प्रयास में सफल रहे ■

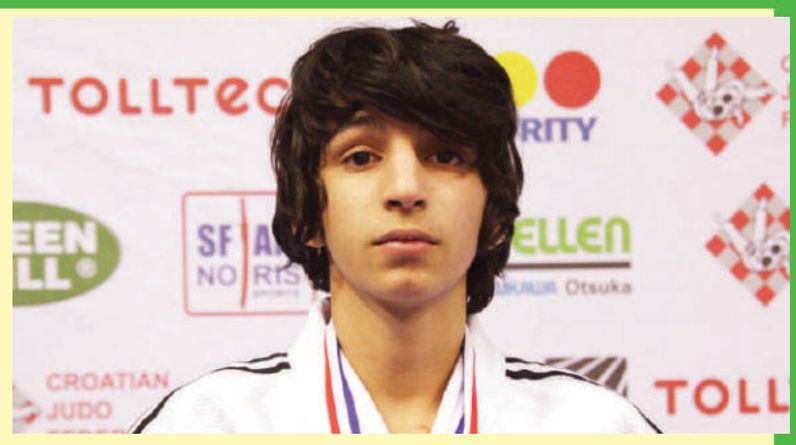

गरिमा ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया

उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई एशियन जूडो प्रतियोगिता में सातवें स्थान पर रहने के बावजूद गरिमा चौधरी ने ओलंपिक के लिए वरीयता हासिल कर ली है. गरिमा लंदन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ की नई रैंकिंग के आधार पर गरिमा ने ओलंपिक में 63 किग्रा वर्ग प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालीफाई किया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली गरिमा ओलंपिक में अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं. भारतीय जूडो संघ ने गरिमा को प्रशिक्षण के लिए ओलंपिक से पहले क्यूवा भेजने का फ़ैसला किया है.■

खेल के दौरान महिला हॉकी खिलाड़ी की मौत

ऑस्ट्रेलिया में एक महिला हॉकी खिलाड़ी की सिर में चोट लगने की वजह से मौत हो गई. क्लब मैच के दौरान नार्थ कोस्ट रेडिस्ट की तरफ़ से खेलते हुए 24 वर्षीय एलिजाबेथ वाटकिंस के सिर पर गेंद लगी और वह बुरी तरह घायल हो गईं. उन्हें उसी वक़्त अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Hockey Australia

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 21 मई–27 मई 2012

सिनेमा प्रेमी बुज़ुर्ग बताते हैं कि 60 और 70 के दशक के मध्य में टिकटों का मूल्य सिर्फ़ साठ या सत्तर पैसे ही होता था. अंग्रेज़ी फिल्में केवल ख़ास जगहों पर ही लगती थीं और उनके भी कुछ ही शो होते थे.

सिनेमाघरों से जुड़ी खट्टी-मीठी यादें

दर्शन शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

देश का ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा, जहां के लोगों की सिनेमा से जुड़ी कोई मीठी याद न हो. हर मोहल्ले में कोई न कोई बीना दीदी ज़रूर होती थी, जो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा कर पास के सिनेमाघर में फिल्म दिखाने ले जाती थी. सुना है, जब धार्मिक फिल्म जैसे जय संतोषी माता लगती तो महिलाओं का रेला फिल्म देखने जाता था. धार्मिक फिल्म देखने के लिए महिलाएं पैर धोकर ही सिनेमा घर में प्रवेश करती थीं. पुरुषों में भी कई बनारसी भैया होते थे, जो बीती रात फिल्म देखकर आते और अगली दोपहर चौक पर बैठकर उस फिल्म की कहानी सबको सुनाते, जिसे सुनकर बाक़ी लोग भी फिल्म देखने जाते. लड़कियों में कोई न कोई बहानेबाज़ गुड्डी होती, जो सभी सहेलियों को बहाने बताकर उनके लिए फिल्म देखना आसान करती. कॉलेज में लड़कों का फैशन और प्यार का पैशन भी फिल्मों की प्रेरणा से होता था. फिल्मों में दिखाई गई कई प्रेम कहानियां तो कई प्रेम युगलों की प्रेरणा बन गईं और लोगों ने उसे असल ज़िंदगी में उतार लिया. सिर्फ़ यही नहीं, देशप्रेम, धार्मिक, मार्मिक आदि भावनाएं भी फिल्मों के ज़रिए समाज में प्रवाहित होती थीं. कुछ फिल्में तो पिता अपने बच्चों को ख़ुद दिखाने जाते थे. सिनेमा के ज़रिए एक नई सीख बच्चे के मन में डालने की कोशिश होती थी. सिनेमा लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

सिनेमा के जानकार 50 से 80 के दौर को हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग मानते हैं. धार्मिक, पारिवारिक और साहित्य पर आधारित फिल्मों में मनोरंजन के साथ-साथ संदेश भी होता था. ऐसा सिनेमा जीवन को प्रभावित करता था, तभी देश के विभिन्न शहरों और क़स्बों में सिनेमाघरों का निर्माण तेज़ी से हुआ था. यह पहल सरकार की तरफ़ से भी होती थी. सरकार ने सिनेमा के बढ़ते क्रेज को देखते हुए शहरों और क़स्बों में सिनेमाघर बनवाने शुरू कर दिए थे, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ा था. कई क़स्बों में तो पर्दा तानकर अस्थाई सिनेमाघर बनाकर दर्शकों के लिए फिल्म देखने का इंतज़ाम होता था. जब जय संतोषी मां जैसी धार्मिक फिल्में देखने के लिए जनता उमड़ती थी, तब उन्हें संभाल पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता था. आलम यह होता था कि सिनेमाघरों में नई फिल्म आने से पहले ही टिकट एडवांस में बिक जाते थे. सिनेमा के शौक़ीन ब्लैक में टिकट ख़रीदते थे. पहले टिकट का भी सिस्टम अलग था. जैसे अब पब, डिस्कोथेक या एडवेंचर क्लब में देखने को मिलता है, तब भी इसी तरह टिकट के बदले हाथ पर मोहर लगाई जाती थी.

सिनेमा प्रेमी बुज़ुर्ग बताते हैं कि 60 और 70 के दशक के मध्य में टिकटों का मूल्य सिर्फ़ साठ या सत्तर पैसे ही होता था. अंग्रेज़ी फिल्में केवल ख़ास जगहों पर ही लगती थीं और उनके भी कुछ ही शो होते थे. लखनऊ के बुक सेलर्स के नाम से मशहूर बुज़ुर्ग राम आडवाणी बताते हैं कि लखनऊ के मेफेयर ऑडिटोरियम में पहली हिंदी फिल्म 1939 में लगी थी. मेफेयर के अलावा उस समय दूसरा कोई ऑडिटोरियम नहीं था, जहां अंग्रेज़ी फिल्म लगे और ज़रूरत पड़ने पर मेफेयर में ही फिल्म बंद कर कार्यक्रम आयोजित होते थे. पृथ्वीराज कपूर सहित कई कलाकार यहां आकर कार्यक्रम पेश करते थे. इसके बाद आया मैटिनी शो का चलन. मेफेयर में 4-5 सालों बाद लगने वाली फिल्मों के लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे. उत्तर प्रदेश के पुराने सिनेमाघरों में पर्ल सिनेमाघर का नाम सबसे पहले आता है. इसकी नींव 1911 में पड़ी थी, जिसे इतरौला के नवाब संजू एवं जर्मनी की एक महिला ने बनवाया था. बाद में इसका नाम कोहिनूर एवं रॉयल सिनेमा हो गया. इसमें पहली हिंदी फिल्म अमर ज्योति और अनारकली (मूक) प्रदर्शित हुई थी. क़रीब 70 साल पहले इस सिनेमाघर को ताराचंद बड़जात्या ने भी चलाया था. मशहूर संगीतकार नौशाद हारमोनियम बजाया करते थे. बाद में इसे डीएल मेहरा ने चलाया. लीला सिनेमा के मालिक शिव नारायण अग्रवाल के अनुसार, 1974 में रिलीज हुई फिल्म शोले लीला सिनेमाघर में 52 हफ्ते चली.

तीस साल पहले तक लखनऊ के सिनेमाघरों में भीड़ होती थी, लेकिन अब यह बीते ज़माने की बात हो गई है. कुछ ऐसा ही हाल देश के दूसरे प्रतिष्ठित सिनेमाघरों का है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आधुनिकता ने इन सिनेमाघरों के अस्तित्व को ख़त्म करके रख दिया है. इनकी जगह मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों ने ली है. बची-खुची कसर टेलीविजन, केबल और फिल्मों की आने वाली सीडी ने पूरी कर दी. सिनेमा हॉल्स में पहले जैसा आनंद नहीं रह गया है. जब फिल्म देखने के दौरान लाइट जाने पर सीटियों का शोर मचता था. मल्टीपलेक्सों में वह मज़ा कहां? अब सिनेमाघर लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं. इसका प्रमाण रोज़ाना अख़बारों में आने वाली घटनाओं से मिलता है. पहले के सिनेमाघरों में हर तबक़े के दर्शक आते हैं, जिससे सामाजिक असमानताएं और लोगों के बीच दूरियां कम होती थीं, जबकि मल्टीप्लेक्स में संभ्रांत परिवारों के लोग ही आते हैं तो लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ गईं. समाज अमीर-ग़रीब में विभाजित ही नहीं हुआ, बल्कि एक पाट भी पड़ गई.

लखनऊ की ही तरह देश के अन्य शहरों के सिनेमाघर भी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं. जहां पुराने सिनेमाघर ख़त्म हो रहे हैं, वहीं टीवी और मल्टीप्लेक्स ने कई सिनेमाघरों को चलन से बाहर कर दिया है. कई सिनेमाघर अंतिम सांसें गिन रहे हैं. इसका सबसे बड़ा दर्शकों का टोटा है. टाकीजों में देख-रेख और ख़र्चे बढ़े हैं. मनोरंजन कर का भारी भरकम टैक्स सिनेमा मालिकों को चुकाना पड़ रहा है. ऐसे में सिनेमा मालिक कंगाल होते जा रहे हैं. इन परिस्थितियों में कई मालिकों ने या तो सिनेमाघर बंद कर दिए हैं या बेच दिए अथवा उनकी जगह व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना दिए गए हैं. सिनेमा प्रबंधन में ख़र्च ज़्यादा और आमदनी कम होने लगी है. कुछ में होटल तो कुछ में व्यावसायिक शोरूम बन गए हैं. बदलते दौर ने सिनेमाघर को लोगों के बीच से निकाल दिया गया है, मगर लोगों के दिल से सिनेमाघर को निकाल पाना मुश्किल है. ■

हॉलीवुड

मेन इन ब्लैक

फिल्म मेन इन ब्लैक की पहली कड़ी आई 1997 में और फिर 2002 में बनी इसी फिल्म की दूसरी कड़ी. मेन इन ब्लैक के ऑरिजनल और सिक्वल ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और अब फिर इसी कड़ी की तीसरी फिल्म मेन इन ब्लैक-3 भी लोगों के बीच जादू चलाने को तैयार है. 10 साल बाद आ रही सोनी पिक्चर्स की इस फिल्म मैन इन ब्लैक-3 में निर्देशक बैरी सोंनेनेफेल्ड दो धमाकों को एक साथ लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में पिटबुल का गाना तो है ही, इसके अलावा फिल्म के हीरो हैं विल स्मिथ जो इस फिल्म की पिछली दोनों सीरीज में भी थे. इस फिल्म में पॉप गायक पिटबुल ने विशेष रूप से बैक इन टाइम गीत गाया है. अब देखते हैं कि ये दोनों क्या कमाल करते हैं, क्योंकि संगीत में दिलचस्पी रखने वाले सभी श्रोता गायक पिटबुल के गीत बैक इन टाइम को सुन सकते हैं और विल स्मिथ के अभिनय के दीवाने अभिनय का लुत्फ उठा सकते हैं. विल स्मिथ का नामांकन दो बार अकेडमी अवॉर्ड के लिए हो चुका है. इस फिल्म में विल स्मिथ का साथ देंगे हॉलीवुड के अकेडमी अवॉर्ड विजेता अभिनेता टौमी ली जोंस. इनके अलावा फिल्म में हैं अकेडमी अवॉर्ड से नामांकित अभिनेता जोश ब्रोलिन. 10 साल बाद आ रही सोनी पिक्चर्स की फिल्म मेन इन ब्लैक-3 के निर्माता हैं वाल्टर ऍफ पार्क्स एंड लौरी मैकडोनाल्ड. फिल्म के लेखक हैं इटेन कोहेन, एडिटर हैं डोन ज़िमेरमन. वैसे तो फिल्म में संगीत दिया है डैनी एल्फमेन ने, लेकिन लोकप्रिय पॉप सिंगर पिटबुल ने भी एक गाना विशेष रूप से गाया है बैक इन टाइम. फिल्म की कहानी है एजेंट जे और के की. एजेंट जे एजेंट के की ज़िंदगी और ब्रह्मांड को बचाने के लिए पुराने वक़्त में जाता है, जहां एलियन और खलनायक बोरिस से उसकी भयंकर लड़ाई होती है. आख़िर में वह मानवता को बचाने में कामयाब होता है. 1997 में और 2002 में बनी फिल्म मैन इन ब्लैक ने दर्शकों के दिलो-दिमाग़ पर अपना जादू किया था, लेकिन क्या वही जादू मैन इन ब्लैक-3 भी दर्शकों कर पाएगी? ■

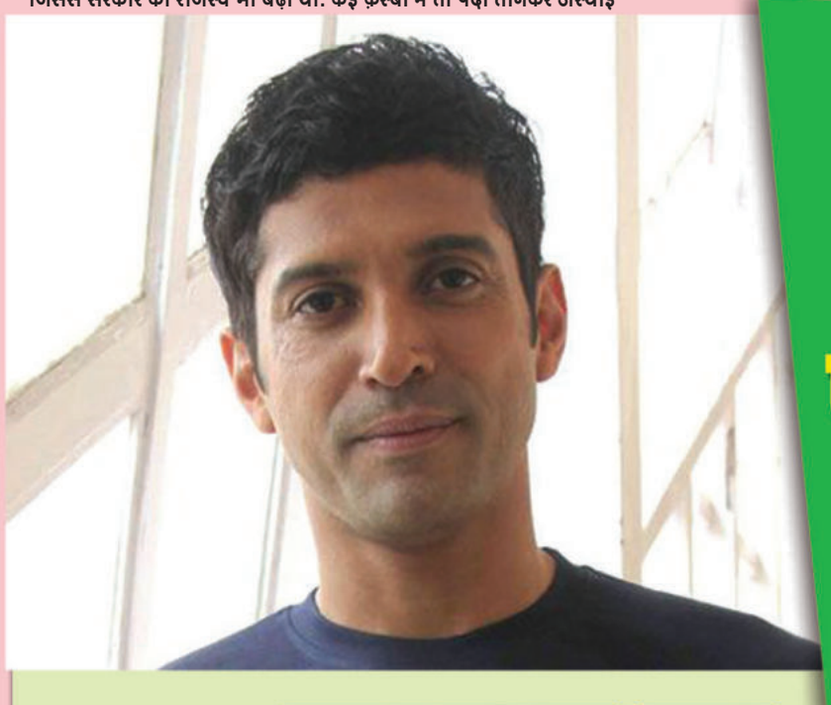

फ़रहान का नया लुक

आपने फिल्म करन अर्जुन का वह डायलॉग ज़रूर सुना होगा, जिसमें सलमान ख़ान शाहरूख़ से कहते हैं भाग अर्जुन भाग, अर्जुन तू भाग... अब हो सकता है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में एक नया डायलॉग सुनने को मिले, जिसमें बॉलीवुड के सह कलाकार निर्देशक और एक्टर फ़रहान अख्तर से कहेंगे, भाग मिल्खा भाग... दरअसल, सुनने में तो यह आया है कि आजकल डैशिंग फ़रहान अख्तर हर संभव कोशिश में है कि कैसे वह अपने लुक को बदलें और 17 साल के किशोर से अपनी बराबरी कर लें. वहीं अगर फ़रहान के नए लुक को देखें तो लगेगा कि फ़रहान में एक ज़बरदस्त बदलाव आया है. अब आप सोच रहे होंगे कि आख़िर ऐसी क्या वजह है, जिसके लिए फ़रहान को एक 17 साल का किशोर बनना पड़ रहा है. चलिए हम आपको बताते हैं कि आख़िर माजरा क्या है. निर्देशक फ़रहान आजकल अपनी आने वाली फिल्म भाग मिल्खा भाग में व्यस्त हैं. वह मशहूर धावक मिल्खा सिंह की जवानी के उन दिनों को परदे पर निभा रहे हैं, जब वह सेना में काम करते थे और उस वक़्त मिल्खा की उम्र महज़ 17 साल थी. अगर फ़रहान के नज़दीकी सूत्रों की मानें तो इस फिल्म में अपने किरदार को एक रियल फील देने के लिए फ़रहान आजकल आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं. फ़रहान की दिन भर की गतिविधियों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वह फिल्म में एक दम रियल फील देने वाले हैं. ख़ैर, जो भी हो, फिल्म दिलचस्प होगी और हम सभी ज़रूर कहेंगे, वाह फ़रहान भाई वाह. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बिपाशा अफ़वाहों से परेशान

बॉलीवुड की एक्ट्रेस बिपाशा बसु अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफ़वाहों से काफ़ी परेशान हो चुकी हैं. अब वह चाहती हैं कि इस तरह की किसी भी बात को मीडिया तूल न दे. बिपाशा ने अपने ट्विटर पर लिखा है, काफ़ी लंबे समय से मेरा नाम कुछ लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है. वक़्त बीतने के साथ ब्रेकअप और फिर से एक होने और शादी की कहानियां बन रही हैं. मैं चाहती हूं कि यह सब रुक जाए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. बिप्स ने कहा कि मौज मस्ती पसंद करने वाले लोगों का मतलब तुच्छ नहीं होता. लोगों से मिलने का मतलब उनके साथ वक़्त गुज़ारना नहीं है. बिपाशा का नाम शाहिद कपूर और राणा दागुबत्ती जैसे अभिनेताओं से जुड़ता रहा है. ख़बर है कि जॉन अब्राहम से अलग होने के बाद बिपाशा अकेली हैं. वहीं जॉन अपनी नई गर्लफ्रेंड प्रिया रूंचाल के साथ शादी के लिए तैयार हैं. वह कह चुके हैं कि वह कभी भी शादी कर सकते हैं.■

चौथी दुनिया

दिल्ली, 21 मई-27 मई 2012

www.chauthiduniya.com

चेवेल्ला परियोजना

क़रार में किसका हित

महाराष्ट्र के शिवणी और आंध्र प्रदेश के तुमडीहेटी गांव के निकट निर्माण होने वाली इस परियोजना से गढ़चिरोली और चंद्रपुर के कुछ इलाक़ों में बाढ़ का ख़तरा पैदा होने की आशंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, जब इस परियोजना को अंतुले सरकार ने खारिज़ कर दिया था. इस परियोजना से सबसे अधिक नुक़सान गढ़चिरोली ज़िले को होने वाला है.

राज्य में बहने वाली प्राणहिता नदी पर प्रस्तावित चेवेल्ला जल परियोजना के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौता हो गया. इस क़रार पर केंद्रीय मंत्री पवन बंसल की उपस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने हस्ताक्षर किए. यह क़रार दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से हुआ. क़रार के अनुसार, इस जल परियोजना में संशोधन और उसे क्रियान्वित करने की कार्यक्षमता, निर्माण कार्य तेज़ी एवं किफ़ायत के साथ करने की प्रक्रिया को निश्चित करने और दोनों राज्यों के हितों का ध्यान रखने के लिए संयुक्त मंडल एवं समिति गठित करने का निर्णय लिया गया. यह मंडल जल परियोजना निर्माण के लिए स्थान का चयन और सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिस आधार पर निर्माण कार्य शुरू होगा. इस समिति को दोनों राज्यों में प्राणहिता नदी के संबंधित मामलों को देखने का पूरा अधिकार रहेगा.

ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण और जे वेंगला राव के बीच 6 अक्टूबर, 1975 को हुई बैठक की कार्यवाही के अनुसरण और गोदावरी जल विवाद पंचाट 1980 की रिपोर्ट की परिशिष्ट-ब में शामिल लेंडी प्रकल्प, लोअर पेनगंगा और प्राणहिता सहित तीन सिंचाई परियोजनाओं का काम दोनों सरकारों के संयुक्त उपक्रम के रूप में करने का निश्चय किया गया था. इनमें लेंडी एवं लोअर पेनगंगा परियोजनाओं का कार्य हुआ, लेकिन प्राणहिता जल परियोजना पर सहमति नहीं बन पाई थी. संभवत: इसलिए प्राणहिता चेवेल्ला जल परियोजना के प्रस्ताव को 13 मई, 1981 को राज्य की एआर अंतुले सरकार ने ख़ारिज कर दिया था. उसके बाद अब चेवेल्ला परियोजना के निर्माण पर नए सिरे से क़रार हुआ है. हालांकि आंध्र प्रदेश में चेवेल्ला जल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू है. वैसे आंध्र प्रदेश सरकार को यह पता था कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग के बिना यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी नहीं हो सकती. चूंकि इस परियोजना से सबसे अधिक लाभ तेलंगाना क्षेत्र को होना है. वहां पृथक तेलंगाना आंदोलन भी चल रहा है. इसलिए वहां की सरकार को इस बात की जल्दी है कि वह इस परियोजना को पूरा कर यह साबित करे कि वह तेलंगाना के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है. उसे तेलंगाना के किसानों की चिंता है. बात रही इस क़रार से महाराष्ट्र के हितों की तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है. बीती 5 मई को हुआ क़रार सिर्फ़ प्राणहिता परियोजना के संदर्भ में विविध मुद्दों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय मंडल या समिति के गठन के लिए है. इसमें परियोजना का निर्माण किस जगह पर किया जाएगा और जल नियंत्रण और पानी के उपयोग एवं डूबित क्षेत्र आदि के विषय में कुछ नहीं कहा गया है. इन मुद्दों को समिति द्वारा अन्वेषण एवं सर्वेक्षण करने के बाद दोनों राज्यों की सहमति से सुलझाने की बात कही गई है. अभी तक उक्त मुद्दों के विषय में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है. गठित होने वाली अंतरराज्यीय मंडल अथवा समिति का अध्यक्ष क्रमश: दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे. साथ ही दोनों राज्यों के जल संसाधन, ऊर्जा, वित्त, वन विभाग के मंत्री, सचिव और कार्यकारी संचालक एवं मुख्य अभियंता सदस्य होंगे. इनमें एक सदस्य केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का प्रतिनिधि रहेगा. अंतरराज्यीय मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रभावी तरीक़े से अमल करने के लिए अधिकारी स्तर की स्थायी समिति गठित करने का भी निर्णय इस क़रार में किया गया है. इस समिति का अध्यक्ष आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्रालय के प्रधान सचिव बारी-बारी से रहेंगे. समिति अध्यक्ष का कार्यकाल एक साल का रहेगा. साथ ही दोनों राज्यों के अन्य संबंधित विभागों के सचिव, कार्यकारी संचालक, संबंधित मुख्य अभियंता इस स्थायी समिति के सदस्य होंगे. प्राणहिता नदी पर निर्माण होने वाली परियोजना से दोनों राज्यों को पानी मिलना है. आंध्र प्रदेश शासन ने अपने हिस्से का पानी डॉ. बीआर आंबेडकर प्राणहिता-चेवेल्ला श्रवंती परियोजना में नियोजित किया है. चूंकि यह परियोजना आंध प्रदेश के हिस्से के पानी का उपयोग करने पर आधारित है, इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकेगा. वहीं प्राणहिता नदी पर बांध बनाने पर दोनों राज्य पहले से ही सहमत हैं. प्राणहिता जल परियोजना को अंतिम रूप देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नदी में अधिक से अधिक पानी रहे, कम से कम ज़मीन डूबे, डूबित ज़मीन का उचित मुआवज़ा मिले. महाराष्ट्र को इसका अधिक लाभ मिले और बांध के पानी पर राज्य का अधिकार अबाधित रूप से रहे. इस बाबत अंतरराज्यीय मंडल और स्थायी समिति में शामिल महाराष्ट्र के प्रतिनिधि पूरी तरह सजग रहेंगे.

ग़ौरतलब है कि इस क़रार के बाद राज्य में राजनीति भी होने लगी है और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा जल्दबाज़ी में हस्ताक्षर करने पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेलंगाना आंदोलन के कारण आंध्र सरकार यह क़रार करने में जल्दीबाज़ी दिखा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को क्या जल्दी थी. जिस ज़िले में इस परियोजना को साकार होना है, उस ज़िले के पालक मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना ज़रूरी नहीं समझा गया. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री ने यह हस्ताक्षर केंद्र के दबाव में किया हो. इसकी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना की आधारशिला 31 जनवरी, 2007 में रखी थी. उनके निधन के बाद उनके पुत्र द्वारा कांग्रेस सरकार को निरंतर चुनौती मिल रही है. यह परियोजना वर्धा और वैनगंगा नदी के संगम में दोनों राज्यों की सीमा पर साकार होनी है. इसलिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस जल परियोजना पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव तो नहीं डाला गया. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान के वफ़ादार रहे स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगनमोहन रेड्डी वहां बग़ावत कर कांग्रेस के लिए चुनौती बन गए हैं. इसलिए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं इस जलपरियोजना का हश्र भी पोलवरम परियोजना की तरह न हो जाए. यहां सवाल यह है कि इस परियोजना से राज्य को क्या मिलेगा? इस सवाल पर बहस भी शुरू हो गई है. विदर्भ वैधानिक विकास मंडल के विशेषज्ञ सदस्य और पूर्व मंत्री मधकर किम्मतकर का कहना है कि गोदावरी की उप नदी प्राणहिता के पानी पर आंध्र प्रदेश सकार की नज़र है. इस बाबत प्रदेश सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की परियोजना पर काम भी शुरू कर दिया है.

आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पानी के उपयोग के लिए सहमति बनाने हेतु अंतरराज्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना करने की क़वायद भी शुरू हो गई है. इतना होने के बाद भी राज्य सरकार गंभीर नहीं है. उन्होंने विदर्भ के सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को आगाह किया है कि वे नींद से जागें और विदर्भ के हित के लिए लड़ाई लड़ें, वरना विदर्भ में मौजूद संसाधनों का दोहन दूसरे लोग करेंगे. इसके अलावा यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि चेवेल्ला परियोजना के साकार होने से गढ़चिरोली-चंद्रपुर ज़िले की कई तहसीलें प्रभावित होंगी. प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में गढ़चिरोली के चामोर्शी अहेरी, सिंरोचा, चंद्रपुर ज़िले के गोंडपिपरी और राजुरा के नाम हैं. साथ ही चपराला अभ्यारण्य के डूबने की बात भी कही जा रही है. इस परियोजना से जितना पानी विदर्भ के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा, उससे कहीं अधिक नुक़सान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. यह बात ज़रूर है कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के सात ज़िलों के 95 मंडलों के 1742 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा. इसके अलावा हैदराबाद और सिंकदराबाद को पेयजल के अलावा वहां के औद्योगिक क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा सकेगी. इसलिए आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता पी लक्ष्मया ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताते हुए ख़ुशी ज़ाहिर की. इतना ही नहीं, इस क़रार का स्वागत प्रदेश के विपक्षी नेताओं ने भी किया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह समझौता तेलंगाना के विकास में अहम भूमिका निभाएगा. इसका सीधा मतलब है कि इस क़रार से जहां आंध्र प्रदेश के नेताओं में ख़ुशी है, वहीं महाराष्ट्र में स्थिति ठीक विपरीत है. यहां राज्य के जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में हुए इस क़रार की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जो कुछ पता चला वह मीडिया की मार्फ़त ही चला. हालांकि इस पर यक़ीन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके मंत्रालय की कोई भी फाइल उनकी मर्ज़ी के बिना इधर से उधर नहीं हो सकती. उनकी दलील चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ़ है कि राज्य में शीर्ष स्तर के नेताओं के बीच समन्वय नहीं है. महाराष्ट्र के शिवणी और आंध्र प्रदेश के तुमडीहेटी गांव के निकट निर्माण होने वाली इस परियोजना से गढ़चिरोली और चंद्रपुर के कुछ इलाक़ों में बाढ़ का ख़तरा पैदा होने की आशंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, जब इस परियोजना को अंतुले सरकार ने ख़ारिज कर दिया गया था. इस परियोजना से सबसे अधिक नुक़सान गढ़चिरोली ज़िले को होने वाला है. वहां अहेरी, सिरोंचा, चामोर्शी के गांव डूब क्षेत्र में आएंगे. साथ ही चंद्रपुर के गोंडविपरी और राजुरा में भी बाढ़ आने का ख़तरा बढ़ सकता है. ऐसे में प्राणहिता नदी के किनारे बसे गांवों को सबसे अधिक नुक़सान उठाना पड़ सकता है. नदी पर बांध बनने के बाद प्राणहिता का पानी नहरों के माध्यम से आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा. इस पानी का संग्रह करीमनगर स्थित येल्लमपल्ली जलाशय में किया जाएगा. उसके बाद चेवेल्ला में यह पानी पहुंचेगा. इस परियोजना के पूर्ण होने पर तेलंगाना में पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को राहत तो मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र को लाभ से अधिक नुक़सान होगा. जब प्राणहिता का पानी आंध्र प्रदेश जाने लगेगा तो उसकी सहायक नदियों का प्रवाह कमज़ोर पड़ेगा. ऐसे में जब प्राणहिता के पानी में कमी आएगी तो सिरोंचा, आसरअल्ली और अंकिसा क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. फ़िलहाल प्राणहिता के पानी के भरोसे ही इस क्षेत्र में धान, कपास, तंबाकू और मिर्च की फ़सल पैदा की जाती है. इन बातों का गुणा-भाग पता नहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया है कि नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें पारदर्शिता की बेहद कमी है. असल में इससे प्रभावित ज़िलों के जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर यह क़रार किया गया है. लिहाज़ा जो आशंकाएं राज्य के लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, वह सही हैं, लेकिन एक बार फिर राज्य में पुनर्वास की एक नई समस्या जन्म ले रही है, जबकि पहले से ही राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं के विस्थापितों का अब तक पुनर्वास नहीं किया जा सका है. अब यह नई समस्या खड़ी हो रही है. इसलिए इस परियोजना के निर्माण की राह भविष्य में आसान नहीं हो सकेगी. मुख्यमंत्री द्वारा इस क़रार पर हस्ताक्षर करने से सभी लोग अचंभित हैं. लिहाज़ा उसकी राह में अड़चनों का आना लाज़िमी है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में इस परियोजना को साकार होना है वह आदिवासी बाहुल्य और घना वन क्षेत्र है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उल्लेखनीय है कि ज़मीन ख़रीद-बिक्री में लगने वाली स्टांप ड्यूटी फीस की 65 प्रतिशत रक़म संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए दी जाती है.

भारतीय संविधान में कहा गया है कि जातिविहीन, सम्प्रदाय विहीन समतामूलक समाज का निर्माण हम भारतीय करेंगे. इस सबके बावजूद जाति का क्रेज बढ़ता जा रहा है.

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र हलचल

सोने से उत्पाद शुल्क हटाए जाने पर मंदिर में देवी की आरती उतारकर ख़ुशी का इज़हार करते नागपुर इतवारी सर्राफ़ा बाज़ार के व्यापारी.

चांदूर बाज़ार में आयोजित गरीबाच्या लग्नला नवरी गोरी काय-काली काय कार्यक्रम में मराठी ग़ज़ल पेश करते कवि एवं गीतकार.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बल्लारपुर की प्राथमिक शाला में आयोजित शिक्षणोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते जि.प. सदस्य एवं अन्य अतिथिगण.

यवतमाल ज़िले के महागांव में अखंड दत्त नाम सप्ताह पर निकाली गई शोभायात्रा में गजराज एवं भक्तजन.

वर्धा में आयोजित श्रीमद्भागवत ज्ञानयज्ञ सप्ताह पर प्रवचन करते तवाडें महाराज और रसास्वदन करते श्रद्धालुजन.

पवनी तहसील के पटवारी अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए.

वाशिम बस स्टैंड परिसर से शराब की दुकान हटाने के लिए मोर्चा निकालते नागरिक.

गोंदिया पब्लिक शाला के प्राचार्य पटले के मार्गदर्शन में पक्षियों के चारे-दाने का अध्ययन करने वाली छात्राएं.

अकोला में संभाजी ब्रिग्रेड द्वारा आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में भजन गाते कीर्तनकार.

निरीक्षक विहीन हैं हज़ारों लिफ्ट

राज्य में मॉल संस्कृति का चलन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से एक मंज़िल से दूसरी मंज़िल में आने-जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल तीव्र गति से हो रहा है. हालांकि जिस गति से मॉल संस्कृति के साथ लिफ्टों का कारोबार बढ़ रहा, उस गति से इसकी देखरेख करने वाला राज्य का तकनीकी विभाग आधुनिक नहीं हो रहा है, जबकि आज के दौर में लिफ्ट का उपयोग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं. मॉल के अलावा अस्पतालों, कॉलेजों, आवासीय इमारतों, व्यावसायिक टॉवरों में भी लिफ्ट का उपयोग किया जाता है. इन लिफ्टों की जांच का ज़िम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, लेकिन इस विभाग के पास राज्य की 86 हज़ार से अधिक लिफ्टों की जांच के लिए मात्र अभियंता स्तर के 16 निरीक्षक ही हैं. इस बात का ख़ुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा दाख़िल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ है.

ग़ौरतलब है कि राज्य में लिफ्टों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है. इसके लिए जो क़ानून राज्य में लागू है वह 71 साल पुराना है. मुंबई लिफ्ट अधिनियम 1939 अंग्रेज़ों के शासन में ही बनाया गया था. उसके 24 साल बाद लिफ्टों के संचालन के संबंध में नियमावली तैयार की गई थी, वह भी 51 साल पुरानी हो चुकी है. इसके कई नियम वर्तमान परिस्थितियों में बेकार हो चुके हैं. अत: मुंबई लिफ्ट अधिनियम 1939 और उसकी नियमावली में आज की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए जाने की अत्यंत ज़रूरत है. इस बात को ध्यान में रखते हुए आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद अफ़ज़ल ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर लिफ्ट क़ानून में संशोधन करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि पिछले नौ सालों में हुई लिफ्ट की विविध दुर्घटनाओं में 50 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है. इसलिए लिफ्ट क़ानून में सुधार किया जाना चाहिए.

नियमों के अनुसार, किसी भी इमारत में लगी लिफ्ट की हर दो साल में जांच की जानी ज़रूरी है, लेकिन इस नियम का भी पालन नहीं किया जाता है, जबकि राज्य की कई इमारतों में लगी लिफ्टों की हालत जर्जर है और वह अक्सर बंद पड़ी रहती हैं. राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि राज्य की अधिकृत 86 हज़ार 154 लिफ्टों का निरीक्षण किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास अभियंता स्तर के मात्र 16 अधिकारी हैं. यहां यह भी ध्यान दिला दें कि लिफ्टों की यह संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष तक की ही है, जबकि राज्य में हर साल हज़ारों की संख्या में बनने वाली इमारतों के साथ ही पांच से सात हज़ार लिफ्टों की बढ़ोत्तरी हो जाती है. यदि सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो राज्य में 17 हज़ार 500 लिफ्ट निरीक्षकों की ज़रूरत है. यह बात उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मानी है. इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लिफ्ट निरीक्षकों को एक साथ उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है. इससे यह ज़ाहिर होता है कि राज्य में लिफ्ट लगाने और उनका संचालन बाबा आदम के ज़माने के क़ानून एवं नियमों के अनुसार हो रहा है. सरकार ने अब तक उसमें किसी तरह का परिवर्तन

करने पर विचार नहीं किया है. आधुनिक तकनीक का विस्तार होने के साथ ही मुंबई लिफ्ट अधिनियम में भी बदलाव सरकार को स्वयं करना चाहिए था, लेकिन यह प्रतीत होता है कि सरकार को किसी क़ानून में तब तक ख़ामियां नज़र नहीं आती हैं, जब तक उसकी ओर न्यायालय द्वारा ध्यान न दिलाया जाए अथवा उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा जनांदोलन न हो या कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए.

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने न्यायालय को बताया कि एमपीएससी की मार्फ़त सरकार 75 लिफ्ट निरीक्षकों की भर्ती करने वाली है. इसका मतलब यह हुआ कि अभी वर्तमान ज़रूरत के अनुसार लिफ्ट निरीक्षकों की भर्ती करने में सरकार को कम से कम दस-पंद्रह साल का समय और लग जाएगा. इससे पता चलता है कि हमारी राज्य सरकार किस गति से कार्य करती है. लगता है कि इसे किसी बड़ी लिफ्ट दुर्घटना का इंतज़ार है. आज की स्थिति में कई पुरानी ख़स्ताहाल लिफ्टों को बदले जाने की सख्त ज़रूरत है. यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि आज लिफ्टों का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है और पुरानी लिफ्टों के ख़राब होने पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. हालांकि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने सरकार को एक समिति की स्थापना करने का निर्देश दिया है. इस समिति में 11 सदस्य होंगे, जिनमें लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों के तीन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. यह समिति राज्य में लिफ्टों की जांच कर उसकी हालत पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी. रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों और सुझावों के आधार पर सरकार लिफ्ट क़ानून एवं नियमों में संशोधन भी करेगी. इससे यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में लिफ्टों के लिए जल्द ही नई नियमावली बनाई जा सकेगी.

राज्य में लिफ्टों की संख्या में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है. इसके लिए जो क़ानून राज्य में लागू है वह 71 साल पुराना है. मुंबई लिफ्ट अधिनियम 1939 अंग्रेज़ों के शासन में ही बनाया गया था. उसके 24 साल बाद लिफ्टों के संचालन के संबंध में नियमावली तैयार की गई थी, वह भी 51 साल पुरानी हो चुकी है. इसके कई नियम वर्तमान परिस्थितियों में बेकार हो चुके हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नागपुर में स्टांप घोटाला

राज्य में हुए तेलगी स्टांप घोटाले की गूंज एक समय पूरे देश में गूंजी थी. इस घोटाले से राज्य की जनता को अब भी छुटकारा नहीं मिला है. हालांकि तेलगी स्टांप घोटाले के बाद राज्य के महसूल विभाग ने कई उपाय योजनाएं बनाई थीं, लेकिन उक्त सभी उपाय योजनाएं नाकाफ़ी साबित हुई हैं. यह इस बात से पता चलता है कि नागपुर ज़िले के ग्रामीण भाग में सात करोड़ रुपये का स्टांप घोटाला होने का ख़ुलासा हुआ है.

हालांकि अब तक पांच ग्राम पंचायत में हुए एक करोड़ 33 लाख रुपये के स्टांप की रक़म का गोलमाल करने के आरोप में नागपुर तहसील के खंड विकास अधिकारी को ही निलंबित किया गया है. इससे राज्य में पुन: स्टांप घोटाले की बात होने लगी है. इस मामले का ख़ुलासा तब हुआ, जब नागपुर तहसील की जामठा, पांजली, खडगांव, पिपल-घोगली और बेसा ग्राम पंचायतों को मुद्राक शुल्क का 65 प्रतिशत हिस्सा गांव के विकास को नहीं मिला. नियमों के अनुसार, यह रक़म ग्राम विकास के लिए दी जानी आवश्यक है. इस पर वहां के जागरूक सरपंच और ग्रामसेवकों ने महसूल विभाग में शिकायत की.

उल्लेखनीय है कि ज़मीन ख़रीद-बिक्री में लगने वाली स्टांप ड्यूटी फीस की 65 प्रतिशत रक़म संबंधित ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दी जाती है. मगर नागपुर के ग्रामीण तहसील के खंड विकास अधिकारी विजय धापके ने मनमानी करते हुए अपनी पसंद की ग्राम पंचायतों को स्टांप ड्यूटी की फीस से मिलने वाली रक़म की अपेक्षा कई गुना रक़म देकर कमीशन में भारी रक़म वसूल की. मगर जब जामठा, पांजली, खडगांव, पिपल-घोगली और बेसा ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अपने हक़ के एक करोड़ 33 लाख रुपये नहीं मिले तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला किया. उन्होंने इस संबंध में ज़िलाधिकारी से शिकायत की. ज़िलाधिकारी द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में बीडीओ को दोषी पाया गया. इस पर ज़िलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से खंड विकास अधिकारी विजय धापके को निलंबित कर दिया है. आश्चर्य की बात यह है कि इस संबंध में मीडिया में ख़बरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन प्रशासन की आंख तब तक नहीं खुली, जब तक पांच ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामसेवकों ने शिकायत नहीं की. महसूल विभाग में यह भी चर्चा है कि नागपुर ग्रामीण तहसील की 50 ग्राम पंचायतों में क़रीब सात करोड़ रुपये को गोलमाल स्टांप ड्यूटी की रक़म में किया गया है. कई ग्राम पंचायतों को 65 प्रतिशत से कम रक़म दी गई है. स्टांप शुल्क से जिन ग्राम पंचायतों को रक़म नहीं मिली है वह करोड़ों की है. जिन ग्राम पंचायतों को स्टांप ड्यूटी की वसूल फीस की 65 प्रतिशत से अधिक निधि दी गई. इनमें बुटीबोरी, नरसाला, बाज़ारगांव, शिवा, सावंगा, आष्टा ग्राम पंचायतें शामिल हैं. यह तो सर्वविदित है कि उक्त ग्राम पंचायतों में ज़मीनों की ख़रीद-बिक्री बड़ी मात्रा में की गई. नागपुर ग्रामीण के उप ज़िला उपनिबंधक क्रमांक 7 और 10 में वर्ष 2010-11 में स्टांप ड्यूटी फीस के रूप में 12 करोड़ 91 लाख 921 रुपये की आमदनी हुई. उक्त रक़म में से 8 करोड़ 14 लाख 15 हज़ार 332 रुपये नागपुर पंचायत समिति को मिले, जिनमें से 25 प्रतिशत रक़म ज़िला परिषद पंचायत विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी गई. उसके बाद बची 7 करोड़ 98 लाख 95 हज़ार 404 रुपये की निधि का बंटवारा संबंधित इन ग्राम पंचायतों को किया जाना था, जिनकी ज़मीन के सौदे से उक्त आमदनी महसूल विभाग को हुई थी. इस रक़म को वितरित करने का दायित्व खंड विकास अधिकारी का था. यहीं गड़बड़ी की गई.

खंड विकास अधिकारी ने स्टांप ड्यूटी फीस से प्राप्त रक़म का वितरण करने में सारे नियम-क़ायदों को किनारे रख दिया. बीडीओ विजय धापके ने अपनी मर्ज़ी से रक़म का बंटवारा किया. जिन ग्राम पंचायतों को कम रक़म मिलनी थी, बीडीओ ने उनको दोगुनी-तिगुनी रक़म का वितरण किया. उसके बदले उक्त रक़म का 15 प्रतिशत कमीशन के तौर पर अपने पास रखता रहा. यह आरोप इन ग्राम पंचायतों के अधिकारियों ने लगाया है, जिनके हिस्से की रक़म बीडीओ ने दूसरों को दे दी. जिन ग्राम पंचायतों को कम रक़म दी गई है, अब उनके पदाधिकारियों ने ज़िलाधिकारी से 1 करोड़ 33 लाख रुपये उन्हें दिए जाने की मांग की है. रक़म न मिलने पर जामठा, पांजरी, पिपला-घोगली आदि ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने आंदोलन करने की बात भी कही है.

ख़ास बात यह है कि अभी जो स्टांप ड्यूटी फीस वितरण के मामले का जो ख़ुलासा हुआ है, वह मात्र पांच ग्राम पचायत का ही है. इस ख़ुलासे के बाद अब यह सवाल उठता है कि इस तरह के मामले और कितने दबे पड़े हैं? यही घोटाला सात करोड़ रुपये का है, जिनमें से 1 करोड़ 33 लाख रुपये की हेराफेरी करने का पता चला है. बाक़ी रक़म का क्या हुआ, इसका पता लगाया जाना बाक़ी है. इस घोटाले के उजागर होने के बाद शासन-प्रशासन को ज़मीन ख़रीद-बिक्री की स्टांप ड्यूटी फीस की रक़म के वितरण के मामलों की जांच हर तहसील एवं पंचायत समिति के स्तर पर की जानी चाहिए, ताकि इस तरह के घोटालों को रोका जा सके.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

किसानों का यूरोप दौरा

प्रवीण महाजन
feedback@chauthiduniya.com

आज यूरोप जाने की बात सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं. सभी की इच्छा कम से कम एक बार यूरोप जाकर घूमने की ज़रूर होती है. आख़िर यूरोप में ऐसा है क्या है? वहां देखने को क्या मिलेगा, वहां किस विषय का अध्ययन किया जा सकेगा, अपने को वहां के लोगों की भाषा समझ में आएगी क्या? वहां का रहन-सहन कैसा होगा, वातावरण रास आएगा क्या? जैसे अनेक सवाल मन में उमड़ने-घुमड़ने लगते हैं. साथ ही मन मे यह उत्सुकता होती है कि हम वहां क्या कर सकेंगे. राज्य के किसानों की इसी उत्सुकता को शांत किया राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय ने. कृषि मंत्रालय ने पिछले दिनों राज्य के प्रगतिशील किसानों का यूरोप कृषि अध्ययन दौरा आयोजित किया था. इस दौरे के लिए राज्य के हर क्षेत्र के किसानों का चयन किया गया था. महाराष्ट्र कृषि संशोधन परिषद के उपाध्यक्ष विजयदादा कोलते, खापोली के नगराध्यक्ष दत्तात्रेय मसूरकर, औरंगाबाद से एड. वसंतराव देशमुख, राजे भोसले, आरए लोथवडे, के. शशिकांत देशमुख, महादेव देसाई, काले लाखनी, के. घनश्याम खेडीकर एवं हुकुमचंद गायधानी, गढ़चिरोली के चंद्रशेखर भंडागे, जाखिणवाडी के नरेंद्र नांगरे, जलगांव की सौ. स्मिता एवं प्रवीण निकम, मेहकर के बादशाह देशमुख, फलटण के सोपाल पोल, कोल्हापुर के हेमंत सोनार, सुनील क़दम एवं राहुल देसाई, रूई के विजय घाडगे, कर्नाल के उमेश एडके, मान्नपावाडी से मनोज कुमार जगतप, हवेली के सुनील शितोले, सणसर के दीपक निंबालकर, पुणे से प्रशांत कोंडे, चिखली से संदीप वाघ, लातूर के राजेंद्र गाडे, बारामती से सौ. नीला गाडे, नारायणगांव से राजश्री बोरकर, नीता बोरकर, अंजली खैरे, लोथवडे के दादासाहब चोपड़े, सुपने के दीपक पाटिल, मलकापुर-कराड के मनोहर शिंदे, विजयनगर से सुनील पाटिल, झरेकाठी के एड. पोपटराव वाणी, चालीसगांव के प्रदीप देशमुख, निडणी के बालासाहब आरलिंगे, बुलढाना से मोहन मानकर, राजगुरुनगर से प्रमोद थेऊरकर, लोधवडे के दिलीप चव्हाण, अहमदनगर से मच्छिंद्र नवले, नांदेड़ के यशवंतकर, नागपुर से प्रभाकर वधने एवं प्रवीण महाजन इस अध्ययन दौरे में शामिल थे. इस दौरे में जो देखने को मिला और उसका जो अनुभव हुआ, वह यहां शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है.

फूल मार्केट फ्लोरा हॉलैंड

दौरे के प्रथम चरण में सबसे पहले हालैंड की राजधानी एमस्टर्डम में पहुंचे. यहीं से हमारा अभ्यास दौरे का सही रूप में शुभारंभ हुआ. यहां सबसे अधिक आकर्षित किया विश्व प्रसिद्ध फूलों की मार्केट फ्लोरा हॉलैंड ने. यह फूल का विश्व में सबसे बड़ा बाज़ार है. यहीं से विश्व के सभी देशों में फूलों का निर्यात किया जाता है. दरअसल, फ्लोरा हॉलैंड एक सहकारी संस्था है और उसमें क़रीब 500 सदस्य हैं. उसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों में समन्वय स्थापित कर विश्व बाज़ार की मांग के अनुसार फूलों का उत्पादन किया जाता है. इसके बाद बारी आती है उत्पादित फूलों की नीलामी की, जिसमें फ्लोरा हालैंड संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. इस अत्याधुनिक व्यावसायिक केंद्र में 6 नीलामी केंद्र हैं. यहां किसान जब अपने उत्पादित फूलों को बाज़ार में लाते हैं तो सबसे पहले उनका तकनीकी परीक्षण कर क्वालिटी कंट्रोल नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है. तत्पश्चात 50-100-200 की संख्या में बास्केट में रखकर फूलों की नीलामी की जाती है. नीलामी के लिए यहां 13 हॉल हैं. एक हॉल में 75 से लेकर 100 की संख्या में व्यापारी नीलामी में भाग लेते हैं. हॉल में व्यापारियों की बैठने की जगह से 10 फुट ऊंचाई पर ऑडिटोरियम जैसी व्यवस्था है, जहां पर फूलों से भरी ट्रॉली व्यापारियों को स्पष्ट रूप से नज़र आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक परदे पर उत्पादक का नाम, फूल के प्रकार, क्वालिटी कंट्रोल का रिमार्क, फूलों की कुल संख्या आदि सभी सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं. इसी जानकारी के आधार पर व्यापारी फूलों की ख़रीददारी करते हैं. फ्लोरा हॉलैंड से कीनिया, इथोपिया, इज़रायल, दक्षिण अमेरिका सहित अन्य देश भी उत्तम श्रेणी के फूलों के उत्पादन के लिए फ्लोरा हॉलैंड से झाड़ों की ख़रीदी करते हैं. यहां उत्पादों का अत्याधुनिक तरीके से पैकिंग की जाती है. भारत के किसान भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फूलों की खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें कम ज़मीन रहने पर भी भरपूर आमदनी हो सकती है.

डेयरी फार्म

दौरे के दौरान यूरोप में कृषि व्यवसाय, पारिवारिक खेती, रोप की पैदावार, कृषि से जुड़े पूरक व्यवसाय, अंगूर बागों, वायनरी प्लांट, कुक्कुट पालन व्यवसाय, डेयरी फार्म, चीज फैक्ट्री, ट्यूलिप गार्डन (फूल खेत), वुडन शू फैक्ट्री, लेक फार्म (बोडेंसी), ब्लैक फॉरेस्ट, जलापूर्ति योजनाओं के स्थलों पर जाकर अवलोकन किया. वहां के डेयरी फार्म की व्यवस्था एवं मवेशियों का रखरखाव क़ाबिले-तारीफ़ था. फ्रायबर्ग के नज़दीक ब्रेटगांव में स्थित डेयरी फार्म को देखकर दौरे पर गए सभी लोग अचंभित रह गए. ब्रेटगांव 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर था. यहां क़रीब 100 गाय-बछड़े थे. यहां क़रीब 40 गाएं अति स्वस्थ्य और दुधारू थीं. प्रत्येक गाय 35 से 40 लीटर दूध देनेवाली थी. गायों के रहने की व्यवस्था अपने यहां की अपेक्षा बेहतर थी. वहां के वातावरण के अनुसार गरम और ठंडा रखा जाता है. वहां गायों को क्रमांक देकर प्रत्येक के संबंध में जानकारी रखी जाती है. उन्हें निर्धारित समय पर चारागाहों में छोड़ा जाता है और उनकी रखवाली के लिए दो प्रशिक्षित कुत्तों का रखा जाता है. यूरोप में मनुष्य बल का कम ही उपयोग किया जाता है. यहां के फार्मों में गिने-चुने लोग ही काम करते दिखाई दिए. गायों का दूध निकालने के लिए व्यवस्थित अत्याधुनिक दूध पार्लर हैं. दूध को एकत्र कर रखने के लिए फार्म के अंदर ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था थी. वहां लगभग सभी कार्य मशीनों के माध्यम से करने का चलन है. डेयरी फार्म से ही जोड़कर बायोगैस का प्लांट था, जिसमें गायों के मल-मूत्र, सड़े चारे आदि का उपयोग किया जाता था. यहां की सरकार और लोग पर्यावरण को विशेष महत्व देते हैं. इससे उन्हें दोहरा फ़ायदा होता है. एक तो आस-पास के लोग घरों का कचरा लाकर उसमें डाल देते हैं, जिससे सफ़ाई रहती है, दूसरा फ़ायदा यह होता है कि बायोगैस से उत्पादित बिजली का उपयोग भी करने को मिलता है. इसी बिजली का उपयोग डेयरी फार्म में किया जाता है. यहां डेयरी फार्म से किसान 100 दुधारू गायों को पाल कर साल में 70 से 80 लाख रुपये का मुनाफ़ा कमाते हैं. इसके अलावा गायों के मल-मूत्र से जो कमाई होती है वह अलग. विशेष बात यह है कि यहां कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है.

प्रसिद्ध प्लाज मार्केट

जर्मनी में फलों और सब्ज़ियों की ख़रीद-बिक्री का व्यवहार एक ही जगह करने के मक़सद से पुरानी तीन मार्केट को बंद कर दिया गया और वर्ष 1985 में प्लाज मार्केट की स्थापना की गई. अब यहीं फलों और सब्ज़ियों का सारा कारोबार होता है. यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को माल लाने के लिए 50 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़े. इसलिए प्लाज मार्केट अपनी गाड़ियां भेजकर किसानों के उत्पाद को बाज़ार में मंगवा लेता है. प्लाज मार्केट का संचालन कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर करते हैं.

एक व्यवस्थापक पर बाज़ार की व्यावसायिक नीति निर्धारण की ज़िम्मेदारी रहती है. अध्यक्ष एवं अन्य लोग बाज़ार की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं. इसके अलावा बाज़ार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षक मंडल की स्थापना भी की गई है. उसके सदस्यों की साल में एक बार बैठक होती है, जहां व्यवसायिक नीतियों और परिस्थितियों पर विचार-विमर्श किया जाता है. विशेष बात यह है कि जर्मनी के इस बाज़ार में कुल 115 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 75 कर्मचारी बाज़ार में और बाक़ी कर्मचारी किसानों की सहूलियत के लिए पांच स्थानों में कार्यरत हैं. इस बाज़ार में किसानों के उत्पाद की बिक्री की 100 प्रतिशत गारंटी दी जाती है. यहां बाज़ार के नियमों के अनुसार, किसानों को अपना उत्पाद अन्य जगह बेचने की इजाज़त नहीं होती. ■

ये क्या हो रहा है...

जाति ही पूछो साधु की

पिछले दिनों मुंबई उच्च न्यायालय ने चुनाव के दरम्यान उम्मीदवारों को जांच पड़ताल समिति द्वारा जारी किए गए 35 लाख जाति प्रमाण पत्र और 27 हज़ार जाति वैधता प्रमाण पत्र ख़ारिज कर दिए तो राज्य में कोहराम मच गया. हालांकि न्यायालय के इस निर्णय से कोहराम मचना स्वाभाविक था. आख़िर आजकल सब कुछ जाति को देखकर ही तो किया जाता है. बिना जाति के आज आदमी की कहीं पूछ-परख ही नहीं है. पढ़ाई करनी हो तो जाति पूछी जाती है. शादी-ब्याह में जाति, नौकरी करनी हो तो जाति, राजनीति करनी हो तो जाति, चुनाव लड़ना हो तो जाति, यानी जाति का झमेला इतना व्यापक है कि जाति के बिना आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है. सामान्य आदमी को छोड़िये, आजकल तो साधु-संतों को भी जाति के खांचे तक सीमित कर दिया गया है. पहले कहा जाता था- जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान. अब कहा जाता है- जाति ही पूछो साधु की, रखा क्या है ज्ञान में. हमारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि जाति का कीटाणु लोकतंत्र को खोखला कर रहा है.

भारतीय संविधान में कहा गया है कि जातिविहीन, संप्रदाय विहीन समतामूलक समाज का निर्माण हम भारतीय करेंगे. इस सबके बावजूद जाति का क्रेज बढ़ता जा रहा है. आज जब बच्चे को कक्षा पहली में प्रवेश के लिए ले जाया जाता है तो उसकी

जाति का प्रमाण पत्र या उसके पिता की जाति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है. शिक्षा का जाति से क्या संबंध है, यह बात समझ में नहीं आती है, लेकिन सरकार ने नियम बना दिया है कि स्कूल में प्रवेश चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र देना ही होगा. जिन संतों ने जात-पात की परंपरा को समाज में बढ़ते वैमनस्य का सबसे बड़ा कारण बताया, उन संतों को भी आज के तथाकथित शिक्षित समाज ने जाति के फ्रेम में मढ़ कर रख दिया है. संत तुकाराम, संत जगनाड़े महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, संत गुरुनानक, संत रविदास व अन्य संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया था. आज भी इन संतों को समाज में माना जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण एवं फूल चढ़ाने तक ही वे श्रद्धा के पात्र बनकर रह गए हैं. उनके उपदेशों-सीखों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. विडंबना यह है कि जिन लोगों पर भारतीय लोकतंत्र की ख़ामियों को दूर करने की ज़िम्मेदारी है, वही जाति की विष बेल को सींच रहे हैं. हमारे मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों का चयन ही जातीय आरक्षण के आधार पर होता है. अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता की बजाय जाति के आधार पर होती हो तो भला कैसे जाति की कुप्रथा का अंत हो सकता है. इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय के फ़ैसले से तो यह कोहराम होना ही था.

आज आदमी की पहचान उसके काम की बजाय जाति के आधार पर होने लगी है. यह भारतीय तंत्र को कमज़ोर करता है. मगर हमारी कार्यपालिका इस जाति के कीटाणु से मुक्ति के उपाय करने की जगह इसे और बढ़ने का मौक़ा दे रही है. वर्तमान में चुनावों में टिकट का वितरण जाति के आधार पर किया जाता है. हमारे सभी नेता भाषणों में भले ही जातिप्रथा समाप्त करने की बात करते हों, लेकिन हक़ीक़त यही है कि आज बच्चे को बचपन से ही जाति का पाठ-पहाड़ा पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है. अब यह तो हमारे बुद्धिजीवी ही बता सकते हैं कि यह क्या हो रहा है? जातिप्रथा को ख़त्म करने की बजाय हमारी लोकतांत्रिक सरकारें जाति को बढ़ावा क्यों दे रही हैं?

आज आदमी की पहचान उसके काम की बजाय जाति के आधार पर होने लगी है. यह भारतीय तंत्र को कमज़ोर करता है. मगर हमारी कार्यपालिका इस जाति के कीटाणु से मुक्ति के उपाय करने की जगह इसे और बढ़ने का मौक़ा दे रही है. वर्तमान में चुनावों में टिकट का वितरण जाति के आधार पर किया जाता है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबर

लोहार ने इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन बनाई

काम करने वाले के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह बात परतवाड़ा निवासी मदन इंजीनियर्स के संचालक मदन माहुले और पुत्र ज्ञानेश माहुले की जोड़ी ने कर दिखाया है. इन दोनों ने अभियांत्रिकी की कोई पढ़ाई नहीं की, मगर अपने अनुभव एवं कल्पना शक्ति के दम पर राज्य की पहली इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन का निर्माण कर दिखाया है. फूलरानी नाम की यह टॉय ट्रेन गाड़ी पूना के पेशवा उद्यान (सारस बाग़) में दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी है. इसका निर्माण पूना महानगर पालिका के ऑर्डर पर किया गया है. इस तीन डिब्बे वाली टॉय ट्रेन की कुल लागत 25 लाख रुपये है और इसमें 18 से 20 लोग एक साथ बैठकर सफ़र का आनंद उठा सकते हैं. इसके लिए सारस बाग़ में एक किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है. यह पूर्णत: आवाज़-धुआं-प्रदूषण रहित पर्यावरण के अनुकूल है. यह 72 बोल्ट की डीसी बैटरी, 16 हॉर्स पावर के इंजन और रीडिक्शन गेयर बॉक्स की मदद से ट्रैक पर दौड़ेगी. विशेष बात यह है कि इसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया है. इसकी मदद से गाड़ी किस गति से ट्रैक पर दौड़ रही है, कौन सी लोकेशन पर है और इसमें कहां, कैसी ख़राबी आ गई है, यह सभी सूचना परतवाड़ा में बैठे इसके निर्माता को मिलती रहेगी. लिहाज़ा गाड़ी के रखरखाव के लिए निर्माता को बार-बार पूना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. ग़ौरतलब है कि 8 अप्रैल 1956 को देश की प्रथम टॉय ट्रेन सारस बाग़ में दौड़ी थी जिसका नाम रखा गया था- फूलरानी. पिछले चार सालों से फूलरानी तकनीकी ख़राबी आने के बाद से बंद पड़ी है. इसकी जगह अब परतवाड़ा में माहुले पिता-पुत्र की जोड़ी द्वारा निर्मित फूलरानी ने लिया है. इस सफलता पर माहुले पिता-पुत्र की जोड़ी को नगराध्यक्ष अरुण वानखडे.और पार्षद राजू लोहिया ने बधाई दी और इनका अभिनंदन किया.

केंद्र का राष्ट्रपति को तोहफ़ा

अमरावती में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी गई है. मानव संसाधन मंत्रालय के इस निर्णय को राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल को विदाई में तोहफ़ा दिए जाने की बात कही जा रही है. सूचना है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने स्वयं महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि वह अमरावती विश्वविद्यालय का स्तर सुधारने की इच्छुक है या वहां नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलना चाहती है. ग़ौरतलब यह है कि इसके पूर्व 2008 में जब राष्ट्रपति ने अमरावती में केवल महिलाओं के लिए आईटीआई खोलने की मांग की थी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनकी मांग को सिरे से ठुकरा दिया था. इसके बाद वर्ष 2010 में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अमरावती के संत गाडगे महाराज विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. तब भी मानव संसाधन मंत्रालय ने यह कहते हुए इनकी मांग को ख़ारिज कर दिया था कि विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाने का अब तक का अनुभव सुखद नहीं रहा है. अब जब प्रतिभाताई का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तब अचानक मानव संसाधन मंत्रालय के रुख़ में परिवर्तन आ गया. उसने अब स्वयं अमरावती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की पहल की है. इसीलिए यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा यह प्रतिभाताई को तोहफ़ा दिया जा रहा है.

दायित्व के प्रति ऐसी निष्ठा

अपने काम और दायित्व के प्रति इतना समर्पण कि 27 साल में न कभी देरी हुई और न एक दिन की छुट्टी ली. ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है, यह मिसाल पेश की पुणे ज़िले के मुंडवा स्थित कल्याणी कॉर्पोरेटर स्पेशल स्टील लिमिटेड कंपनी में इलेक्ट्रिशियन पद पर कार्यरत सदाशिव अनंता लाड ने. सदाशिव कर्जत तहसील के पाटेगांव का मूल निवासी है. वह कक्षा 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नौकरी की तलाश में पुणे आ गए. 1 अक्टूबर, 1974 में वह कल्याणी कॉर्पोरेटर स्पेशल स्टील लि. कंपनी में 250 रुपये प्रतिमाह की पगार पर नियुक्त हुआ. उनका घर कंपनी से 11 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वह बारहों माह साइकिल से आना-जाना करते हैं. इसके बावजूद वह कभी अपनी ड्यूटी पर देर से नहीं पहुंचे और न ही पिछले 27 वर्ष में कभी एक दिन की भी छुट्टी ली. सदाशिव का कहना है कि जब पिता का निधन हुआ था, तब सप्ताह भर का अवकाश लिया था. इसके बाद से कभी छुट्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सच, इनके इस अद्‌भुत रिकॉर्ड को सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता है, पर सच तो सच होता है. आज वह कंपनी के एक आदर्श कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं और अपने सहयोगियों के बीच अपने काम के प्रति समर्पण के लिए श्रद्धा के पात्र भी हैं.

मंत्री वाटर पार्क में व्यस्त

राज्य सूखे की समस्या से जूझ रहा है. 15 ज़िले सूखे की चपेट में हैं. मगर इससे मंत्रियों के कार्यक्रमों में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है. राज्य के पर्यटन मंत्री छगन भुजबल वाटर पर्क के उद्‌घाटन में व्यस्त हैं. इतना ही नहीं, पिछले दिनों उन्होंने लोनावला के कार्ला में एक वाटर पार्क का उद्‌घाटन किया और कहा कि इसको सूखे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल (एमटीडीसी) की ओर से पर्यटकों के लिए कार्ला रिसोर्ट में 3 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से आलीशान वाटर पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्‌घाटन हमारे मंत्री ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोनावला-खंडाला हमेशा से पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा है. हालांकि यहां कई निजी वाटर पार्क हैं, पर कार्ला रिसोर्ट का वाटर पार्क पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी कम ख़र्च पर सुलभ हो सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में कई पांच सितारा वाटर पार्क हैं, पर महंगे होने के कारण आमजन वहां जाने से कतराते हैं. अब यह नया वाटर पार्क उनके लिए उपलब्ध रहेगा. सही है भाई, मंत्री जो बोले वह सही होता है. इसलिए वाटर पार्क का भला सूखे से क्या संबंध हो सकता है? जहां सूखे की स्थिति है, उसकी चिंता वहां के लोग करें, मंत्री क्यों करे?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कम से कम मुख्यमंत्री को राज्यपाल की नेक सलाह का ख्याल रखना चाहिए था. यहां उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि जिस मंच को वह संबोधित कर रहे हैं, वह राजनीतिक मंच नहीं है.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

मुख्यमंत्री की मजबूरी और साहस

राजेश नामदेव
feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आख़िरकार अपना दर्द और अपनी मजबूरी व्यक्त कर ही दी. वह भी ऐसे मंच से जहां सत्तापक्ष और विपक्ष के अलावा राज्यपाल के शंकरनारायणन भी मौजूद थे. अवसर था राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण की जन्म शताब्दी समारोह के तहत आयोजित संगोष्ठी का. यहां मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर गठबंधन सरकार की वजह से होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए अपरोक्ष रूप से अपने सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दल के बहुमत वाली सरकार में फ़ैसले लेने में आसानी होती है. यशवंतराव चव्हाण के समय और अब की राजनीति में बहुत अंतर आ चुका है. तब एक पार्टी की सरकार होती थी. यशवंतराव चव्हाण जब मुख्यमंत्री थे, तो राज्य में एक दल की बहुमत वाली सरकार थी. अब गठबंधन की राजनीति का ज़माना है. इसमें निर्णय लेने में मुश्किल होती है. इसका यही मतलब है कि मुख्यमंत्री शासन–प्रशासन से संबंधित निर्णयों में होने वाली देरी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राकांपा को ज़िम्मेदार बता रहे हैं. इससे राज्य में कांग्रेस–राकांपा के मध्य नए सिरे से शीतयुद्ध शुरू हो गया है और राकांपा की ओर से शरद पवार और अजीत पवार ने भी मोर्चा खोल दिया है. हालांकि इसी मंच से उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की बात कहकर राजनीतिक साहस का परिचय भी दिया. यह घोषणा भले ही राजनीतिक दबाव में की गई हो, लेकिन इसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी. इसके अलावा उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पर भी निशाना साधा, क्योंकि राज्य में जब से आघाड़ी (गठबंधन) सरकार है, तब से राज्य के सिंचाई विभाग की कमान राकांपा नेताओं के हाथ में है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चव्हाण पर लंबे समय से मामलों को लटका कर रखने का आरोप लगता रहा है. यह आरोप न केवल विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, बल्कि सहयोगी दल राकांपा और कांग्रेस पार्टी के लोग भी यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं. इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच पहले भी कई बार कोल्डवार हो चुका है. इस दफ़ा मुख्यमंत्री ने इसे यशवंतराव जन्म शताब्दी समारोह के मंच से पुन: शुरू कर दिया है. इस संगोष्ठी का विषय था– महाराष्ट्र कल, आज और कल. इससे यह तो आभास हो ही जाता है कि राज्य सरकार के मुखिया कहां उलझे हुए हैं. वहीं राज्य में सूखा, कुपोषण जैसी अनेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. जनहित में संचालित होने वाली योजनाएं भी भ्रष्टाचार का शिकार बनी हुई हैं और हमारे सत्ताधीश ओछी राजनीति करने में मसरूफ़ हैं. आख़िर मुख्यमंत्री को इस मंच का अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने की क्या ज़रूरत थी. क्या राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए यही मंच मिला था? उस मंच पर तो आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता यशवंतराव चव्हाण को आदरांजलि अर्पित करने के साथ राज्य को नई दिशा दृष्टि देने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई थी. हालांकि यहां राज्य को बेहतर बनाने के लिए कोई विचार रखने की बजाय आरोप–प्रत्यारोप की राजनीति के दर्शन ही अधिक हुए और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बह गए. यह रवैया गंभीर राजनीति का परिचायक नहीं है. हालांकि अब राकांपा मुखिया शरद पवार ने कहा है कि यह सही है कि गठबंधन सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं. यह खरी बात है, लेकिन गठबंधन सरकार चलाना भी एक कला है. उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन सरकार है, इसलिए राज्य से संबंधित सारे निर्णय राज्य में ही लिए जाते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर अपरोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि एक पार्टी की सरकार होने पर राज्य के सारे निर्णय दिल्ली में लिए जाते हैं, यानी राज्य में सत्तारूढ़ दलों के बीच आपसी कलह शुरू हो गया है.

अफ़सोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के शंकरनारायणन की सलाह–मशविरे का ख्याल भी नहीं रखा. राज्यपाल ने राज्य में गंभीर जलसंकट का ज़िक्र करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते हम नहीं चेते तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि यदि युद्धस्तर पर समस्या से निपटने के प्रयास नहीं किए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है. राज्यपाल ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने में विफल साबित हुई. इसके साथ ही भविष्य में जलसंकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है. सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क़रीब 75 हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी. उन्होंने सरकार को सलाह भी दी कि पहले उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाए, जिनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है. यदि इन परियोजनाओं का काम पूरा हो जाता है तो जनता को काफ़ी राहत मिल सकती है. उन्होंने राज्य के 15 ज़िलों में सूखे और कुछ ज़िलों में कुपोषण की समस्या होने का भी ज़िक्र किया. इसके अलावा राज्य के उच्च शिक्षा में छात्रों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के मार्फ़त प्रदान कर कुशलता निर्माण करने पर ज़ोर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्य की हालत सुधारने के लिए क्या उपाय योजना कर सकते हैं, इस पर विचार व्यक्त करने की बजाय राजनीतिक रंजिश का ज़िक्र कर बैठे, जिससे उस मंच की गरिमा कम हुई.

कम से कम मुख्यमंत्री को राज्यपाल की नेक सलाह का ख्याल रखना चाहिए था. यहां उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि जिस मंच को वह संबोधित कर रहे हैं, वह राजनीतिक मंच नहीं है. ऐसा देखकर यह प्रतीत होता है कि विपक्षी नेताओं के आरोपों और राज्यपाल के यह कहने पर कि राज्य सरकार सिंचाई परियोजनाओ को निर्धारित समय में पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है, वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके. लिहाज़ा वह सरकारी निर्णयों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राकांपा को ज़िम्मेदार ठहराने के चक्कर में अपना दर्द और मजबूरी प्रकट कर बैठे, लेकिन बार–बार इस मजबूरी को प्रकट करने से तो उनकी ही कमज़ोरी ज़ाहिर होती है. यह बात कोई भी साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी बता सकता है. यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें तीन माह का समय दिया है, जिसमें उन्हें काम करके दिखाना है. इसलिए उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां बनाते समय कठोर निर्णय लेने होंगे, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें अब तक कठोर निर्णय लेने से किसने रोका था. अब उन्हें याद आ रही है, जब पार्टी आलाकमान द्वारा उन्हें अपने कामकाज की शैली में परिवर्तन करने और काम करके दिखाने का अल्टीमेटम मिला है. अब वह कह रहे हैं कि भविष्य में योजना की रूपरेखा तय करते समय बिजली, पानी, शिक्षा और रोज़गार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यदि वे यही काम पहले करते तो उन्हें सहयोगी दल और विपक्षी पार्टियों की आलोचना नहीं झेलनी पड़ती.

बावजूद इसके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने राजनीतिक साहस दिखाते हुए सिंचाई परियोजनाओं पर अब तक किए गए ख़र्च पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है. भले ही यह साहसिक घोषणा किसी भी वजह से किया गई हो, लेकिन ध्यान रहे कि श्वेत पत्र जारी करने की मांग लंबे समय से विपक्षी दल भी करते रहे हैं. मुख्यमंत्री का यह क़दम शायद अब तक के राजनीतिक करियर का सबसे यादगार क़दम कहा जा सकता है. वजह यह है कि राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार होने और उनके निर्माण में जानबूझकर विलंब किए जाने का आरोप लगता रहा है. साथ ही इन परियोजनाओं के निर्माण न होने से किसानों की उम्मीदों पर कुठाराघात होता रहा है. जिन किसानों की खेती की ज़मीन परियोजनाओं में गई, घर–बार तबाह हुए और हज़ारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए, उन्हें आज तक कोई मुआवज़ा नहीं मिला है. वे ख़ुद को सरकार द्वारा ठगा गया महसूस करते हैं. इसलिए यदि मुख्यमंत्री ने अब सिंचाई परियोजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा कर दी है तो, उन्हें अपनी इस घोषणा पर अमल करने के लिए गंभीर प्रयास करनी चाहिए. इस बाबत उन्हें विपक्षी दलों का सहयोग भी आसानी से हासिल होगा, क्योंकि वी पहले से ही श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते रहे हैं. इसलिए अब मुख्यमंत्री को यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ़ बोल वचन तक सीमित नहीं हैं, बहल्क कठोर क़दम भी उठा सकते हैं. हालांकि सिंचाई परियोजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करना सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं होगा. इसकी वजह यह है कि सिंचाई मंत्रालय पर लंबे समय से राकांपा के मंत्री विराजमान हैं और सिंचाई मंत्री कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे कि उनके विभाग पर श्वेत पत्र जारी किया जाए. नाराज़ राकांपा नेता एवं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि मुख्यमंत्री को जल संसाधन विभाग के कामकाज की जानकारी नहीं है. इसीलिए उन्होंने श्वेतपत्र जारी करने की बात कही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सहित पूरा मीडिया झूठे आरोप लगा रहा है. राकांपा के अन्य नेताओं का भी कहना है कि यदि मुख्यमंत्री को यह घोषणा करनी थी तो कम से कम सिंचाई मंत्री से तो सलाह–मशविरा करना चाहिए था. बहरहाल, सरकार श्वेत पत्र सरकार ला पाती है कि नहीं यह अलग बात है, लेकिन इसे लेकर सरकार के घटक दलों में बहस शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री की घोषणा से कांग्रेस–राकांपा के बीच तनाव बढ़ गया है. हालांकि श्वेत पत्र जारी होने से राज्य के किसानों को यह तो मालूम पड़ेगा कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए आने वाली करोड़ों की निधि जाती कहां है? उसका बंदरबांट कहां और कौन लोग कर रहा है? ■

मुख्यमंत्री चव्हाण पर लंबे समय से मामलों को लटका कर रखने का आरोप लगता रहा है. यह आरोप न केवल विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, बल्कि सहयोगी पार्टी राकांपा और कांग्रेस के नेता भी लगा रहे हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच पहले भी कई बार कोल्डवार हो चुका है. इस बार मुख्यमंत्री ने इसे यशवंतराव जन्म शताब्दी समारोह के मंच से पुन: शुरू कर दिया. इस संगोष्ठी का विषय था– महाराष्ट्र कल, आज और कल.इससे यह तो आभास हो ही जाता है कि राज्य सरकार के मुखिया कहां उलझे हुए हैं.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 21 मई–27 मई 2012

www.chauthiduniya.com

The Most Cost Effective Builder In India

www.vastuvihar.org

वास्तु विहार®

एक विश्वस्तरीय टाउनशिप

AN ISO : 9001-2008 CERTIFIED COMPANY

हम बनाते हैं आपके सपनो का घर...!

7 लाख में घर

स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग सेन्टर, 24 घन्टे बिजली एवं जलापूर्ति

Multiple Option to choose your dresme shelter in any city...

पटना	– 07488538120/21/23, 0612–6450735	रांची	– 07488535220
मुज़फ्फरपुर	– 07488535211, 0621–6499030	आरा	– 07488535201
गया	– 07488535291/93, 0631–2221624	छपरा	– 07488535202
हाजीपुर	– 07488538151, 07488538139	दरभंगा	– 07488538162
हजारीबाग	– 07488538192/93	पूर्णिया	– 07488535250
भागलपुर	– 07488535249/50	सिवान	– 07488538145
धनबाद	– 07488535261/62	बिहारशरीफ	– 07488538178
बक्सर	– 07488535204	कोलकाता, सिल्लीगुडी	– 09331339202
बक्सर	– 07488535204		

For details Enquiry Type SMS VASTUVIHAR and send it to 56677

सुशासन में नरेंद्र मोदी का पेंच

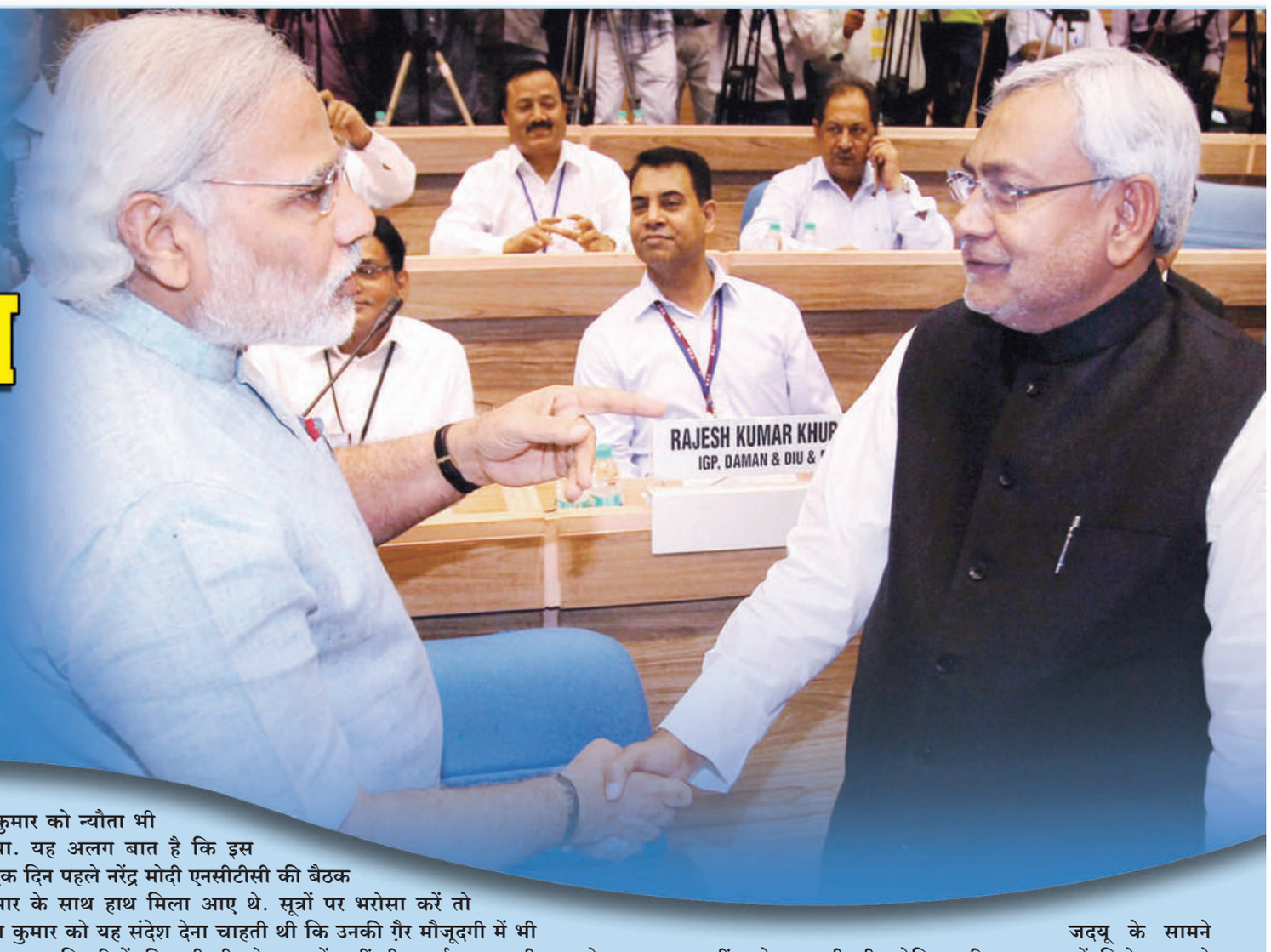

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में जदयू एवं भाजपा के संबंधों में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का पेंच फंस गया है. दरअसल यह पेंच समय-समय पर फंसाया जाता है, ताकि राजनीतिक गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सके और इसी आधार पर आगे फ़ैसला लिया जा सके. इस बार शुरुआत सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नरेंद्र मोदी के साथ सूरत में साझा मंच में की. मौक़ा था बिहार शताब्दी समारोह का. बिहारियों की भारी भीड़ से गदगद अश्विनी चौबे ने हुंकार भरी कि नरेंद्र मोदी जी आप देश का नेतृत्व कीजिए, पूरा बिहार आप के साथ है. चौबे के इतना कहते ही बिहार में सियासी पारा अचानक चढ़ गया. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ़ कहा कि अगर इस तरह की बात हुई तो जदयू अपना रास्ता अलग करने पर गंभीरता से विचार कर सकता है. सुशील मोदी ने संकट की गंभीरता को भांपते हुए कहा कि सूरत में अश्विनी चौबे ने जो कुछ कहा, वह उनकी निजी राय थी, न कि पार्टी की. इसलिए इस मामले को तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भाजपा जदयू संबंधों में दरार डालने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अश्विनी चौबे अपने बयान से हिलते नज़र नहीं आ रहे हैं. चौबे कहते हैं कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बननी तय है और नरेंद्र मोदी सबके चहेते हैं. उनके ही नेतृत्व में कमल खिलना तय है.

जानकार बताते हैं कि दरअसल, भाजपा दो मुद्दों पर वाहवाही लूटने में अपनी सहयोगी जदयू से काफ़ी पिछड़ती जा रही है. पहला विशेष राज्य के दर्जे की मांग और दूसरा बिहार शताब्दी वर्ष समारोह. शताब्दी वर्ष मनाने का सारा कार्यक्रम नीतीश कुमार के ईद-गिर्द ही केंद्रित रहा. बिहार के बाहर भी चाहे वह दिल्ली हो या मुंबई, यह समारोह पूरी तरह नीतीश कुमार का शो बनकर रह गया. भाजपा इसमें दूर-दूर तक नहीं थी. हां, भाजपा को चिढ़ाने के लिए इसमें संजय झा को ज़रूर शामिल किया गया. भाजपा के चिंतकों को लगने लगा कि शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर जो राजनीतिक लाभ पार्टी को मिलना चाहिए था, वह जदयू के खाते में चला गया. यही वजह रही कि सूरत की सभा में उमड़ी भीड़ को देखते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि यहां तो दिल्ली एवं मुंबई की तुलना में तिगुने लोग आए हैं. और तो और इस कार्यक्रम में आने के लिए नीतीश कुमार को न्यौता भी नहीं दिया गया. यह अलग बात है कि इस आयोजन के एक दिन पहले नरेंद्र मोदी एनसीटीसी की बैठक में नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला आए थे. सूत्रों पर भरोसा करें तो भाजपा नीतीश कुमार को यह संदेश देना चाहती थी कि उनकी ग़ैर मौजूदगी में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहारियों की भारी भीड़ देश भर में कहीं भी जुटाई जा सकती हैं. संघ से जुड़े नेता बताते हैं कि सूरत की सभा में यह साफ़ हो गया कि बिहारियों के दिल में नरेंद्र मोदी के प्रति बेहद प्यार है. बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के और कार्यक्रम हो सकते हैं. ऐसे आयोजन कर भाजपा बिहारियों के बीच अपनी ताक़त की थाह लेना चाहती है. दूसरा मुद्दा विशेष राज्य के दर्जे का है. नीतीश कुमार एवं जदयू शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर भाग रहे हैं. ऐसा तब हो रहा है कि जब विधानसभा में सभी दलों ने विशेष राज्य के दर्जे के प्रति अपना समर्थन दिया है, लेकिन इस भावना को नज़र अंदाज़ करते हुए जदयू ने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया और लगभग एक करोड़ हस्ताक्षरों को दिल्ली ले जाकर सौंपा गया. गाहे-बगाहे जब भी केंद्र की तरफ़ से इस मुद्दे पर नकारात्मक टिप्पणी हुई, तो जदयू और नीतीश कुमार ने ही बढ़-चढ़कर इसका प्रतिवाद किया, लेकिन बेगूसराय में कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने यह तय किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा 1977 की तरह आंदोलन करेगी. देखा जाए तो यह संकल्प लेने में भाजपा ने काफ़ी देर कर दी. इसका अहसास भाजपा के कार्यकर्ता लगातार अपने नेताओं को दिला रहे थे, पर गठबंधन के बोझ तले दबे नेताओं ने कोई निर्णायक क़दम नहीं उठाया. जब मामला ज़्यादा गंभीर हो गया तो भाजपा के लिए विकल्प सीमित हो गए. यह सही है कि इससे पहले भाजपा अति पिछड़ा सम्मेलन, दलित बस्तियों में भोज और मल्लाह सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के सहारे जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने की क़वायद कर रही थी, पर किसी बड़े मुद्दे पर जदयू के सामने आने का साहस नहीं बटोर पा रही थी. लेकिन परिषद चुनाव में मिले जख्म ने भाजपा को चौकन्ना कर दिया और इसी का परिणाम है कि जिन दो मुद्दों पर जदयू अपना विशेषाधिकार मान रही थी, उन पर भाजपा ने मज़बूत राजनीतिक पहल कर दी. सूरत की सभा से भाजपाई इतने उत्साहित हैं कि उनको लगता है कि यह काम काफ़ी पहले शुरू कर देना चाहिए था. बहरहाल, जदयू भी भाजपा की इन चालों को बारीकी से समझने में लगा है. अश्विनी चौबे के बयान पर जिस तरह जदयू की प्रतिक्रिया आई, वह यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि दोनों दलों के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए हैं. इसके पीछे दोनों दलों की अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं. जदयू को संबंध तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी का बहाना चाहिए और वह इसके इंतज़ार में है. उधर, भाजपा की तैयारी भी डैमेज कंट्रोल की है. ऐजेंडे में लोकसभा का चुनाव है और दोनों ही दल की चाहत ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर क़ब्ज़ा करने की है. सीटों के बंटवारे को लेकर भी इस बार कई पेंच फंसने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इससे कहीं पहले परिषद के लिए मनोनयन कोटे की सीटों का मामला गरमाने के पूरे आसार बन गए हैं. क़ायदे से 12 में पांच सीट भाजपा की बन रही है, पर सूत्रों पर भरोसा करें तो भाजपा को इसमें एक या दो सीट गंवानी पड़ सकती है. मनोनयन की सिफ़ारिश के लिए चूंकि नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है. इसलिए चाह कर भी भाजपा इस पर दबाव नहीं बना सकती है. विवाद से बचने के लिए इन सीटों पर मनोनयन को लटकाया भी जा सकता है. प्रदेश एवं देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए नीतीश कुमार इस संबंध में कोई फ़ैसला ले सकते हैं. फ़िलहाल नरेंद्र मोदी को आगे कर भाजपा एवं जदयू दोनों अपनी-अपनी तैयारी में जुटी हैं. जिस दिन सही में नरेंद्र मोदी प्रकट होंगे, उसी दिन पता चलेगा कि किसकी तैयारी ज़्यादा मज़बूत थी. ■

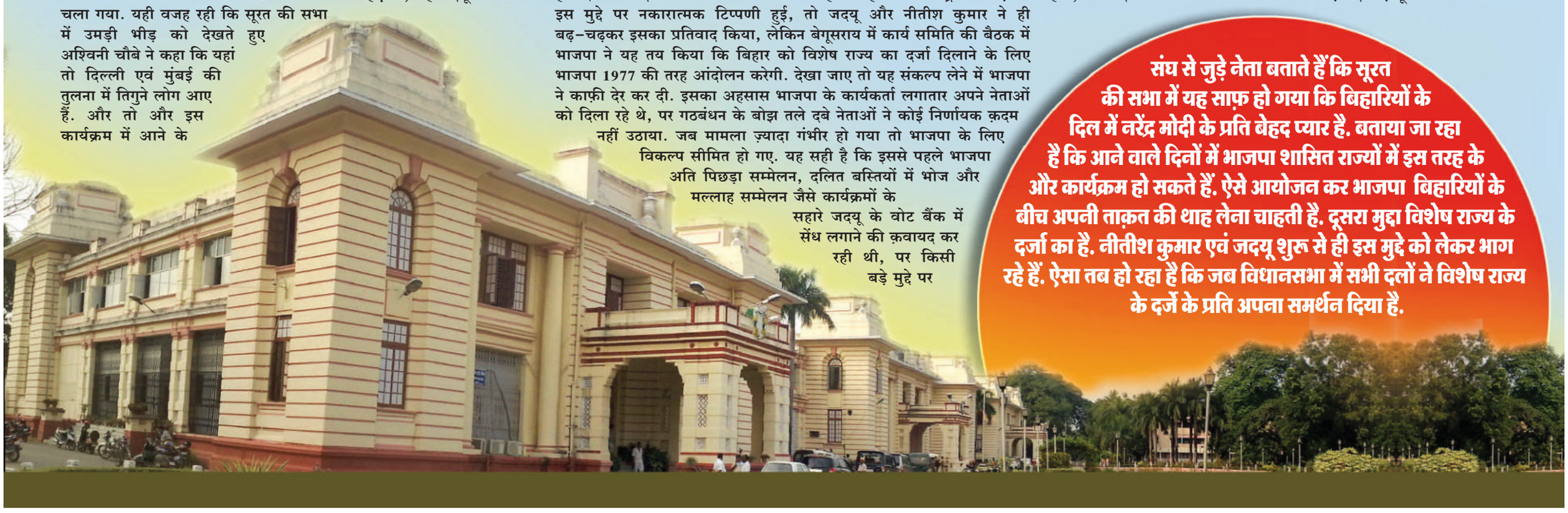

संघ से जुड़े नेता बताते हैं कि सूरत की सभा में यह साफ़ हो गया कि बिहारियों के दिल में नरेंद्र मोदी के प्रति बेहद प्यार है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित राज्यों में इस तरह के और कार्यक्रम हो सकते हैं. ऐसे आयोजन कर भाजपा बिहारियों के बीच अपनी ताक़त की थाह लेना चाहती है. दूसरा मुद्दा विशेष राज्य के दर्जा का है. नीतीश कुमार एवं जदयू शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर भाग रहे हैं. ऐसा तब हो रहा है कि जब विधानसभा में सभी दलों ने विशेष राज्य के दर्जे के प्रति अपना समर्थन दिया है.

चौथी दुनिया

सर्व शिक्षा अभियान और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता.

अगर समुचित सावधानी नहीं बरती जाए तो किसी भी क्षण आग लग सकती है और व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति हो सकती है.

परिषद की गरिमा की रक्षा पहली प्राथमिकता : सलीम परवेज

अशरफ़ अस्थानवी feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधान परिषद की अपनी एक अलग गरिमा है. इसकी गरिमा को ग्रहण नहीं लगे, इसकी ज़िम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ सदन के सदस्यों की भी है. तारकांत झा के बाद उप सभापति सलीम परवेज़ के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है. वह अपनी ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी समझते हैं. यही वजह है कि पहले दिन से ही परवेज़ अपने काम में लग गए हैं.

ग़ौरतलब है कि परिषद में सभापति तथा उप सभापति की कुर्सी पर अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक नहीं रहा. परिषद सचिवालय के रिकॉर्ड के मुताबिक़, बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त विधान परिषद में सभापति के पद पर 1922 से 1929 तक ख़ान बहादुर ख़्वाजा मुहम्मद नूर रहे. वहीं बिहार विधान परिषद में नईमा ख़ातून 12 मई, 1952 से 15 मई, 1952 तक, अब्दुल ग़फ़ूर 5 जून, 1972 से 2 जुलाई, 1973 तक, प्रो जाबिर हुसैन 6 अप्रैल, 1995 से 6 मई, 2000 तक फिर 7 मई, 2000 से 29 जून, 2000 तथा तीसरी बार 30 जून, 2000 से 15 अप्रैल, 2006 तक उच्च सदन के सभापति रह चुके हैं. उप सभापति की बात करें तो बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त विधान परिषद में सैयद हसन इमाम 7 फरवरी, 1921 से 1922 तक, ख़ान बहादुर ख़्वाजा मुहम्मद नूर 1922 में कम समय के लिए तथा सैयद नक़ी इमाम 23 जुलाई, 1937 से अक्टूबर 1939 तक इस पद पर रहे, जबकि स्वतंत्र बिहार विधान परिषद में मौलाना सैयद वली रहमानी 23 जनवरी, 1985 से 30 जुलाई, 1985 तक तथा 23 जनवरी, 1990 से 6 मई, 1990 तक इस पद पर पदासीन रहे हैं. इसके बाद वर्तमान उप सभापति सलीम परवेज़ को यह मौक़ा मिला है.

सभापति के रूप में पंडित तारकांत झा ने 6 मई, 2012 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया. भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति की वजह से उन्हें दुबारा मौक़ा नहीं दिया गया. इसके बाद सदन के प्रावधान के तहत उप सभापति सलीम परवेज़ अब सभापति के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं. अपनी इसी भूमिका के तहत उन्होंने 11 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई. इसके बाद अब वह उच्च सदन को नए परिदृश्य में कुछ नया करने की तैयारी में हैं. इस दिशा में उन्होंने अपनी पहल भी शुरू कर दी है. चौथी दुनिया से एक संक्षिप्त भेंट में उन्होंने कहा कि यहां कुछ नया करने की ज़रूरत है और वह नियम के तहत इस बाबत कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि विधान मंडल के उच्च सदन होने के नाते विधान परिषद की गरिमा और उच्च परंपरा को बनाए रखते हुए सबके सम्मान और अधिकार की रक्षा करें. वह इस बात का ख़ास ख़्याल रखेंगे और यहां जो भी कार्य हों, वह नियमानुकूल हों, क्योंकि वह स्वयं नियमों से बंधे हुए हैं.

परिषद के निवर्तमान सभापति तारकांत झा द्वारा उठाए गए कुछ क़दम तथा उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई. राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू जो लंबे इंतज़ार के बाद परिषद में वाजिब जगह नहीं पा सकी थी, वह झा के कार्यकाल में हाशिए पर चली गई. उर्दू के तीन प्रतिवेदक उनके द्वारा हटा दिए गए. इस प्रकरण में अदालती फ़रमान को भी उन्होंने नज़रअंदाज़ किया. उर्दू पत्रिका ख़ुश्बनामा तथा रूदाद का प्रकाशन बंद हो गया तथा इससे जुड़े कार्यक्रम भी बीती बातें बनकर रह गए. इस उपेक्षा से अल्पसंख्यकों को निराशा हुई, लेकिन सलीम परवेज़ के इस भूमिका में आने के बाद उनमें उम्मीदें बढ़ी हैं. ज़ाहिर है, यह बड़ी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर होगी. परवेज़ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. इस आंगन में भी उर्दू अपनी बहन हिंदी के साथ फिर चहकेगी. यहां बंद पड़ी उर्दू पत्रिका के प्रकाशन को हटाए जाने के मामले की भी समीक्षा करेंगे, ताकि भाषा को इंसाफ़ मिल सके. इन्हीं मुद्दों के साथ सबके साथ न्याय तथा समान अवसर के फ़ॉर्मूले पर विधान परिषद में कुछ नया करने की तैयारी चल रही है.

सिमरी नगर पंचायत में बहने लगी चुनावी बयार

संतोष सिंह feedback@chauthiduniya.com

ब्रिटिश शासनकाल में स्टेट के नाम से चर्चित सिमरी बख्तियारपुर में पंचायत चुनाव की बयार बहने लगी है. पहली बार नगर पंचायत का दर्जा मिलने से उत्साहित मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य लिखने के लिए बेचैन दिख रहे हैं, जबकि चुनाव में क़िस्मत आज़मा रहे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज़ हो गई हैं. बख्तियारपुर उत्तरी तथा दक्षिणी पंचायत को मिलाकर बनाए गए सिमरी नगर पंचायत के 7 हज़ार 641 पुरुष तथा 6 हज़ार 587 महिलाओं सहित कुल 14 हज़ार 288 मतदाताओं द्वारा 15 वार्डों के पार्षदों की तक़दीर लिखी जाएगी. स्थानीय लोगों के मुताबिक़, नगर पंचायत का दर्जा मिलने के पूर्व भी सिमरी बाज़ार की रौनक़ सहरसा बाज़ार से कम नहीं रही.

सिमरी बाज़ार में भी दशकों से शहरी चहल-पहल एवं रौनक़ बरक़रार है. वैसे आगामी 27 मई को नगर पंचायत का पहला चुनाव संपन्न होने के बाद वाशिंदे न केवल शहरी बाबू कहलाएंगे, बल्कि सरकार का टैक्स अदा करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा. टैक्स अदा किए जाने के बाद भी नगर पंचायत की सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि अनुमंडल के रूप में सरकारी संसाधनों का समुचित विकास ज़रूर हुआ है. नगर पंचायत चुनाव की बाबत नामांकन, समीक्षा एवं नाम वापसी के बाद अखाड़े में रह गए 15 वार्डों के कुल 111 चुनावी पहलवान न केवल चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं, बल्कि अपने-अपने चुनाव चिह्न के साथ मतदाताओं की देहरी तक पहुंचकर जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं. अब चुनावों का खट्टा-मीठा स्वाद चखने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इस बार के पंचायत चुनाव में क़िस्मत आज़माने से स्थिति रोचक बन चुकी है. सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाली सहरसा की पूर्व ज़िला परिषद उपाध्यक्ष नीलम भगत नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 से चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं. उनके पति राघव भगत वार्ड 9 से बाज़ी मारने की अलग जुगत लगा रहे हैं. हालांकि समाजसेवी एवं हाई स्कूल के दाता सदस्य कहे जाने वाले ज़िला परिषद के पूर्व प्रत्याशी भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद के पुत्र चंद्रमणि कुमार वार्ड नंबर 9 से चुनावी मैदान में कूदकर राघव के राह का कांटा बन गए हैं. वर्ष 1969 से 1972 तक विधायक रहे स्व. रामचंद्र प्रसाद द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की चर्चा कर चंद्रमणि जीत की जुगत में लगे हुए हैं.

कांग्रेस के वफ़ादार सिपाही के रूप में चर्चित युवा राजनीतिज्ञ राहिल अंसारी भी वार्ड संख्या 9 से खड़े होकर मुक़ाबले को त्रिकोणीय बनाने में लग गए हैं. लगभग सभी वर्गों के बीच लोकप्रिय राहिल युवाओं के बीच अलग पहचान रखते हैं. वार्ड संख्या 11 से भाग्य आज़मा रहे बिहार पीपुल्स पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष इक़बाल आलम पूर्व सांसद आनंद मोहन के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं. भाजपा के मंडल अध्यक्ष रह चुके विजय कुमार वार्ड संख्या 15 से चुनाव लड़ रहे हैं. ग़रीब और दलित महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती आ रही सिया देवी वार्ड संख्या 10 से चुनावी वैतरणी पार करने के लिए चुनावी मोहरे बिछाने में लगी हैं. कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सभी 111 चुनावी पहलवान अपनी-अपनी जीत का पैमाना जनता के साथ किए गए सदाचारों को मानते हुए जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन सभी की निगाहें राजनीति के दो दिग्गज खिलाड़ियों यथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली क़ैसर एवं खगड़िया के सांसद दिनेश चंद्र यादव की राजनीतिक दांवपेंच पर टिकी है. वैसे यह अलग बात है कि सिमरी बख्तियारपुर गृह क्षेत्र होने के बाद भी राजनीति के दोनों खिलाड़ियों का राजनीतिक खींचतान फ़िलवक़्त नज़र नहीं आ रहा है. यह क़यास लगाया जा रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक डॉ. अरुण कुमार यादव नगर पंचायत के इस चुनाव में अपने चहेते प्रत्याशियों की जीत के लिए राजनीतिक गोटी खेल सकते हैं. चुनाव परिणाम के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाले समय में स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी देवेंद्र कुमार दर्द नगर पंचायत चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के प्रति संकल्पित है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लगे निर्वाचित पदाधिकारी का कहना है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. ■

एक नज़र

हत्या या आत्महत्या

चतरा ज़िले के लावालौंग प्रखंड स्थित सीआरपीएफ पिकेट में तैनात हेड कांस्टेबल उमाशंकर सिंह की आत्महत्या का मामला उलझता जा रहा है. मृतक बक्सर ज़िला अंतर्गत करहसी गांव का रहने वाला था. यह घटना बीती 6 मई की है, जब लावालौंग पिकेट से यह सूचना आई कि सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल उमाशंकर सिंह ने अपने ही राईफल से स्वयं को गोली मार ली. घटना के बाद जब शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल लाया गया तो लाश की स्थिति देखने से लग रहा था जिस प्रकार सर पर गोली लगी है, वह आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है. वहीं सीआरपीएफ के कमांडेंट बीके वर्मा का कहना है कि लावालौंग कैंप में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, उमाशंकर पारिवारिक तनाव में था.

स्थानांतरण के बाद भी विद्यालय सहायक जमे हैं

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की बात अब आम हो गई है. इसका परिणाम यह है कि जिसकी मर्ज़ी वही अपना उल्लु सीधा करने में लगा है. हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय में अव्यवस्थित राजकीयकृत रामनारायण प्लस टू उच्च विद्यालय के सहायक के पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार तिवारी स्थानांतरण के बावजुद पिछले छः माह से जमे हैं. सहायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की मिलीभगत के कारण ज़िला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा की चुप्पी रहस्यमय साबित हो रही है. इस बाबत ज़िला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार सिंहा ने चौथी दुनिया को बताया कि सहायक के स्थानांतरण से संबंधित फाईल गुम हो गई है, जिसकी खोज की जा रही है.

पंचायत उपचुनाव में तीन उम्मीदवार मैदान में

आगामी 29 मई को होने वाले पंचायत उपचुनाव में चतरा ज़िले के हंटरगंज प्रखंड से एकमात्र पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तीन महिला उम्मीदवार मैदान में रह गई हैं. इनमें धर्मिला देवी, सरिता देवी तथा बैजयंती देवी का नाम प्रमुख है. इन तीनों उम्मीदवारों में सदस्य के तौर पर धर्मिला देवी सर्वाधिक चर्चा में हैं. धर्मिला देवी को राज्य में सक्रिय प्रमुख राजनितिक संगठन का सर्मथन प्राप्त है, जिसके कारण उनके जीत की संभावना बढ़ गई है.

– अमरेंद्र प्रताप सिंह

मेडिजोन अस्पताल का उद्घाटन

आधुनिक साधन-संसाधन से सुसज्जित मेडिजोन हॉस्पिटल का पटना में उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यहां के चिकित्सकों की चिकित्सीय दक्षता के कारण विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों को इलाज कराने में आसानी होगी. चौबे ने बिहार के बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा अब बिहार से बाहर भी होती है. मुख्य अतिथि डॉ. दिलीप सेन तथा पद्मश्री डॉ. एसएन आर्य की मौजूदगी में डॉ. बिनोद चौधरी, पद्मश्री डॉ. नरेंद्र प्रसाद, पद्मश्री डॉ. इंद्रभूषण सिन्हा, पद्मश्री डॉ. विजय प्रकाश, पद्मश्री डॉ. प्रो. यूसी सांवल आदि उपस्थित थे. उद्घाटन के पश्चात मेडिजोन हॉस्पिटल के निदेशक मंडल सदस्य शिवशंकर प्रसाद, डॉ. रामजी प्रसाद, डॉ. अनिष्णु प्रकाश तथा डॉ. अमरेंद्र ने कहा कि मेडिजोन हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक और कर्मचारी रोगियों के इलाज एवं देखभाल के लिए सदैव तत्पर रहेंगे. ■

– चौथी दुनिया ब्यूरो

नियमित दिनचर्या सेहत के लिए ज़रूरी

डॉ. डीएस सिंह

आज के दौर में सर्जरी में लगातार इज़ाफ़ा होने के कारण आम लोगों के साथ-साथ चिकित्सक भी ख़ासे परेशान हैं. इस बारे में पटना के जाने माने सर्जन डॉ. डीएस सिंह ने ख़ास जानकारी दी.

सर्जरी कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

वर्तमान दौर में भी लोगों के चिकित्सा के प्रति जागरूक नहीं रहने के कारण सर्जरी कराने की स्थिति उत्पन्न होती है.

लोग छोटी-मोटी बीमारी के इलाज के लिए झोलाछाप चिकित्सकों के चक्कर में पड़कर अपने रोग को इतना गंभीर बना लेते हैं कि जिस रोग का इलाज दवा से संभव है, उसका इलाज सर्जरी द्वारा कराना पड़ता है.

सर्जरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

पौष्टिक आहर, नियमित दिनचर्या तथा व्यायाम करते रहने से न केवल सर्जरी, बल्कि विभिन्न रोगों से भी बचा जा सकता है. किसी तरह की हल्की परेशानी महसूस होते ही लोगों को चिकित्सक की सलाह लेते हुए जांच करानी चाहिए. वर्तमान समय में जांच की प्रक्रिया इतनी सरल है कि अविलंब रोग का पता चल जाता है.

सर्जरी के बाद परहेज़ के तौर पर क्या करना चाहिए?

झोलाछाप चिकित्सकों के चक्कर में पड़ने की बजाय किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सर्जनी कराते हुए सदैव सलाह लेते रहना चाहिए. बेहतर खान-पान और अनुशासित दिनचर्या अपनाना श्रेयस्कर होगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

चंपारण में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं

इंतेज़ारुल हक़ feedback@chauthiduniya.com

बिहार की सुशासन सरकार भले ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने एवं बेहतर भवन बनाने के साथ-साथ सभी वर्गों के छात्रों को अलग-अलग कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था करने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है. पूर्वी चंपारण ज़िले में क़रीब चार सौ विद्यालय अभी ऐसे हैं जिनके पास न तो अपनी भूमि है और न भवन. कुछ विद्यालय पेड़ के नीचे चलते हैं तो कुछ किराये के मकान में. यहां विद्यालय मस्जिद के बरामदे में भी वर्षों से चल रहे हैं और इसकी चिंता न तो विभाग को है और न प्रशासन को. पेड़ के नीचे चलने वाले तमाम विद्यालय नवसृजित हैं, तो मस्जिदों एवं किराये के मकानों में चलने वाले विद्यालय प्राथमिक हैं. सर्व शिक्षा अभियान और सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता. ज़िले के बंजरिया, सुगौली, बनकटवा, छौड़ादानो, रामगढ़वा, ढाका समेत कई प्रखंडों में नवसृजित विद्यालय पेड़ के नीचे चलते हुए देखे जा सकते हैं. हालांकि भूमि के लिए विभाग के पास राशि है, लेकिन लापरवाही के कारण भूमिदाता भूमि देने से परहेज़ कर रहे हैं और विद्यालयों की यह स्थिति बनी हुई है. वर्ष 2006 में ज़िले में 786 नवसृजित विद्यालय खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी. ज़िला मुख्यालय का भी यही हाल है और यहां भी कई विद्यालय किराये के मकानों में एवं मस्जिदों के बरामदे में संचालित हो रहे हैं. पेड़ के नीचे चलने वाले विद्यालयों में साल में छह माह ही पढ़ाई होती है और छह माह शिक्षक और बच्चे आराम फ़रमाते हैं. कारण यह है कि बरसात का मौसम आते ही इन विद्यालयों में छुट्टी हो जाती है और बच्चे अपने-अपने घरों में रहते हैं. बंजरिया एवं सुगौली प्रखंड बाढ़ प्रभावित होने के कारण यहां की स्थिति और दयनीय हो जाती है.

ज़िले के बंजरिया, सुगौली, बनकटवा, छौड़ादानो, रामगढ़वा, ढाका समेत कई प्रखंडों में नवसृजित विद्यालय पेड़ के नीचे चलते हुए देखे जा सकते हैं. हालांकि भूमि के लिए विभाग के पास राशि है, लेकिन लापरवाही के कारण भूमिदाता भूमि देने से परहेज़ कर रहे हैं और विद्यालयों की यह स्थिति बनी हुई है.

ज़िला मुख्यालय के चिकपट्टी मोहल्ले में दो प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, जिनकी हालत देखने से ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां बच्चों को पढ़ाने लायक़ कोई व्यवस्था है. ज़िला प्रशासन की नाक के नीचे यह दोनों ही प्राथमिक विद्यालयों के पास न तो अपनी भूमि है और न ही भवन. दूसरों की दया पर चलने वाले यह विद्यालय बेहाल हैं और इसमें वहीं बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूरे ज़िले में विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, ऐसे में ज़िला मुख्यालय स्थित इस विद्यालय के लिए ज़मीन और भवन की व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही है. यह तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बेहतर तरीक़े से बता सकते हैं. राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू कन्या चिकपट्टी मस्जिद में चलाया जाता है. मस्जिद के पश्चिमी छोर पर एक खपरैल का छोटा सा बरामदा है, जिसमें यह विद्यालय संचालित होता है. इस विद्यालय में 1 से 5 वर्गों की पढ़ाई की जाती है और इस छोटे से बरामदे में सभी बच्चों को बैठाने का समायोजन किया जाता है. विद्यालय के पास न तो अपना शौचालय है और न चापाकल और न ही पोषाहार बनाने के लिए कोई शेड. इस विद्यालय से 10 मीटर की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम बैकवर्ड कम्युनिटी चिकपट्टी स्थित है. इस विद्यालय के पास भी न तो अपनी भूमि है और न भवन. इस विद्यालय का संचालन भी दूसरों की दया पर की जाती है. कुरैशी कमेटी द्वारा बनाई गई कमेटी भवन में इस विद्यालय को संचालित किया जाता है. विद्यालय में एक ही कमरा है, जिसमें कार्यालय, पोषाहार बनाने एवं वर्ग संचालन करने का कार्य संचालित किया जाता है. सरकार द्वारा किया जाने वाला ख़र्च इन विद्यालयों में व्यर्थ ही साबित हो रहा है, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. ज़िला शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहे लाख ढिंढोरा पीटें, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त बिल्कुल अलग है. ■

आर्य समाज कन्या विद्यालय

वर्चस्व की लड़ाई में पढ़ाई चौपट

मनेंद्र कुमार feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया ज़िले के इकलौते आर्य समाज मंदिर से संबद्ध आर्य कन्या विद्यालय दो गुटों की लड़ाई के कारण ख़स्ता हालत में है. विद्यालय की स्थिति दिनोदिन बदहाल होती जा रही है और ज़िला प्रशासन चैन की निंद्रा में सो रहा है. विवाद जब चरम पर पहुंचता है, तब ज़िला प्रशासन की नींद खुलती है, लेकिन विवाद के स्थाई निदान के प्रति ज़िला प्रशासन कभी गंभीर नहीं होता है. प्रसिद्ध समाजसेवी श्यामलाल, वीरगुरु, छोटेलाल एवं यमुना प्रसाद के भागीरथ प्रयास से स्थापित आर्य समाज मंदिर, यज्ञशाला, वेद आधारित शिक्षा हेतु गुरुकुल, कन्या विद्यालय तथा अनाथालय की स्थिति को देखकर लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन राजनीतिज्ञों का इस तरह की स्थिति से कोई सरोकार नहीं रह गया है. बालिकाओं को अच्छी तालीम दिए जाने के मामले में अव्वल आर्य कन्या उच्च विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है. लेकिन इधर के दिनों में विद्यालय की प्रबंधन कमेटी को लेकर दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है. विवाद का स्थाई निदान नहीं होने से नाराज़ आर्य समाज की प्रवक्ता डॉ. ऋचा योगमयी द्वारा कई बार विरोध का स्वर बुलंद किया गया. बार-बार विरोध किए जाने के बाद भी इस संदर्भ में जब कोई कारगर क़दम नहीं उठाया गया, तब मजबूर होकर योगमयी द्वारा नई प्रबंध कमेटी के गठन को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष आमरण अनशन भी किया गया. आमरण अनशन के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर ज़िला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-1113/-16.03.12 के ज़रिए चुनाव कराए जाने का आदेश जारी किया. हालांकि योगमयी का कहना है कि आर्य समाज खगड़िया की मान्यता का निर्णय प्रांतीय सभा द्वारा लेने की बात पर समझौता करते हुए अनशन समाप्त किया गया था. प्रांतीय सभा से अनुमोदित समिति के प्रधान निर्मल ज्ञानमयी के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके तहत संपन्न चुनाव में महादेव प्रसाद अध्यक्ष एवं नील कमल दिवाकर सचिव निर्वाचित किए गए. वर्तमान सचिव डॉ. विद्यानंद दास का कहना है कि खगड़िया आर्य समाज एक स्वतंत्र इकाई है. कन्या सोसायटी एक्ट के तहत संचालित आर्य समाज में प्रतिनिधि, संगठन या बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. दास का यहां तक दावा है कि आर्य समाज चुनाव कराने या संगठन खड़ा कराने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र है. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित संस्था में किसी बाहरी व्यक्ति या सरकारी प्रतिनिधि के साथ-साथ सभा द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रावधान नहीं है. इतना ही नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किए जाने तथा प्रबंधन अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत निबंधित आर्य कन्या विद्यालय के अंदरूनी अथवा बाह्य मामले में सरकार को भी हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर दास की बातों पर भरोसा करें तो वह 1999, 2002, 2005, 2008 के साथ-साथ 2011 में भी लगातार सचिव पद के लिए चुने गए हैं. उधर कुछ लोगों द्वारा मनमाने तरीक़े से विद्यालय की विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है. एकतरफ़ा चुनाव किया जाना नियम के विपरीत है. यही कारण है कि इस तरह की स्थिति के ख़िलाफ़ अपील दायर करते हुए स्थानीय व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ़ कोर्ट में दीवानी मामला दायर किया गया है. ज़िला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पत्रांक-501/05.03.2012 के आलोक में आर्य कन्या उच्च विद्यालय की वैद्य

प्रबंध कार्यकारिणी समिति के विवाद को निष्पादित करने का आदेश जारी किया गया. 1968 में स्थापित आर्य कन्या उच्च विद्यालय एक धार्मिक अल्संख्यक विद्यालय है. इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् बिहार, पटना द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया था तथा बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ज्ञापांक-120-22/15.12.1976 द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की गई है. विद्यालय के प्रबंध कार्यकारिणी समिति को लेकर पूर्व से विवाद चलना गंभीर मामला है. विवाद के कारण ही पूर्व के ज़िला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी समिति

खगड़िया

को मान्यता नहीं दी गई है. विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों के पांच पद रिक्त रहने के कारण पठन-पाठन कार्य भी प्रभावित हो रहा है. विभागीय आदेश के तहत विद्यालय का उचित प्रबंधन होना तो आवश्यक है ही, पठन-पाठन सुचारू रूप से होना भी मायने रखता है. जानकारों के मुताबिक़, विधिसम्मत राय से विवाद का निपटारा विद्यालय हित एवं शिक्षा हित में आवश्यक है. बावजूद इसके ज़िला प्रशासन द्वारा इस संदर्भ में कोई क़दम नहीं उठाना आश्चर्य का विषय है. ज़िले की गौरवमयी आर्य कन्या उच्च विद्यालय में वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही विधि व्यवस्था सहित पठन-पाठन की स्थिति बदहाल होती जा रही है. ■

बेदख़ल होकर फ़रियादी पहुंचे थाना

गोगरी अनुमंडल अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के परबत्ता गांव में बीते दशक से न्याय की लड़ाई लड़ रहे ग्रामीण आज भी संघर्षरत नज़र आ रहे हैं. मामले को लेकर माले नेता अरुण दास के साथ परबत्ता थाना पहुंचकर जामुन मंडल, कमलेश्वरी मंडल, विंदेश्वरी मंडल, अर्जुन मंडल, रमेश मंडल, राघो मंडल, अरुण मंडल, हरिलाल मंडल, मोती यादव एवं रसिया देवी ने बताया कि दो दशक पूर्व स्थानीय चर्चित जामुन को कई व्यक्तियों ने दो हज़ार रुपये देकर प्राप्त किया, लेकिन ज़मींदार द्वारा कोई रसीद नहीं दी गई थी. ज़मीन का मूल्य बढ़ने के कारण ज़मींदार लिखने से आनाकानी कर रहे हैं. वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने स्थानीय थाना से जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद अब यह पुराना मामला चर्चा में आ गया. उक्त जांच रिपोर्ट के समर्थन में लोगों ने अपना-अपना पक्ष भी रखा. थाना अध्यक्ष कृपा शंकर आज़ाद ने लोगो से कई बिंदुओं पर पूछताछ की. थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी बिंदुओं की जांच रिपोर्ट शीघ्र ही एसडीओ को सौंप दिया जाएगी.

- मनेंद्र कुमार

पथ का हाल बदहाल

परबत्ता प्रखंड के कुल्हडिया - कोलवारा पथ बदहाली के कगार पर है .जिसकी सुधी लेने वाला कोई नही है इक्त पथ दो पंचायतो को जोड़ती है .बताते चले कि पूर्व विधान पार्शद स्व जगदम्बी मंडल का कर्मभूमी है तथा इनके पुत्र राहुल कुमार वहाँ का मुखिया है जदयु के प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मंडल ने कहा कि राषि कि बंदर बाट स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कर लिया जाता है वही पंचायत के मुखिया राहुल कुमार ने कहा कि पथ का निर्माण कार्य पंचायत से कराना संभव नही है .वही बीडीओ रामप्रवेष प्रसाद ने कहा कि जल्द इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी.

- गीता कुमार

समग्र विकास के लिए दीवाना बना टुनटुन

संजय सोनी feedback@chauthiduniya.com

स्वार्थ के इस युग में जहां लोग अपने लिए ही सपना बुनने में लगे रहते हैं, वहीं कोसी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए क़रीब डेढ़ दशक से एक दलित व्यक्ति दीवाना बना हुआ है. इस युवक की दीवानगी का ही कमाल है महिषी के बलुआहाघाट स्थित कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल. प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति तक को निरंतर पत्र लिखकर कोसी के समग्र विकास की मांग करते रहने वाला दलित टुनटुन पासवान सहरसा ज़िला अंतर्गत महिषी प्रखंड के पस्तवार गांव का रहने वाला है. उनका दावा है कि महिषी के बलुआहाघाट स्थित कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल उनके एवं दलित सेवा समिति सत्य समाज के साथ-साथ संत गोविंद आश्रम के ही संघर्ष का नतीजा है.

इतना ही नहीं, अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध तरीक़े से आंदोलन करने वाला टुनटुन धरना-प्रदर्शन के अलावा सत्याग्रह,जलासन एवं वृक्षासन भी कर चुका है. यह दलित व्यक्ति फ़िलवक़्त विभिन्न सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चक्र बनाने में लगा है और आंदोलन के जरिए ही भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारी को बेनक़ाब करने का संकल्प ले चुका है. टुनटुन के मुताबिक़, कोसी नदी के बलुआहा घाट पर निर्माणाधीन सेतु का नाम डॉ. अंबेदकर सेतु रखने, कोसी क्षेत्र को बिहार की उप राजधानी बनाने, कोसी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने, वर्ष 2008 के कुसहा बाढ़ पीड़ितों को समुचित मुआवज़ा प्रदान करने सहित महंगाई पर अंकुश लगाने एवं मनरेगा को बिचौलियागिरी से मुक्त कराने आदि को लेकर वह संघर्षरत हैं. पासवान के 12 सूत्री मांगों पर ग़ौर करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अवर सचिव राम अवतार आज़ाद ने अपने पत्र (पत्रांक 12252 दिनांक 11 नवंबर, 2011) के ज़रिए तथा सरकार के उप सचिव राम उद्गार महतो ने राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त अपर सचिव सुधीर श्रीवास्तव के पत्र के आलोक में (पत्रांक 4277 दिनांक 23 सितंबर, 2011) कृत कार्रवाई से अवगत कराया है, जबकि भारत के राष्ट्रपति एडिशनल कंट्रोलर केसी जयाराजन ने भी बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र (सं. पीटू/ई 2010110231 दिनांक 20 अक्टूबर, 2011) के ज़रिए संबंधित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. युवक पासवान का कहना है कि बलुआहा घाट पर पुल निर्माण के लिए कोसी नदी में जलासन एवं वृक्षासन तक किया गया है.

आंदोलन एवं पत्राचार के बाद राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा राज्य सरकार से इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा गया है. अब इस पुल निर्माण का राजनीतिक लाभ उठाने वालों की कोसी क्षेत्र में कमी नहीं रह गई है. टुनटुन यह भी कहते हैं कि जब तक कोसी क्षेत्र का समग्र विकास नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. सत्य की जय हो, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, इसी मूलमंत्र पर संघर्षरत टुनटुन वर्तमान परिवेश में लोगों के लिए प्रेरक बन गया है. कोसी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि काश! रोज़ पैदा होता टुनटुन, तो शायद कोसीवासियों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता. ■

फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में अपार संभावनाएं

करियर

कहीं पर भी आग लग जाना एक सामान्य सी घटना है. कोई भी मौसम हो. घर, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, म्यूज़ियम, अभिलेखागार, हवाई अड्डा, गोदाम, बस अड्डा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेट्रोल पंप, गैस फीलिंग स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, कल-कारख़ाना आदि में आग लगने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. अगर समुचित सावधानी नहीं बरती जाए तो किसी भी क्षण आग लग सकती है और व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति हो सकती है. इन्हीं कारणों से फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में कैरियर की व्यापक संभावनाएं बढ़ती जा रही है. चौथी दुनिया से इस विषय पर ख़ास बातचीत करते हुए पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ फायर और सेफ्टी मैनेजमेंट के निदेशक ललन कुमार प्रसाद ने कहा कि करियर की दृष्टि से सेफ्टी फायर मैनेजमेंट की पढ़ाई करना बेहद लाभकारी है. किए गए सर्वे के अनुसार, वर्तमान में हमारे देश में अढ़ाई लाख से अधिक फायर पर्सन की ज़रूरत है. वर्तमान समय में सिर्फ़ बिहार के 57 अनुमंडलों में फायर स्टेशन स्थापित करने की बाबत फायर स्टेशन अफ़सर तथा सब फायर अफ़सर के 57-57 पद, हेड फायरमैन एवं फायर टेंडर ड्राइवर के 114-114 पद, जबकि 570 फायरमैन सहित कुल 912 पदों के लिए बहाली होना तय है. इसके लिए बीते 18 जनवरी को मंत्रिमंडल द्वारा पद सृजित भी कर दिया गया है. वैसे फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने पर फायर स्टेशन अफ़सर, फायर इंसपेक्टर, फायर सुपरवाईजर, फायर अफ़सर, फायर इंजीनियर, फायर एलार्म टेक्नीशियन, फायरमैन, हेड फायरमैन तथा फायर इंजन ड्राइवर के पद पर बहाली संभव है. कल कारख़ानों में बिजली का उपयोग करने पर शॉर्ट सर्किट के कारण हमेशा आगज़नी का ख़तरा बना रहता है. 85 प्रतिशत आगज़नी की घटनाएं केवल शॉर्ट सर्किट के कारण ही होती हैं. ऐसी परिस्थिति में दक्ष फायर पर्सन की आवश्यकता लगभग सभी जगह महसूस की जा रही है. फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद अच्छे-ख़ासे वेतनमान पर बेरोज़गार छात्र-छात्राओं को नौकरी मिलना आसान है. एक सवाल के जवाब में निदेशक ने कहा कि सेफ्टी शिक्षण संस्थान का चुनाव करते समय शिक्षण संस्थान की फैकल्टी पर ध्यान देते हुए यह जानना ज़रूरी है कि अच्छी फैकल्टी के कारण देश के कोने-कोने से फायर मैनेजमेंट पर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संस्थान को आमंत्रित किया जाता है या नहीं. हालांकि तमाम दृष्टिकोण से पटना के एक्ज़ीबिशन रोड स्थित आशियाना गैलेक्सी में संचालित पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ फायर सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ही उपयुक्त संस्थान है.

फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी दूरभाष सं. 0612, 3297011, 9334107607, 9234929075, 9308067238 पर ली जा सकती है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree in the following Subjects :
• Fire Safety Management • Industrial Safety Management • Occupational Safety & Health Management • Environmental Safety & Health Management
Only one Institute of Bihar where students of Bihar, Magadh & Several other Universities and Employees of industrial organizations of all over India get theoretical & Practical training in fire & Safety Management.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Website : www.psfsm.in
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-3297011, Mob. : 9334107607, 9234929075

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) सत्र 2012-14 में नामांकन हेतु अधिसूचना

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया द्वारा दो वर्षीय बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा) पाठ्यक्रम में 500 सीटों के नामांकन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योग्यता-: -i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री। (अनु. जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छुट) ii) वैसे विधिवत् नियुक्त सेवारत शिक्षक/शिक्षिका जिन्हें केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम दो वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो। आरक्षण या 5% प्राप्तांक में छूट का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को नियमानुकूल दिया जायेगा। निर्धारित अर्हता नहीं होने पर फार्म न भरें अन्यथा प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

आवेदन-पत्र (विवरणिका के साथ) दिनांक 03 मई 2012 से 05 जून, 2012 तक निम्नलिखित अध्ययन केन्द्रों से निर्धारित शुल्क रूपये 800/- (सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति के लिए) एवं रूपये 500/- (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) नगद या बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। 1) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, म.वि.वि., बोधगया 2) गया कॉलेज गया 3) जे.डी. वीमेन्स कॉलेज, पटना 4) ए.एन. कॉलेज पटना 5) श्री अरविन्द महिला कॉलेज, पटना। 6) एस. सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद 7)नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बी.एम.दास रोड, पटना 8) नालन्दा कॉलेज बिहारशरीफ । बैंक ड्राफ्ट Director, DDE, M.U., Bodh Gaya के नाम से देय तथा अदाकर्त्ता शाखा Bodh Gaya होना चाहिए। निदेशालय के website: www.mudde.org द्वारा downloaded आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित तिथि तक बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र केवल दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मुख्यायालय, बोधगया एवं ए.एन. कॉलेज, पटना में ही निर्धारित तिथि तक जमा किया जायेगा। प्रवेश पत्र का वितरण, प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की सूचना जून, 2012 के अंतिम सप्ताह में वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार
डॉ. मो. इसराईल खां
निदेशक

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

PATLIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT

An ISO 9001 :2008 Certified Institution

Authorised study centre o EIILM University , Code - CIIP/101683

SERVICE WITH SAFETY

Estd. 2000

DIPLOMA/PG DIPLOMA/BACHELOR DEGREE/PG DEGREE

In the following subject

- FIRE SAFETY MANAGEMENT
- INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
- ENVIRONMENTAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT
- OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT

Only one institute of Bihar Where students of Bihar, Magadh & Several other universities and employees of industrial organizations of all over india get theoretical & Practical training in the fire & Safety Management

फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट में रोजगार की अपार संभावनाएं : ललन

बढ़ते इंडस्ट्रीज से देश–विदेश का विकास जिस कदर बढ़ रहा है,उसी तरह सुरक्षा के सवाल पर सरकारी और गैरसरकारी कंपनियां भी गंभीर होती जा रही है. जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सुरक्षा संबंधित मामले में दक्ष लोगों के लिए नए–नए रोजगार के अवसर भी सामने आ रहे हैं. पटना स्थित पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट ने 'सेफ्टी' के मामले में शिक्षार्थियों को दक्ष करने के बावत एक अभियान छेड़ रखा है. इस संदर्भ में चौथी दुनिया से निदेशक ललन कुमार प्रसाद से हुई बातचीत के आधार पर खास रपट.

बढ़ते इंडस्ट्रीज से देश –विदेश का विकास जिस कदर बढ़ रहा है उसी तरह जान माल की सुरक्षा के सवाल पर सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएं भी गंभीर होती जा रही है.

आए दिन देश–विदेश या महानगरों में घटित होने वाली आगजनी की घटनाएं इस बात को पुख्ता करती है कि या तो कंपनियां सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है या सुरक्षा संबंधित मामलों में दक्ष लोगों की बेहद कमी है. लेकिन पटना स्थित 'पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट' ने सेफ्टी के मामले में लोगों को दक्ष करने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है. बीते वर्श 2000 में स्थापित इस संस्थान के निदेशक ललन कुमार प्रसाद से चौथी दुनिया ने कई पहलू पर खुलकर जब बातचीत की तो कई तथ्य उभरकर सामने आए. संस्थान के निदेशक प्रसाद से जब यह पूछा गया कि वर्त्तमान परिवेश में अभिभावकगण अपने बच्चों को बीसीए, एमसीए सहित अन्य तरह का कोर्स कराकर उन्हें क्षितिज पर देखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में लोग आपकी संस्थान की ओर क्यों मुखातिब हों,तो उन्होंने बेबाकी के साथ कहा कि अन्य शिक्षण संस्थान बीसीए, एमसीए सहित अन्य तरह की तकनीकी शिक्षा देने के बाद भी शिक्षार्थियों के लिए निश्चित तौर पर नौकरी की राह आसान नहीं कर पाती है. कभी–कभी शिक्षार्थी नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में भटकाव के माहौल में जीना शुरू कर देते हैं. लेकिन पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ फायर एण्ड सेफ्टी मैनेजमेंट 'सेफ्टी' के मामले में शिक्षार्थियों को अच्छी तालीम देकर न केवल आत्मविश्वास से लबरेज करती है बल्कि उनके लिए नौकरी की राह भी आसान कर देती है. सेफ्टी संबंधित मामलों में दक्ष करने का दावा करने वाली अन्य कंपनियां शिक्षार्थियों को इस तरह का तालीम नहीं दे पाती है कि मान्यता प्राप्त कंपनियों में रोजगार मिल ही जाय लेकिन इस संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वाले सैकड़ों शिक्षार्थी न केवल विभिन्न कंपनियों में अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं बल्कि लगभग 3500 शिक्षार्थी रिलायंस, टाटा, टाटा मोटर्स, एलएनटी, गेमन इंडिया, रिफाइनरी, थर्मल पावर सहित अन्य विख्यात कंपनियों में बड़ों पदों पर हैं. वैसे भी सेफ्टी के लिए देश–विदेश में अच्छे वेतनमान पर सर्वाधिक वेकेंसी है. ऐसा इसलिए क्योंकि मशीनें अपने आप नहीं चलती है. मशीन चलाने के लिए इंसान और विद्युत की आवश्यकता होती है. ऐसी परिस्थिति में आगजनी की संभावित घटनाओं के कारण कर्मचारी सहमे–सहमे रहते हैं और आगजनी की संभावना मात्र से कर्मचारियों के कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है. अगर कर्मचारी अपने आपको सदैव सुरक्षित महसूस करेंगे तो कार्य का परिणाम भी बेहतर आना तय है. अक्सर देखा गया है कि शॉट सर्किट के कारण कल कारखानों में जब आग लगती है, तब व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति होती है. लेकिन दक्ष लोगों के नहीं रहने के कारण आग पर काबू पाना आसान नहीं रह जाता है.

जब तक सरकारी या अन्य स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो जाता है. प्लांट के एक्सपर्ट के साथ–साथ सेफ्टी के प्रति सरकारी और गैरसरकारी कंपनियां गंभीर होती जा रही है और इस क्षेत्र में रोजगार के नए–नए अवसर भी सामने आते जा रहे हैं. एक सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि जहां तक संस्थान के द्वारा बीपीएल परिवार के सदस्यों के लिए अलग से व्यवस्था किए जाने की बात है तो फिलवक्त इस तरह का कोई नियम कानून नहीं है लेकिन मानवता के आधार पर आर्थिक रूप से विपन्न शिक्षार्थियों के लिए संस्थान हरसंभव मदद करती है. प्रसाद के मुताबिक उनकी संस्थान के द्वारा शिक्षार्थियों के सामने कई अत्याधुनिक उपकरण सामने रखकर उसके उपयोग की बारीक से बारीक जानकारियां दी जाती है. जिसके कारण उनके संस्थान से दक्ष शिक्षार्थी अन्य संस्थान के शिक्षार्थी के सामने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा ही लेते हैं. अभी तक 365 शिक्षार्थियों का आर्मी में भी बतौर प्लांट एक्सपर्ट चयन होना, इस बात का प्रमाण है कि पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ सेफ्टी एण्ड मैनेजमेंट अन्य संस्थान से कहीं न कहीं बहुत आगे है. ●

FREE

Demo - Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Website : www.psfsm.in

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna - 800 001 Ph : 0612-3297011, Mob : 9334107607, 9234929075

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 21 मई–27 मई 2012

www.chauthiduniya.com

फिर निकला आरक्षण का जिन्न

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पदोन्नतियों में आरक्षण के खेल में समाजवादी पार्टी और बसपा ने तो अपना रुख़ साफ़ कर दिया है, लेकिन इस खेल में कांग्रेस और भाजपा रुको और देखो की भूमिका में हैं. वे मौक़ा देखकर अपनी राजनीति को परवान चढ़ाएंगीं. एक तरफ़ नेता राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ पदोन्नति में आरक्षण की मुख़ालफ़त और समर्थन करने वाले कर्मचारी संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है. एक ओर पदोन्नतियों में आरक्षण की वकालत करने वाले अदालत का फ़ैसला पलटने के लिए शाहबानो प्रकरण की तरह संविधान संशोधन करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल और पदोन्नतियों में आरक्षण की वकालत करने वाले बताएं कि क्यों ऐसी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए. आरक्षण का जिन्न लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में विचरण कर रहा है.

संजय सक्सेना

feedback@chauthiduniya.com

आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है. इस बार सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला इसे बाहर ले आया है. सरकारी नौकरियों में पदोन्नतियों में आरक्षण ख़त्म करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी में आरक्षण के जिन्न ने जान फूंक दी है. कोर्ट के फ़ैसले का विरोध करते हुए बहुजन समाज पार्टी दलितों का सच्चा हितैषी बनने का ड्रामा करने में लग गई है, वहीं समाजवादी पार्टी इस फ़ैसले के सम्मान की बात करके नया जातीय राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी है. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आते ही उसके पक्ष में खड़े होकर समाजवादी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न केवल बसपा सुप्रीमो मायावती के सर्वजन और बहुजन समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया है, बल्कि अदालत के आदेश का सम्मान करने की बात करके अगड़ों–पिछड़ों का नया समीकरण बनाने के अभियान को आगे बढाने में लग गए हैं. इसमें मुस्लिम भी उसके साथ होंगे. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मद्देनज़र अखिलेश सरकार ने सभी विभागों में पदोन्नतियों में आरक्षण को ख़त्म करने का शासनादेश जारी करके गेंद अब विरोधियों के पाले में डाल दी है. पदोन्नतियों में आरक्षण के खेल में समाजवादी पार्टी और बसपा ने तो अपना रुख़ साफ़ कर दिया है, लेकिन इस खेल में कांग्रेस और भाजपा रुको और देखो की भूमिका में है. वे मौक़ा देखकर अपनी राजनीति को परवान चढ़ाएंगी. एक तरफ़ नेता राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ पदोन्नति में आरक्षण की मुख़ालफ़त और समर्थन करने वाले कर्मचारी संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है. एक ओर पदोन्नतियों में आरक्षण की वकालत करने वाले अदालत का फ़ैसला पलटने के लिए शाहबानो प्रकरण की तरह संविधान संशोधन करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इसका विरोध करने वाले पूछ रहे हैं कि राजनीतिक दल और पदोन्नतियों में आरक्षण की वकालत करने वाले बताएं कि क्यों ऐसी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए. आरक्षण का जिन्न लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में विचरण कर रहा है. विरोध और समर्थन में जगह–जगह सम्मेलन हो रहे हैं. ग़ौरतलब हो, मायावती ने अपने शासनकाल में अनुसूचित जाति को प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. तत्कालीन मायावती सरकार ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने महत्वपूर्ण फ़ैसले में उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती बसपा सरकार के पदोन्नतियों में आरक्षण के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दे दिया.

बसपा के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दलित नेता आरके चौधरी के नेतृत्व में लखनऊ में प्रदर्शन हुआ तो अन्य दलित संगठन भी लामबंद होने लगे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इसी संसद सत्र में प्रोन्नति में आरक्षण को अमलीजामा पहनाया जाए. संविधान में संशोधन करके आरक्षण को नौवीं सूची में डलवाया जाए, जिससे सही मायने में दलित कर्मचारियों को संविधान की 77वें और 85वें संशोधन का लाभ मिल सके. आरक्षण का मुद्दा उठने से बसपा को लड़ने के लिए नई ज़मीन मिल गई है, तो उनके विरोधी इसी मुद्दे के सहारे उनको पटख़नी देने की कोशिश में हैं. कहा जा रहा है कि दलितों की इस लामबंदी का फ़ौरी फ़ायदा मायावती को भले मिल जाए, पर इसका ठीकरा भी उन्हीं के सिर फूटना तय है. बसपा विरोधियों का मानना है कि सप्रीम कोर्ट में नागराज मामले में मायावती सरकार की तरफ़ से क़ानूनी रूप से जो ज़रूरी क़दम उठाए जाने थे, उनकी अनदेखी करते हुए सस्ती लोकप्रियता के लिए जो फ़ैसला लिया गया, वही उनके ख़िलाफ़ भी जा रहा है. जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज जो हो रहा है, उसके लिए कोई और नहीं सिर्फ़ मायावती ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने नागराज मामले में प्रोन्नति में पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए फ़ैसले की त्रुटियों को सुलझाए बिना आरक्षण लागू करा दिया. इसलिए इस मामले में नुक़सान भी मायावती को ही उठाना पड़ेगा. आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक केबी राम का कहना है कि शाहबानो मामले में यदि संविधान में संशोधन हो सकता है तो हज़ारों दलितों को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए यह क्यों नहीं हो सकता. राम का कहना है कि अब पूरी कार्ययोजना संविधान संशोधन पर केंद्रित है. इसके लिए सांसदों और विधायकों से संपर्क किया जा रहा है. विधि विशेषज्ञ नीलाक्षी सिंह ने कहा हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के नागराज मामले में फ़ैसले के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका और अन्य लोगों की तरफ़ से दायर सिविल अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 को दिए गए अपने फ़ैसले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के उक्त फ़ैसले को बरक़रार रखा है. ध्यान रहे, जब तक नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से निर्धारित नियम पूरे नहीं किए जाते, तब तक पदोन्नति में आरक्षण स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ है. अगर अदालत के फ़ैसले का अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार को करना है, तो प्रोन्नति में आरक्षण देने या न देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट केएम नागराज मामले में फ़ैसले में दिए गये निर्देशों को पूरा तो करना ही होगा.

बहरहाल, पदोन्नति में आरक्षण बसपा सरकार के शासनकाल में भी सरकार पर निर्भर था और अब सपा सरकार में भी सरकार पर ही निर्भर है. सपा सरकार इस मामले पर मायावती सरकार के निर्देशों को सार्वजनिक करती है तो बसपा इस मामले में कोई राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रह जाएगी. फ़िलहाल इस पूरे खेल में सपा सरकार खलनायक और बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों की नायिका नज़र आ रही हैं.

इस मामले में मायावती का सर्वजन अब पूरी ताक़त से अखिलेश यादव के साथ खड़ा है. वह अखिलेश यादव की ताक़त भी बढ़ा रहा है. किसान मंच के अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि मामला 18 लाख सरकारी कर्मचारियों का है, जिससे क़रीब दो करोड़ लोग प्रभावित होंगे. इसलिए इसे मामूली मुद्दा नहीं मान सकते, लेकिन यह साफ़ है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सर्वजन को बहुजन से तोड़ दिया है. प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रही बहुजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि प्रोन्नति में आरक्षण के सवाल पर सभी राजनीतिक दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए तो आरक्षण का समर्थन करने वाले संगठनों को इस मामले में एक ब्लू प्रिंट जारी करके बताना चाहिए कि आख़िर क्यों और कब तक पदोन्नति में आरक्षण मिलते रहना चाहिए. पिछले दिनों पदोन्नति में आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों ने कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग की. प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध कर रही बहुजन हिताय संरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद, केंद्रीय कार्मिक मंत्री पी नारायण सामी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाक़ात करके अपना पक्ष रखा. ■

मामला क्या है ?

2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब बसपा सुप्रीमो मायावती क़ाबिज़ हुईं तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस (रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी और ओबीसी) अधिनियम में उप धारा 8 ए जोड़ते हुए एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ वरिष्ठता (परिणामी वरिष्ठता) देने का प्रावधान कर दिया. इस संधोधन के ख़िलाफ़ सामान्य वर्ग के कुछ कर्मचारी संगठनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का दरवाज़ा खटखटाया. इस पर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी, 2011 को महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाते हुए माया सरकार के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार देते हुए संशोधन को ख़ारिज कर दिया. तिलमिलाई माया सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुच गई. पर यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की पीठ ने 27 अप्रैल को दिए अपने अहम फ़ैसले में प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक क़रार देते हुए उच्च न्यायालय के जनवरी 11 के आदेश को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ का कहना था कि यह क़ानून सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज मामले में दिए गए फ़ैसले के अनुरूप नहीं है. एम नागराज फ़ैसले में आरक्षण देने से पहले उसका लाभ पाने वाले की स्थिति का अध्ययन करने की बात कही गई थी. फ़ैसला आने के बाद सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के वकील कुमार परिमल ने फ़ैसले का स्वागत किया, वहीं एससी एसटी कर्मचारियों के वकील मनोज गोरकेला ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दाख़िल करने की बात कही. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि जो लोग संशोधित नियम का फ़ायदा उठा कर प्रोन्नति लाभ पा चुके हैं. उन्हें परेशान नहीं किया जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले एक साल से राज्य की सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति पर लगी रोक भी ख़त्म कर दी है, जिसके बाद कर्मचारियों की प्रोन्नति का रास्ता खुल गया है.

आवश्यकता है

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया को उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों एवं ज़िलों में आवश्यकता है संवाददाताओं, विज्ञापन प्रतिनिधियों एवं प्रसार व्यवस्थापकों की. अनुभवी एवं कार्यरत लोगों को वरीयता दी जाएगी. सम्मानजनक वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय. इच्छुक लोग पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं:–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11
नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष –0120–6451999, 6452888, 6450888

Email –advt.uttarpradesh@gmail.com

चौथी दुनिया

प्रदेश में एम्स स्थापित कराने के लिए यूपी के माननीयों में ललक बढ़ गयी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि प्रदेश में एम्स लाने के लिए उनकी पार्टी से जो भी बन पड़ेगा, वह करेंगी.

बिजली से बेहाल उत्तर प्रदेश

अजय कुमार feedback@chauthiduniya.com

गर्मी के दस्तक देते ही उत्तर प्रदेश बिजली और पेयजल संकट से करहाने लगा है. प्रदेश के दूरदराज़ के ज़िलों में ही नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी बिजली–पानी की समस्या के कारण हाहाकार मचा हुआ है. जनता त्राहिमाम कर रही है, तो सरकार और उसके ज़िम्मेदार अधिकारी ख्याली पुलाव पकाकर जनता को गुमराह करने में लगे हैं. कभी लाइन लॉस पर रोक लगाने के नाम पर, तो कभी प्राइवेट सेक्टर को बिजली व्यवस्था सौंपे जाने के झुंझुनों के सहारे जनता को बरगलाया जा रहा है. दूसरी तरफ़ बिजली विभाग का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है. बिजली चोरी रोकने के दावे किए तो जाते हैं, लेकिन चोरी रोकने के नाम पर बड़े उपभोक्ताओं पर हाथ डालने की बजाय छोटे उपभोक्ताओं को ही तंग किया जा रहा है. बिना किसी रणनीति के हवा में हाथ–पैर मार रहे पावर कॉरपोरेशन को बिजली व्यवस्था कैसे सुधारनी है, इसके बारे में ज़मीनी हक़ीक़त का ज़रा भी आभास नहीं है. सरकार और विभाग का बिजली उत्पादन बढ़ाने से अधिक ज़ोर इस बात पर है कि कैसे उपलब्ध बिजली के सहारे सबको संतुष्ट कर दिया जाए. राज्य में वर्षों से कोई नया बिजली प्लांट नहीं लगा है. हालात नहीं बदले तो आने वाले दिनों में प्रदेश को बिजली के गंभीर संकट से जूझना पड़ सकता है.

प्रदेश में बिजली व्यवस्था की स्थिति वर्षों से दयनीय है. उत्पादन और मांग का अंतर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसकी कमी हमेशा बनी रहती है, जबकि साल–दर–साल प्रदेश में बिजली की ज़रूरत बेतहाशा बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे खपत में वृद्धि हो रही है. शहरों की आबादी बढ़ने की वजह से भी बिजली की मांग में इज़ाफ़ा हो रहा है. प्रदेश में जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण दोषपूर्ण है. प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जो बिजली कटौती से बचा हुआ हो, कहीं घोषित तो कहीं अघोषित बिजली कटौती हो रही है. लखनऊ तक बिजली संकट से त्रस्त है. सरकारी नियंत्रण में होने से ऊर्जा क्षेत्र की दयनीय दशा पर हमेशा उंगली उठती रही है. इस क्षेत्र में समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि किसी न किसी मोर्चे पर सरकार की विफलता सामने आ ही जाती है. प्रदेश की नई सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के क्रम में शुरुआती दौर में 6–7 ज़िलों की ही बिजली व्यवस्था प्राइवेट हाथों में देने का मन बना रही है. इसमें लखनऊ भी शामिल है. अगर नतीजे उत्साहजनक आए तो इसे और ज़िलों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है.

बिजली वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं की एक बड़ी आबादी चोरी सें बिजली का उपयोग कर रही है, लेकिन इसका ख़ामियाज़ा बिजली उपयोग करने वाले उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो ईमानदारी से बिजली ख़र्च करके उसके बिल का भुगतान करते हैं. बिजली के बिना शहरी जीवन पंगु सा हो जाता है. इसकी ज़रूरत जानते हुए भी आम जनता उसका अपव्ययय नहीं रोक पाती.

हालांकि प्रदेश में बिजली वितरण को निजी क्षेत्र के हाथों देने पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है. पावर कॉरपोरेशन कर्मियों को लगता है कि बिजली निजी हाथों में गई तो उनके अधिकारों का हनन होगा. इसलिए बिजली कर्मी धरना–प्रदर्शन पर उतर आए हैं. अभी जो हालात हैं, उसमें सरकार को एक दूरगामी योजना बनानी होगी, ताकि हालात सुधरें और आने वाले समय में बिजली की मांग और आपूर्ति में संतुलन बन सके. साथ ही प्रदेश में उद्योग–धंधों और खेतीबाड़ी के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए पर्याप्त बिजली मिलती रहे. उत्तर प्रदेश लंबे समय से बिजली की क़िल्लत झेल रहा है. कई वजहों में से एक इसकी बर्बादी भी है. जनता बिजली का भरपूर उपयोग करना तो जानती है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने में उसकी कोई रूचि नहीं है. 1990 के दशक में राजनीतिक फ़ायदे के लिए बिना किसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर राजनेताओं ने मुफ्त में बिजली क्यों बांटी? लोगों में आज भी मुफ्त में बिजली जलाने की आदत पड़ गई है. वे हवा–पानी की तरह बिजली का भी उपयोग करना चाहते हैं. इसी का परिणाम है कटिया डालकर, मीटर रोककर बिजली चोरी करना उनकी आदत में शुमार हो गया है. बिजली वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण बिजली उपभोक्ताओं की एक बड़ी आबादी चोरी से बिजली का उपयोग कर रही है, लेकिन इसका ख़ामियाज़ा बिजली उपयोग करने वाले उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो ईमानदारी से बिजली ख़र्च करके उसके बिल का भुगतान करते हैं. बिजली के बिना शहरी जीवन पंगु सा हो जाता है. इसकी ज़रूरत जानते हुए भी आम जनता उसका अपव्ययय नहीं रोक पाती. देश में मुंबई जैसे कुछ शहरों में निजी कंपनियां बिजली आपूर्ति का काम संभाल रही हैं. वहां निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है. यह ज़रूरी है कि निजी कंपनियों पर संदेह करने की बजाय हम उसके काम को देखें और परखें. विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति बिजली वितरण को निजी हाथ में देने के विरोध में आवाज़ उठा रही है. निजीकरण का हौव्वा खड़ा कर कर्मचारियों को भड़काना उचित नहीं है. सरकारी कर्मचारियों ने यदि मेहनत ईमानदारी और लगन से अपना काम किया होता तो प्रदेश में बिजली की यह दुर्दशा नहीं होती. आज भी शहरों में रोज़ आठ घंटे बिजली कटौती हो रही है. गांवों में बिजली आती रहे, तो लोगों के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं होता है.

उपभोक्ता बिजली की बर्बादी करते हैं तो बिजली कंपनियां अपने व्यय पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं. इससे भी बिजली की क़ीमत पर फ़र्क़ पड़ता है. बिजली के अपव्यय को रोकने के साथ बिजली कंपनियों को अपना फ़ालतू ख़र्च कम करना होगा. अनाप–शनाप ख़र्च से जो घाटा होता है, अंततः उसका ख़ामियाज़ा जनता को ही भुगतना पड़ता है. वितरण के अलावा बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार को ध्यान देना होगा. दादरी में 2004 में अनिल अंबानी समूह की जिस परियोजना की आधारशिला रखी गई वह कई विवादों से घिर गई. किसानों से ज़मीन अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सरकार को चाहिए कि वह दादरी प्लांट का मामला जल्द सुलझाए. बिना उत्पादन बढ़ाए यह संकट ख़त्म होने वाला नहीं है. ■

रायबरेली में एम्स को मुख्यमंत्री की हरी झंडी

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनने का सपना अब साकार होने जा रहा है. राज्य में नये मुख्यमंत्री के आने के बाद अब एम्स की बात बनती दिख रही है. यूपी में एम्स को लेकर संसद में कई बार नोक झोंक हुई. इस बात को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने रखा गया तो उन्होंने ज़मीन देने का वादा किया है. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के विकास के लिए उनसे जो बन पा रहा है, वह कर रहे हैं.

2008 में केंद्र सरकार ने रायबरेली में एम्स स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार से ज़मीन चाही थी, लेकिन पूर्ववर्ती मायावती सरकार ने रायबरेली की बजाय बुंदेलखंड में एम्स स्थापित करने की शर्त रख दी. इससे प्रदेश में एम्स स्थापित करने का मुद्दा अधर में फंस गया. प्रदेश में एम्स स्थापित कराने के लिए यूपी के माननीयों में ललक बढ़ गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि प्रदेश में एम्स लाने के लिए उनकी पार्टी से जो भी बन पड़ेगा, वह करेंगी. सपा ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया. सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने संसद को भरोसा दिलाया कि सपा प्रदेश सरकार से एम्स के निर्माण के लिए ज़मीन दिलवाएगी. इस पर भाजपाइयों ने भी हवा दे दी कि एम्स के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने को वह विधानमंडल सत्र में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह ने दो टूक कह दिया, एम्स की स्थापना में कोई शर्त नहीं रखी जाएगी, उसका निर्माण चाहे रायबरेली में हो या फिर अन्य किसी शहर में लेकिन होना चाहिए.जिन योजनाओं को केंद्र यूपी को भेजना चाहता था, उन योजनाओं को दूसरे राज्य के निज़ाम अपनी ओर खींच ले गए. दो की लड़ाई में किसी तीसरे को लाभ हुआ. यूपी पिछड़ गया, कई योजनाएं अधर में लटकी रहीं. उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर भी माया और मनमोहन की सरकारों में राजनीतिक द्वंद्व चलता रहा.

बहरहाल, अब रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए एक नहीं, बल्कि दो स्थानों पर भूमि उपलब्ध होने का दावा ज़िला प्रशासन ने किया है. दोनों स्थानों का चिन्हीकरण कर पूरा ब्यौरा शासन को भेजा गया है और उपयुक्त भूमि के बारे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का शासन से अनुरोध भी किया गया है. पिछले चार वर्षों से एम्स के लिए भूमि उपलब्ध न होने की बहानेबाज़ी करने वाला जिला प्रशासन सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब एक नहीं, बल्कि दो स्थानों पर पर्याप्त ज़मीन होने का दावा कर रहा है. सदर एवं लालगंज तहसीलों में एम्स की स्थापना के लिए पर्याप्त ज़मीन के संबंध में ज़िला प्रशासन ने शासन को पूरा ब्यौरा भी पेश किया है. बहरहाल, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए रायबरेली में एम्स की स्थापना होने की क़वायद एक शुभ संकेत लेकर आई है. राज्य सरकार ने एम्स के लिए 114 एकड़ ज़मीन देने के लिए बंदोबस्त कर लिया है. केंद्र सरकार ने एम्स के लिए 4 साल पहले जगह राज्य सरकार से मांगी थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार एम्स की स्थापना यूपी में जहां चाहे वहां करे, उसे ज़मीन मिलेगी. सवाल यह है कि जिस तरह अखिलेश यादव सरकार और केंद्र सरकार सहमति क़ायम करने में सफल रहे, वैसे ही केंद्र सरकार और मायावती सरकार क्यों नहीं हो सकी. यदि समय रहते इस निर्धारण माया सरकार में ही हो गया तो होता, तो अब तक एम्स का निर्माण हो चुका होता, जिससे प्रदेश के तमाम रोगियों को राहत मिलती, लेकिन यह विडंबना ही कही जाएगी कि वोट की राजनीति के आगे जनहित की बात नज़रअंदाज़ कर दी जाती है. ग़ौरतलब है कि इक्कीस करोड़ की आबादी वाले इस सूबे की हालत ख़स्ता है, वर्षों बाद यह पहला अवसर है, जब एम्स की स्थापना के लिए किसी राज्य सरकार ने इतनी जल्दी ज़मीन देने का वादा करके एक बड़े अस्पताल को अपने पाले में कर लिया है. इसे प्रदेश की जनता के लिए एक तोहफ़ा ही कहा जाएगा. लेकिन प्रदेश सरकार को इतना ख्याल रखना चाहिए कि अस्पताल चाहे जहां बने, वहां आम जनता सहजता से पहुंच सके. ■

पिछले चार वर्षों से एम्स के लिए भूमि उपलब्ध न होने की बहानेबाज़ी करने वाला ज़िला प्रशासन सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब एक नहीं, बल्कि दो स्थानों पर पर्याप्त ज़मीन होने का दावा कर रहा है. सदर व लालगंज तहसीलों में एम्स की स्थापना के लिए पर्याप्त ज़मीन के संबंध में ज़िला प्रशासन ने शासन को पूरा ब्यौरा भी पेश किया है . बहरहाल, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए रायबरेली में एम्स की स्थापना होने की क़वायद एक शुभ संकेत लेकर आई है.

आरटीआई के रास्ते मायावती की घेराबंदी

> बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो वैभवता के सभी रिकार्ड तोड़ डाले. अपने को दलित की बेटी कहने वाली मायावती के लिए दलित वोट नुचवा से अधिक कुछ नहीं हैं. वह उनके वोटों से राजनीति तो करती हैं लेकिन दलितों की समस्याएं सुनना तो दूर उनके लिए उनकी नजरों में अब सम्मान भी नहीं दिखता है.

अजय कुमार

feedback@chauthiduniya.com

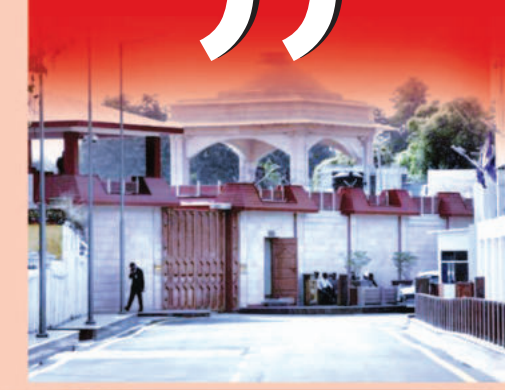

एक बंगला बने न्यारा....रहे कुनबा जिसमें सारा. मशहूर गायक केएल सहगल को 1937 में गाए गए इस गीत से ठीक वैसे ही ख्याति मिली थी, जैसी आजकल बसपा सुप्रीमो मायावती को अपने वैभवशाली बंगलों और विलासतापूर्ण रहन-सहन के कारण मिल रही है. माया के सत्ता से हटने के बाद उनसे जुड़े जो ख़ुलासे हो रहे हैं, वे अचंभित कर देने वाले हैं. उनके राजशाही ठाठ तो किसी से छिपे नहीं थे, लेकिन इसे किसी ने गंभीरता से इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि देश का यह दुर्भाग्य हैं कि अपवाद को छोड़कर अमूमन सभी नेतागण मायावती जैसे विलासतापूर्ण तरीक़े से जीवनयापन करते हैं. भारतीय राजनीति की यह विडंबना है कि अब यहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं होते हैं, जो ग़रीबों-मज़दूरों-किसानों के दुख-दर्द को बांटने का ढोंग करने की बजाय उसे समझते थे. आज माया और जयललिता जैसी नेत्रियों और शशि थरूर जैसे नेताओं की चर्चा होती है. किसी की पहचान बंगलों के लिए होती है, तो कोई अपनी साड़ियों और गहनों के कारण जानी जाती है. ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है, जिनकी नज़र में आम आदमी की ज़िंदगी भेड़- बकरियों जैसी लगती है. ऐशो-आराम के लिए सांसद-विधायक ही नहीं, बल्कि पंचायतों से जुड़े नेता भी नियम-क़ानून की ख़ूब धज्जियां उड़ाते हैं. अक्सर इसकी परतें खुलती रहती हैं.

जनता के पैसे से आराम की ज़िंदगी बिताने वाले हमारे नेताओं का ध्यान अपनी सुरक्षा और सुविधाओं की तरफ़ तो जाता है, लेकिन वे उस वर्ग को भूल जाते हैं जिसके कारण वे यह मुक़ाम हासिल करते हैं. जनता का हक़ सब तरफ़ से मारा जाता है. उसके हिस्से बेबसी ही आती है. चाहे सत्ता में कोई भी दल या नेता रहे, उसका सरोकार जनता की समस्याओं की तरफ़ कम अपनी ज़रूरतें पूरी करने पर ज़्यादा रहता है. नेताओं का यह स्वार्थी चरित्र कभी न रुकने वाला सिलसिला बन गया है. यही वजह है सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते ही नेताओं के दामन पर दाग़ लगने शुरू हो जाते हैं. पिछले 20-25 वर्षों में नैतिक गिरावट का सिलसिला और भी तेज़ हो गया. कोई आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा है, तो किसी पर दवाओं के घोटाले का आरोप है. अपराधियों को शरण देने और अनाप-शनाप काम करने में नेताओं को महारथ हासिल है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो वैभवता के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले. स्वयं को दलित की बेटी कहने वाली मायावती के लिए दलित वोट नुचवा से अधिक कुछ नहीं हैं. वह उनके वोटों से राजनीति तो करती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनना तो दूर दलितों के लिए उनकी नज़रों में अब सम्मान भी नहीं दिखता है. बसपा राज में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दीं. हर विभाग में प्रत्येक स्तर पर लूट का बोलबाला दिखा. सरकारी वसूली का धंधा एक महकमे की तरह चलाया गया. कमीशनख़ोरी चरम पर पहुंच गई. सरकार लोकसेवा की जगह एक बिजनैस मैन की तरह डीलिंग करने लगी. सरकारी संपत्ति को नेता किस तरह से अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं, इसका ताज़ा नमूना पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, जिन्होंने बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से केंद्र सरकार से चार बंगले आवंटित करा लिए. इतना ही नहीं, इन बंगलों में मनचाहा अवैध निर्माण भी हो गया. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को इस बात की जानकारी थी कि मायावती अपने सरकारी आवास में अवैध निर्माण करा रही हैं, लेकिन राजनीतिक ताक़त के आगे उसकी ताक़त बौनी साबित हुई और वह सब कुछ मूक-बधिर होकर देखता रहा.

इन दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माया का बंगला प्रेम चर्चा में है. इन बंगलों को न्यारा बनाने के लिए न केवल इसमें अवैध निर्माण किया गया, बल्कि इसको विस्तार देने के लिए अगल-बग़ल की कई इमारतों को ढहा दिया गया. लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें जो आवास (बंगला) संख्या 13 माल एवेन्यू आवंटित किया गया है, पहले यह स्पीकर हाउस के नाम से जाना जाता था. 13 माल एवेन्यू के रिकॉर्ड बताते हैं कि स्पीकर हाउस में लंबे समय तक कांग्रेस के स्वर्गीय नेता बलदेव सिंह आर्य का क़ब्ज़ा रहा, जो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा में मंत्री रहे थे. मायावती को यह बंगला 1995 में आवंटित किया गया था, जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बनीं. तब यह ढाई एकड़ में फैला था, 2007 में जब वह चौथी बार सत्ता पर क़ाबिज़ हुई तो उन्होंने इसे विस्तार देने का मन बनाया और इसमें गन्ना आयुक्त का कार्यालय मिला लिया गया, जिससे इसका क्षेत्रफल दोगुना हो गया. बसपा सुप्रीमो को आवंटित इस बंगले के रखरखाव पर अभी तक 86 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा एक अरब तक भी हो सकता है. बंगले की ख़ूबसूरती को चार चांद लगाने और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए 20 फुट ऊंची चहारदीवारी राजस्थान के बेशक़ीमती पत्थर सैंड स्टोन से बनी है. बंगले के कॉरिडोर में एक-दो नहीं, दर्जनों लॉकर हैं. कॉरिडोर में दो बुलेट प्रूफ शीशे की खिड़कियां लगी हैं, प्रत्येक खिड़की की क़ीमत लगभग 15 लाख रुपये है. अतिथियों को कोई परेशानी न हो, इसलिए 14 बैडरूम वाला डबल स्टोरी गेस्ट हाउस भी परिसर में है. सभी कमरों की फ्लोरिंग पिंक इटैलियन मार्बल से की गई है. बंगले में स्थापित 20 फुट ऊंची मायावती और कांशीराम की मूर्तियां आने-जाने वालों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं. मायावती का बाथरूम दर्जनों बार तोड़ा और बनाया जा चुका है. क़रीब अस्सी फ़ीसदी निमार्ण और मरम्मत कार्य राज्य संपत्ति विभाग के ख़र्च से किया गया है. बीस फ़ीसदी ख़र्च निर्माण निगम, लखनऊ नगर निगम और गृह विभाग को भी उठाना पड़ा. यह सब ख़ुलासे आरटीआई से मिली जानकारी से हुए. यह आरटीआई कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने लगाई थी. बंगले की मरम्मत के दौरान कई बार बने बनाए निर्माणों को तोड़ गया. बात दिल्ली में फैले माया के साम्राज्य की करें तो दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित बंगला संख्या 4,12,14 और 16 उनके नाम पर आवंटित हैं. इनमें से तीन बंगले बसपा अध्यक्ष तथा एक बंगला बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट के नाम पर है. यह जानकारी भी एक आरटीआई से ही हासिल हुई है. आरटीआई के जवाब में सीपीडब्ल्यूडी ने बताया है कि मायावती के नाम आवंटित बंगला संख्या 4 में चहारदीवारी तोड़कर अवैध निर्माण कराया गया है. मुख्य द्वार के पिछले हिस्से को तोड़कर तीन-चार कमरों का निमार्ण किया गया है. बंगले के लॉन की दीवार तोड़कर पिछले हिस्से में पार्क बनाए गए हैं. अवैध निर्माण के कारण बंगले में क़रीब 150 वर्गमीटर का क्षेत्र बढ़ गया. इसी तरह से अन्य बंगलों में भी अनाप-शनाप निर्माण कराया गया है.

बहरहाल, मायावती के बारे में आरटीआई से जो जानकारी आई है, वे चौंकाने वाली जरूर हैं, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सका है कि अगर विभिन्न दलों के अन्य कुछ नेताओं के कारनामों की भी जांच की जाए तो उनके कारनामे भी इससे कम नहीं होंगे. कई नेता तो भ्रष्टाचार के कारण जेल की हवा तक खा रहे हैं. मायावती और मुलायम दोनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं. फिर भी मायावती के विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौक़ा तो मिल ही गया. समाजवादी पार्टी मायावती को घेरकर उनकी दलित बेटी की इमेज तो तोड़ना चाहती है. इसके अलावा वह मायावती को क़ानूनी दायरे में भी लाना चाहती है. बस, ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि मायावती के ख़िलाफ़ कोई भी कार्यवाही बदले की भावना से प्रेरित नहीं दिखे. सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह ज़रूर कहा था कि बदले की भावना से प्रदेश में काम नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को खुला छोड़ दिया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री और उनके शागिर्दों ने सत्ता में रहते जो लूट मचाई थी, उसका हिसाब ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनसे वसूली भी की जाएगी. ■

मिड डे मील

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

चावल की कालाबाज़ारी

राकेश यादव

feedback@chauthiduniya.com

फ़ैज़ाबाद जनपद के गोसाईगंज स्थित एमबी राइस मिल से मिड डे मील के राशन की कालाबाज़ारी किए जाने का मामला उजागर हुआ है. प्रकरण के सामने आते ही विभाग के काले कारनामे उजागर होने लगे हैं. इस प्रकरण में विभागीय अधिकारी अपने ही जाल में फंसते नज़र आ रहे हैं. बीकापुर विधानसभा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह (बबलू) के परिजनों की जिस आईआर एसोसिएट्स फर्म एवं राइस मिल द्वारा अनाज की कालाबाज़ारी होने की बात उजागर हुई है, उस फर्म के संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण के दौरान अधिकारियों ने नियम-क़ायदों की अनदेखी कर काम किया. पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, लेकिन फर्म के पार्टनरों की तस्दीक के लिए सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझी. इतना ही नहीं वर्ष 2007 से संचालित फर्म के ज़रिए अनाज की कालाबाज़ारी का गोरखधंधा चलता रहा, वहीं विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक न लगना, कई सवाल खड़े करता है. हालांकि प्रकरण के उजागर होने के बाद अब अधिकारी जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, परंतु पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है.

ग़ौरतलब है कि 26 अप्रैल, 2012 को जिलाधिकारी जेपी गुप्ता के निर्देश पर एडीएम प्रशासन राजेश कुमार ने वीरशाहपुर-अमसिन मार्ग पर कालाबाज़ारी के लिए जा रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिस पर मिड डे मील का 395 बोरी चावल पाया गया. उसी समय टीम ने मिल का ताला बंद होने के कारण एमबी इंडस्ट्रीज को सील कर दिया और खाद्यान्न समेत चालक एवं क्लीनर को पुलिस के हवाले कर दिया. दूसरे दिन 27 अप्रैल को भी जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर सुरेंद्र सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी दयाशंकर, जिला आपूर्ति अधिकारी केपी मिश्र, एसएमआई पीके झा, उमाकांत गोस्वामी एवं भानु भास्कर कौल आदि की टीम ने मिल का ताला तोड़कर सघन जांच-पड़ताल की. इस दौरान जांच टीम द्वारा चावल, खंडा एवं गेहूं के 33 नमूने सील किए गए. टीम की ओर से एमबी इंडस्ट्रीज की मालकिन संध्या सिंह, आईआर एसोसिएट्स के पार्टनरों, ट्रक मालिक राकेश सिंह, ट्रक चालक रामअंजोर शर्मा एवं क्लीनर बृजेश के ख़िलाफ़ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत करने के लिए गोसाईगंज थाने मे तहरीर दी गई. इस पर गोसांईगंज थाने की पुलिस द्वारा फर्म सदस्यों, मिल मालिक एवं ट्रक ड्राइवर समेत 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई. वरिष्ठ विपणन अधिकारी उमाकांत की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामज़द अभियुक्तों में ज़िला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बलराम मौर्य एवं उनके भाई कन्हैया मौर्य, पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के पिता इच्छाराम सिंह, चचेरे भाई राकेश कुमार सिंह एवं राकेश की पत्नी संध्या सिंह, बसपा नेता रमेश सिंह के भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह, करुणेंद्र प्रताप सिंह, रामजी, ज्ञान चंद जायसवाल, राम अंजोर शर्मा एवं बृजेश कुमार शामिल हैं. मामले में नामज़द अभयुक्तों के नाम सामने आते ही कई सदस्यों ने उक्त फर्म व मील से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर राजनीतिक साज़िश की बात कहकर अपना नाम उछाले जाने की बात कही. यहां तक ज़िला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बलराम मौर्य ने रमेश सिंह के साथ एक प्रेस वार्ता बुलाकर पत्रकारों से कहा कि वे आईआर एसोसिएट्स या राइस मिल के कभी साझेदार नहीं थे. फ़र्ज़ी काग़ज़ के आधार पर उन्हें बसपा में होने के कारण फंसाया गया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी जेपी गुप्ता से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई से अवगत करा दिया है. उनका कहना था कि बबलू सिंह ने वर्ष 2008 में उनका अपहरण कराया था, जिसमें उनके भाई प्रमोद सिंह कई माह तक जेल में बंद रहे. बसपा नेता रमेश सिंह ने भी अपने भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह को राजनीतिक साज़िश से फंसाए जाने का आरोप लगाया है.

> वर्ष 2007 से संचालित फर्म के ज़रिए अनाज की कालाबाज़ारी का गोरखधंधा चलता रहा, वहीं विभागीय अधिकारियों को इसकी भनक तक न लगना कई सवाल खड़े करता है. हालांकि प्रकरण के उजागर होने के बाद अब अधिकारी जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, परंतु पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है. ग़ौरतलब है कि 26 अप्रैल, 2012 को जिलाधिकारी जेपी गुप्ता के निर्देश पर एडीएम प्रशासन राजेश कुमार ने वीरशाहपुर-अमसिन मार्ग पर कालाबाज़ारी के लिए जा रहे एक ट्रक को पकड़ा.

बताते चलें कि उक्त प्रकरण में सामने आई फर्म का वर्ष 2007 में जब आरएफसी कार्यालय से रजिस्ट्रेशन हुआ और कई लोगों को पार्टनर बनाया गया, तो बिना सत्यापन के सारा काम कर दिया गया. दो साल तक फर्म कार्य करती रही. उसके बाद वर्ष 2009 में फर्म के कुछ सदस्यों को निष्कासित किया गया इस दौरान भी आरएफसी कार्यालय ने सत्यापन नहीं कराया. यही नहीं 7 अप्रैल, 2011 को हुए नवीनीकरण के दौरान भी सत्यापन के लिए फर्म के पार्टनरों की तस्दीक भी नहीं की गई और बिना सत्यापन के फर्म कार्य करती रही, वहीं विभागीय अधिकारियों ने जांच करने की ज़रूरत नहीं समझी, जबकि नियमानुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड फर्म का तीन वर्ष बाद नवीनीकरण होना रहता है. इसमें फर्म के पार्टनरों एवं फर्म के कामकाज की पड़ताल और सत्यापन किया जाता है. अब जब प्रदेश से लेकर ज़िले तक सियासत बदल चुकी है. ऐसे में जिलाधिकारी के आदेश पर हुई छापेमारी ने पूरे प्रकरण से पर्दा उठा दिया है और पूरे मामले में आरएफसी कार्यालय के लिपिक समेत तत्कालीन अधिकारियों और एक विपणन निरीक्षक पर उंगली उठ रही है. ■

एनआरएचएम की विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले हज़ारों करोड़ रुपये के बजट में बंदरबांट का असली खेल 2009-2010 से शुरू हुआ, लेकिन सीबीआई 2005 तक की समयावधि में हुए कार्यों की पड़ताल कर रही है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

एनएचआरएम

घोटाले में नया मोड़

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएमओ डॉ. एके शुक्ला को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में एक बंद कमरे में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डॉ. शुक्ला को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. डॉ. शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ तब उभरा, जब जेल में तलाशी के दौरान उनके मोजे से सल्फास की पुड़िया बरामद हुई.

मालूम हो कि 27 अक्टूबर, 2010 को डॉ. विनोद आर्या की हत्या विकास नगर में कर दी गई थी, जब वह मॉर्निंग वॉक पर थे. इसी तरह 2 अप्रैल, 2011 को सीएमओ डॉ. बीपी सिंह की गोमती नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 5 अप्रैल, 2011 को इसी मामले में तत्कालीन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत मिश्र ने इस्तीफ़ा दे दिया. इसके बाद 7 अप्रैल, 2011 को स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉ. एके शुक्ला के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर हुआ. उन्हें पद से हटा दिया गया. 8 अप्रैल, 2011 तीन ठेकेदार और एक कर्मचारी की पुलिस ने गिरफ्तारी की, वहीं एक अन्य सीएमओ से भी पूछताछ हुई. 17 जून, 2011 को बस्ती के तीन शूटर गिरफ्तार हुए, जिसमें दोनों सीएमओ की हत्या के लिए डॉ. सचान पर शक ज़ाहिर हुआ. इसी आधार पर डॉक्टर सचान को नामज़द कर जेल भेज दिया गया. 20 जून, 2011 को डॉ. सचान हत्या की साज़िश के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहे. 21 जून, 2011 को विवेचक ने डॉ. सचान के बयान जेल में लिए, लेकिन लोगों को हैरत तब हुई, जब जेल में डॉ. सचान का शव लटकता पाया गया.

सीबीआई की 10 महीने की गहन तफ्तीश के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. सीएमओ पद से हटाए जाने के लिए डॉ. शुक्ला ने डॉ. आर्या की हत्या की साज़िश रची.सीबीआई का तर्क है कि इसके बाद उनके एनआरएचएम में भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुलती, जिसे दबाने के लिए ए के शुक्ला ने डॉ आर्या की हत्या करवाई. हत्या से पहले उन्होंने 12 अक्टूबर 2010 को तत्कालीन डिप्टी सीएमओ डॉ वाई एस सचान से बात की थी. इसके बाद सचान ने ठेकेदार आरके वर्मा को फोन किया. वर्मा ने फिर शूटर आनंद तिवारी और विनोद शर्मा से संपर्क किया. सीबीआई का दावा है कि एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए शूटर आनंद प्रकाश तिवारी और विनोद शर्मा ने भी साज़िश में डॉ. एके शुक्ला के नाम की गवाही दी है. इसके बाद डॉ. एके शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि डॉ. विनोद आर्या की हत्या की जांच अब पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्र (अंटू) की ओर तफ्तीश की सुई बढ़ रही है. सीबीआई को संदेह है कि हत्याकांड के पीछे पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा की भूमिका हो सकती है. संभवत: इसमें अनंत कुमार मिश्र की भी मिलीभगत रही हो. सीबीआई का दावा है कि परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा का विभाग अलग-अलग होने और बाबू सिंह कुशवाहा को परिवार कल्याण का काम मिलने से अनंत मिश्र के हित प्रभावित हुए थे. महकमे में एक ख़ास वर्ग ऐसा था, जो ऐसा किसी भी क़ीमत पर नहीं होने देना चाहता था. अंटू की भूमिका की पड़ताल के लिए ही सीबीआई ने डॉ. एके शुक्ला को रिमांड पर लेना चाहती है, क्योंकि पूछताछ में डॉ. एके शुक्ला ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप शुक्ला का नाम लिया है. सीबीआई के मुताबिक़, डॉ. एके शुक्ला सीएमओ परिवार कल्याण का पद सृजित होने के बाद से परेशान थे. वह अपने साथी डिप्टी सीएओ डॉ. वाईएस सचान के साथ मिलकर लखनऊ में एनआरएचएम का पूरा काम संभालते थे. स्वास्थ्य के विभिन्न मदों में आने वाले फंड की वजह से सीएमओ परिवार का पद महत्वपूर्ण था. सीएमओ परिवार कल्याण के पद पर डॉ. विनोद आर्या की तैनाती डॉ. वाईएस सचान और डॉ. एके शुक्ला के लिए परेशानी बन गई थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर एनआरएचएम की योजनाओं में गड़बड़ी कर रखी थी. ईमानदार छवि के सीएमओ डॉ. विनोद आर्या के इस विशेष कुर्सी पर आ जाने से गड़बड़ियों की पोल खुल सकती थी, लिहाज़ा इससे बचने के लिए डॉ. विनोद आर्या को रास्ते से हटाना ही दोनों ने उचित समझा. इस पर आरके वर्मा, आनंद प्रकाश तिवारी और विनोद शर्मा ने डॉ. विनोद आर्या को मौत की नींद सुला दिया. अब सीबीआई डॉ. विनोद आर्या हत्याकांड की तफ्तीश के साथ साथ डॉ. वाईएस सचान द्वारा जेल में लिखे गए पत्र के रहस्य को खंगाल रही है. सीबीआई को संदेह है कि सचान ने मौत से पहले पुलिस कर्मियों को ख़त दिया था. वह डॉ. एके शुक्ला के लिए था, लेकिन यह उन तक पहुंचा या नहीं यह बात साफ़ नहीं हो सकी. ख़त में डॉ. सचान ने डॉ. एके शुक्ला पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसमें सच्चाई उगलने की बात कही गई थी. सीबीआई अब क्षीर नीर करना चाहती है कि आख़िर ख़त किसने छिपाने की कोशिश की. सीबीआई अब पूर्व डीजीपी, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछताछ करना चाहती है.

सीबीआई डॉ. सचान की मौत की गुत्थी सुलझाने में उलझी है, क्योंकि लखनऊ में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रिपोर्ट को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ ही गुजरात की फॉरेंसिक जांच एजेंसी ने भी ख़ारिज कर दिया है. चोटों को ख़ुद द्वारा पहुंचाई गई बताया गया है और गले पर नौवीं चोट के रूप में चिन्हित खरोंच को पेरीमार्टम यानी दम निकलने के दौरान लगी रगड़ क़रार दिया गया है, लेकिन इसे सीबीआई पुख्ता तौर पर पेश नहीं कर पा रही है. क़त्ल के भी कोई सुबूत नहीं मिले हैं. कुछ बड़ों पर उंगली ज़रूर उठ रही है. सीबीआई के अधिकारी आत्महत्या को लेकर यह भी तर्क देते हैं कि जिस स्थान पर शव मिला, वहां इतना ख़ून था, जिससे साफ़ है कि डॉ. सचान की मौत वहीं हुई. सीबीआई को जांच करते हुए दस महीने बीत चुके हैं. जांच जुलाई 2010 में शुरू की गई थी. सीबीआई की पूछताछ जारी है. इस पर सभी की निगाहें लगी हैं.

दूसरी तरफ़ सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया है, सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें अमौसी हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया, उस वक़्त वह दिल्ली से लखनऊ लौट रहे थे. उसके बाद उन्हें सीधे सीबीआई कार्यालय लाया गया, जहां सुबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. प्रदीप शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने एनआरएचम घोटाले को रोकने की बजाय नेताओं के इशारे पर उनकी मनचाही कंपनियों को काम बांटे और करोड़ों रुपये की बंदरबांट की. इसी कारण प्रदीप शुक्ला का नाम चार एफआईआर में दर्ज है. वह ख़ुद को बचाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन साढ़े आठ हज़ार करोड़ रुपये के इस घोटाले में उनकी गर्दन बच न सकी. प्रदीप शुक्ल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के पद पर थे, साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का काम भी देखते थे.

सीबीआई ने एनआरएचएम घोटाले में लिप्त माननीयों और ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ दी है. 1981 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप शुक्ला को सीबीआई अधिकारियों ने कई बार पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया, लेकिन कुछ दिनों से वह सीबीआई अधिकारियों से मिलने से कतराने लगे थे. कभी व्यस्तता तो कभी स्वास्थ्य ख़राब होने की बात कहकर वह सीबीआई को सहयोग देने में आनाकानी करने लगे. इस दौरान पूर्व सीएमओ डॉ. एके शुक्ला को सीबीआई ने गिरफ्तार कर उन्हें दो दिन के रिमांड पर लिया.

एनआरएचएम की विभिन्न योजनाओं के लिए आने वाले हज़ारों करोड़ रुपये के बजट में बंदरबांट का असली खेल 2009-2010 से शुरू हुआ, लेकिन सीबीआई 2005 तक की समयावधि में हुए कार्यों की पड़ताल कर रही है. एनआरएचएम की विभिन्न योजनाओं में होने वाली ख़रीद-फ़रोख्त में पहले ज़िलों में सक्रिय ज़िला स्वास्थ्य समितियां करती थीं. ये समितियां जिलाधिकारी के अधीन होती हैं और उनकी अनुमति के बिना कोई ख़रीद नहीं की जा सकती है, लेकिन ज़िलों में इन समितियों द्वारा अपेक्षा से कम ख़रीद की जाती थी. इसी वजह से कई ज़िलों में समितियां कमोबेश निष्क्रय सी हो गई थीं. कई वर्षों तक बजट की रक़म भी खर्च नहीं की जा सकी. सीबीआई की लिस्ट में कई पूर्व जिलाधिकारी भी हैं. चूंकि एनआरएचएम ज़िलों में इसी सोसायटी के तहत संचालित होता है. डीएम सोसायटी का अध्यक्ष और सीएमओ सचिव होते थे. इसी बीच प्रदेश कैबिनेट ने सोसायटी की नियमावली में संशोधन कर सीएमओ की जगह ज़िला परियोजना अधिकारी को इसका सचिव बना दिया. इस बदलाव को नियमत: सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत कराया जाना चाहिए था. पंजीकरण न होने से यह सोसायटी स्वत: अनधिकृत हो गई. सीबीआई का मानना है कि इसके बाद खाते से रक़म की निकासी भी अवैध है. तत्कालीन प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) प्रभात कुमार सारंगी ने 26 अगस्त, 2010 को कैबिनेट फ़ैसले को लागू करने के लिए सभी डीएम को निर्देश भी भेजे, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया. 70 ज़िलों के तत्कालीन जिलाधिकारियों ने साल भर बिना संशोधन एवं बिना पंजीकरण के ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी के खाते से रक़म निकालकर ख़र्च की. अभी तक उन जिलाधिकारियों से सीबीआई पूछताछ नहीं कर सकी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि एक एक कर सभी से पूछताछ की जाएगी. 60 कर्मचारियों को छोड़कर सभी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं, जिससे योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ है. ■

सल्फास के पीछे का रहस्य

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएमओ डॉ. एके शुक्ला के पास आख़िर सल्फास कैसे पहुंची, इस सवाल ने सीबीआई को हैरत में डाल दिया है. इससे जेल महकमा भी सकते में है. आख़िर यह चूक कैसे हुई? इस सवाल का जवाब देने को न तो सीबीआई के अफ़सर तैयार हैं और न जेल अधिकारी. जेल अधीक्षक के मुताबिक़, गोसाईगंज जेल में दो नंबर गेट पर जेलकर्मियों ने पूर्व सीएमओ की तलाशी ली. पहले तो डॉ. शुक्ला ने तलाशी देने से इनकार किया, मगर जबरन उनकी तलाशी कराई गई. इस दौरान उनके जूता उतारने से मना करने पर जेलकर्मियों को शक हुआ, तब जबरन तलाशी के दौरान उनके मोज़े से सफ़ेद पॉलिथीन में पैक दस ग्राम सल्फास पाउडर मिला. आख़िर डॉ. शुक्ला की साथ में सल्फास लाने के पीछे क्या वजह थी? इस पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. जेल अधीक्षक ने कपड़े उतरवा कर उन्हें डिप्टी जेलर एवं बंदीरक्षकों की निगरानी में कोरनटाइन बैरक भेज दिया, लेकिन सल्फास मिलने के बाद उन्हें महिला कक्ष में स्थानांतरित कर दिया. जेल अधीक्षक दधीराम मौर्य के अनुसार, डॉ. शुक्ला को 24 घंटे सघन देखरेख में रखने की हिदायत दी गई है. वह आत्महत्या जैसा क़दम न उठा सकें, इसलिए उन्हें कड़े पहरे में रखा गया है. रिमांड में लेने के बाद सीबीआई डॉ. शुक्ला से कई सवालों के जवाब भी मांगेगी. बहरहाल, डॉ. शुक्ला के पास सल्फास निकलने के बाद इस ख़ूनी घोटाले ने नया मोड़ ले लिया है. आख़िर इस बड़े ख़ूनी घोटाले की जड़े कहां-कहां तक फैली हुई हैं. सीबीआई इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में है. सीबीआई की तफ्तीश जारी है. देखना है कि सीबीआई के पंजे में अगला मुजरिम कौन होगा?

क्या गंगा सिर्फ लाशें ढोएगी

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

गंगा अब आस्था नहीं बहस का विषय बनती जा रही है. बिजली परियोजनाओं के विरोध के बाद फिर से पावन गंगा नदी पर बहस केन्द्रित हो गयी है. इस बहस में न केवल गंगा के जल का व्यापक उपयोग करने की जरूरत महसूस की जा रही है बल्कि हरिद्वार से पहले ही गंगा और यमुना का संगम कराने के सुझाव भी आ रहे हैं. साहित्यकार व पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी तो बिजली परियोजनाओं को रोकने से इतने व्यथित हैं कि उन्होंने संतों पर आरोप लगाया है कि वे गंगा को सिर्फ लाशें ढोने तक सीमित रखना चाहते हैं.

जगूड़ी का कहना है कि गंगा में हरिद्वार से 42 नहरें निकली हैं. मैदानी इलाकों में यह समृद्धि बढ़ाने के काम आ रही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ लाशें ढो रही है. यह बात जगूड़ी ने तब कही जब भगवान शिव की नगरी काशी में प्रख्यात पर्यावरणविद प्रो.जी.डी.अग्रवाल उर्फ संत सानन्द अनशन कर रहे हैं, और उनके आन्दोलन को भारी जन समर्थन मिल रहा है. जगूड़ी का कहना है कि पौराणिक कथाओं के आधार पर भले ही गंगा जी पुरखों को तारने के लिए अवतरित हुई हों, लेकिन अब वक्त की जरूरत यह है कि इसे जीवंत बनाते हुए लोक कल्याणकारी उपयोग बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि गंगा के लोक महत्व को और बढ़ाने के लिए प्रदेश के भीतर ही गंगा और यमुना का संगम बनाया जाना चाहिए. दोनों नदियों को नहरों के जरिये सौंग नदी में मिलाया जा सकता है. इससे प्रयाग की तरह एक और तीर्थ स्थान का विकास होगा और हरिद्वार का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाएगा. किवदंती है कि महाराजा सगर के साठ हजार पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा धरती पर उतरी थीं. अपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए तप के बल पर गंगा को धरती पर उतारने वाले महाराजा भागीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम देवप्रयाग से पहले भागीरथी है. तब से लेकर आज तक गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है. जगूड़ी ने कहा कि संत गण संसार के भले के लिए कुछ करें.

यह तभी संभव है जब गंगा जैसी लंबी नदी के जल का समुचित उपयोग होगा. सूबे की सरकार और उसके मुखिया विजय बहुगुणा भी गंगा जल का विकास के लिए प्रयोग किये जाने के प्रबल पक्षधर है. जगूड़ी का कहना है कि गंगा की चिंता करने वाले अगर सही मायने में गंगा का भला चाहते हैं तो उन्हें उन सहायक नदियों व गाड़-गधेरों की चिंता करनी चाहिए जिनकी वजह से गंगा अस्तित्व में आयी.

पहाड़ में जंगल कटने से हालत यह हो गयी है कि कई सहायक नदियां व गाड़-गधेरे सूखने लगे हैं, संतों के हठी रवैये से नाराज जगूड़ी ने भारत सरकार द्वारा संतों के सामने घुटने टेकने की स्थिति में सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री पुरस्कार वापस करने की धमकी दी है. काशी में पुलिस द्वारा संत सानन्द को जबरन उठाने की घटना पर धर्मनगरी हरिद्वार में करारी प्रतिक्रिया हो रही है. कुंभ नगरी प्रयाग में भी गंगा को बचाने के सानन्द के आन्दोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है. ■

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाईल : 09266627366